Discussion on the working of the Ministry of Human Resource Development

श्री कलराज मिश्र (**उत्तर प्रदेश**):सभापति जी, आप ने मुझे मानव संसाधन मंत्रालय की चर्चा पर बोलने की अनुमति दी,इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति जी, मानव संसाधन मंत्रालय स्वयं में इतना बृहत है कि अगर समुचित तौर पर इस मंत्रालय का मानव विकास की दृष्टि से उपयोग किया जाता तो आज हम सर्वोत्कृष्ट स्वरुप में लोगों के सामने अपने को प्रस्तुत कर सकते थे। मानव संसाधन के अंतर्गत मानव के चतुर्दिक विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता और उस के सदुपयोग पर ही विशेष रुप से जोर दिया जाता है। इस क्रम में जब हम देखते हैं तो प्रथमतः हमारे सामने यह बात उभरकर आती है कि जब तक शैक्षिक दृष्टि से मानव का उन्नयन नहीं होगा तब तक विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान न तो वह कर सकता है, न स्वयं ही विकसित हो सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समुचित तौर पर विकास हो, अज्ञान समाप्त हो, निरक्षरता समाप्त हो और ऐसी शिक्षा प्राप्त हो, जिसके आधार पर उत्पादन और दक्षता, दोनों में बढौतरी हो सके। इसके साथ ही साथ मौलिक चिंतन,शोध-कार्य और विभिन्न इस प्रकार की समझदारियों को अपने अंदर विकसित कर सके, जिसके आधार पर समाज के विकास की दृष्टि से वह आगे जा सके। इस आधार पर जब हम देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से इस दिशा में संपूर्णता की दृष्टि से विचार किया गया है।

मान्यवर, प्राथमिकता की दृष्टि से, यह बात सही है कि प्राथमिकताएं क्रमशः बहुत बाद में तय की गई हैं, प्रारंभ में जो सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं,वे नहीं की गईं, लेकिन प्राथमिकताएं बाद में सुनिश्चित किए जाने के पश्चात, जैसे वर्ष 1986 मे शिक्षा नीति पर विचार हुआ। उसके अंतर्गत जितने भी निरक्षर हैं उनको साक्षर कैसे बनाया जाए, इसको प्रभावी तौर पर कार्यान्वित कैसे कराया जाए, इस दिशा में विचार हुआ और फिर आगे चलकर भारत के अंदर जो भी निरक्षरता है उसको समाप्त करने की दिशा में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जाएं, इस दिशा में बड़े व्यापक तौर पर विचार हुआ। मैं यह कह सकता हूँ कि विचार के क्रम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आजादी के कई दशक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जिस तरीके से साक्षरता का स्वरुप पूरे देश के अंदर निर्माण होना चाहिए था यह निर्माण नहीं हो पाया। मैं तो केवल एक दशक पहले का बताना चाहूंगा कि वर्ष 1991 में 52.21 प्रतिशत की तुलना मे वर्ष 2001 मे 65.38 प्रतिशत की साक्षरता पर पहुंचे हैं, लेकिन वर्ष 2001 में 65.38 प्रतिशत साक्षरता का होना स्वयं इस बात को व्यक्त करता है कि जिस प्राथमिकता के आधार पर हमे पूरे देश भर में लोगों को साक्षर करना चाहिए था वे प्राथमिकताएं नहीं रखी गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी हम यह नहीं कह सकते कि पूरे देश में संपूर्ण साक्षरता सफल हुई है।

मान्यवर,इस अवधि में साक्षरता की दर में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो सर्वाधिक मानी जाए। महिलाओं में साक्षरता कम थी और इस अवधि में उनमें 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले वर्ष 1991 में जो साक्षरता दर 39.3 प्रतिशत की थी यह बढ़कर 54.16 प्रतिशत हुई, जबकि पुरुष साक्षरता की दर में 11.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले दशक में 64.1 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है। अभी शत-प्रतिशत नहीं है। इस दिशा मे हमने देखने का प्रयत्न किया है तो उससे लगा कि जो योजनाएं चालू की गई हैं,वर्तमान में

उन योजनाओ के अंदर यह भावना दर्शित होती है कि अल्पकाल में ही, पांच वर्ष,दस वर्ष जो भी हो, अल्पकाल में ही हम संपूर्ण साक्षरता अभियान को चरम-सीमा पर ले जाएं जिससे संपूर्ण साक्षरता की स्थिति निर्माण हो जाए और इसके लिए योजनाएं बनाई गई। मैं कहना चाहूंग़ा कि एक अभियान चलाया गया-सर्वे शिक्षा अभियान।सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि कोई भी पढ़ाई से वंचित न हो। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय संसद में एक संविधान संशोधन लाए थे, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का,पढ़ने का मौलिक अधिकार है, वे पढ़ाई करें और शिक्षा से कोई वंचित न रहे, ऎसी व्यवस्था की गई थी। उसके अंतर्गत यह भी कहा गया था,सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कि 2003 तक सभी बच्चो को स्कूल शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल,स्कूल वापसी शिविर में प्रवेश दिया जाए। यानी वह कहीं से वंचित न रहे सके। यह अभियान है कि सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा पर बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक स्त्री-पुरुष तथा सामाजिक वर्गों से संबंधित सभी अंतरों को पाटने की दृष्टि दृष्टि से भी इसमें संकल्प किया गया है। 2010 तक ऎसी स्थिति सृजित की जाए जिससे कि सभी बच्चे पढ़ाई पूरी कर सकें। एक महत्वाकांक्षी अभियान यह लिया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बस्तियों को भी लेकर उनमें प्रभावी तौर पर हम योजना को कार्यान्वित कर सकें, इस प्रकार का अभियान छेड़ने की भी कोशिश की गई है। इसमें 11 लाख बस्तियों में 19 करोड़ बच्चे, 8.5 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल तथा 35 लाख शिक्षक शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से कोशिश यह की जा रही है कि इस सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव हम ला सकें। मान्यवर, 2002-2003 के दौरान 592 जिलों की जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा इसके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के घटक के लिए 5,443 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई। इसमें अध्ययन कक्षो, शौचालयों तथा भवन अनुसरण, शिक्षा-प्रशिक्षण अनुदान जैसे संविदाओ के अलावा बच्चों के लिए 60 हजार स्कूलों और 56 हजार नए शिक्षकों तथा 452 लाख निणीःशुल्क पुस्तकों को शामिल किया गया है। यह इस बात को प्रकट करता है कि अल्प अवधि में ही हम सबको शिक्षा दिला सकें , इस दृष्टि से यह योजना बनाकर चलाई जा रही है।लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों के लिए जो योजना बनाकर देने की बात कही गई है, इसमें कुछ राज्य हैं जिन्होने योजना बडी विलम्बित करके दी है। इस कारण उनके लिए पूरा धन उनको नहीं जा सका। इसे एक तरह से उपेक्षा ही कहा जाएगा। अब केन्द्र सरकार इसके लिए कौन सा प्रभावी अनुश्रवण का तरीका अपनाए। इसमें बिहार,मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, झारखंड, जिनको बीमारु प्रदेश कहते हैं-सचमुच लग रहा है कि इनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है- इन राज्यों ने सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अपने निर्धारित से भी कम पैसा लिया-उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित 811 करोड़ था, लेकिन योजना देर से भेजने के कारण 441 करोड़ ही उसे केवल प्राप्त हो सका। बिहार के लिए 371 करोड़ निर्धारित था, जिसमे से 143 करोड़ ही वह प्राप्त कर सका। राजस्थान के लिए 389 करोड़ था, जिसमे से वह केवल 212 करोड़ प्राप्त कर सके । मध्य प्रदेश के लिए 433 करोड़ था, केवल 241 करोड़ प्राप्त कर सके और झारखंड के लिए 157 करोड़ था, लेकिन वह केवल 73 करोड़ ही ले सके। अब पैसा है, केन्द्र देना चाहता है, केन्द्र की यह महत्वाकांक्षी योजना है इस महत्वकांक्षी योजना के आधार पर वह कुछ करना चाहता है लेकिन राज्य जब तक उचित अवसर पर योजना

बनाकर नहीं देगा, इसमें कठिनाई आ सकती है। इसलिए राज्य का सहयोग अपेक्षित है। इतना ही नहीं, महिलाओं की साक्षरता में कमी होने के कारण इस दिशा में विशेष योजनाएं बनाई गई हैं और वे महिला सामाख्या कार्यक्रम के माध्यम से बनाई गई हैं ताकि महिलाएं यह महसूस कर सकें कि उनका समान अधिकार है, वे अधिकारिता के साथ वार्ता कर सकें, कहीं भी आ-जा सकें, उनके अंदर आत्मानिर्भरता का निर्माण हो सके। इसे दृष्टि से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत वर्ष 2003-2004 के लिए 30 करोड़ के बजट का प्रावधान है। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए यह बजट केवल 7.5 करोड़ रुपए का था। इतना बड़ा बजट निश्चित रुप से इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे छिपी सदभावना को ही व्यक्त करता है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए खासकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की महिलाओं की शिक्षा और अधिकारिता के लिए 1989 में महिला सामाख्या कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह प्रभावी तौर पर चल सके, इसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। यह कार्यक्रम 6 राज्यों के 33 जिलों में 5,200 गांवों में प्रभावी तौर पर चल रहा है। महोदय, बाकी लोग भी इससे वंचित न रहें, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अपनाया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। इस समय 600 जिलों मे से 587 जिलों को प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल किया जा चुका है और 31 मार्च, 2002 तक 9.669 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के तहत शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों मे से लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं, 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

मान्यवर, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, महिला सामाख्या कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि पर्याप्त मात्रा मे जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनके द्वारा साक्षरता की दिशा में हम सफलता प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही साथ व्यापक तौर पर हम प्राथमिक शिक्षा का कार्य कर सकें, इसके लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। जिले-जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को विनिर्दिष्ट किया जा सके कि अमुक स्थान पर प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता ज्यादा है, इसे ध्यान में रखकर जिले को ही केन्द्र मानकर योजना निरुपित की गई है। इसके लिए जो कार्य किया गया है, मैं कह सकता हूँ कि मंत्रालय ने इस ओर बहुत प्रभावी ढंग से ध्यान दिया है और इसके आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक लाख, साठ हजार नए स्कूल खोले गए हैं जिनमें 84,000 वैकल्पिक स्कूल हैं। इन वैकल्पिक स्कूलों मे लगभग 3.5 मिलियन बच्चों को शामिल किया गया है और एक लाख, 70 हजार बच्चों को विभिन्न तरह के सेतु पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, विभिन्न जिलों मे 1997-98 में 79.33 लाख नामांकन था जो बढकर वर्ष 2001-2002 में 90.26 लाख हो गया है। आगामी चरणों मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए जिलो मे कुल नामांकन जो वर्ष 1997-98 में 185.31 लाख था, वह वर्ष 2001-2002 में बढ़कर 422.65 लाख हो गया है।

मान्यवर, अभी जो आंकड़े आए हैं,उनके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पढने के बाद ज्यादातर बालिकाएं जो 5वीं कक्षा मे पढ रही हैं,वे स्कूल छोड़ देती है। ऎसी बालिकाओं की संख्या 42 प्रतिशत है। इसी तरह जो बालिकाएं 8वीं कक्षा में पढ रही हैं और जो बाद में स्कूल छोड़ देती है, उनकी संख्या लगभग 58 प्रतिशत है। यह चिंता का विषय है। ये जो बालिकाएं

स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, उनको फिर से कैसे आगे पढ़ाया जाए, इसको व्यवस्थित करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं और उनके तहत जो वैकल्पिक स्कूलों की व्यवस्था की गई है,वह इस दिशा में एक अच्छा प्रयत्न है और शायद वह इसे पूरा कर सकेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से भी कार्य करने की कोशिश की जा रही है। 1999-2000 और 2000-2001 वर्षों के नामांकन तथा पुनरावृत्ति संबंधी ई.एम.आई.एस. आंकड़ों के पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर का अनुमान लगाने के लिए पुनर्सरचनात्मक तथा प्रत्यक्ष रुप से सहयोगी तरीकों को प्रयुक्त करने वाले 13 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले राज्यों के 102 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिलों के लिए एक अध्ययन आयोजित किया गया है। ग्रेड-ए तथा प्राथमिक स्कूल के अंतिम ग्रेड के बीच 13 प्रतिशत जिलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की प्रतिशतता 10 परसेंट से कम थी तथा एक तिहाई जिलों में यह प्रतिशतता 20 फीसदी से कम थी। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि 72 प्रतिशत जिलों में स्त्री-पुरुष अंतर 5 प्रतिशत तक कम हो गया। परन्तु अधिकांश जिलों में पढ़ाई बीच में छोडने वाले बच्चों की अधिक दर अभी भी चिंता का विषय है। मान्यवर, जो विभिन्न कार्यक्रम इस दिशा में अपनाए जा रहे हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात सबको शिक्षा सुलभ हो सके, यूनिवर्सिलाइजेशन आफ एजूकेशन-सब को प्राप्त हो सके-इस दृष्टि से भी विशेषकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से विशेष रुप से जो पाठ्यक्रम प्राथमिक और आठवीं अपर प्राथमिक इनके पाठ्यक्रम की दृष्टि से एन.सी.ई.आर.टी. विशेष रुप से व्यवस्था करती है और पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाकर कि किस ढंग से बच्चों का समुचित तौर पर विकास हो सके,बच्चे ज्ञान अर्जित कर सके,शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से सारी चीजें चलती हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि एन.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से जो इस बार पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया,यह निश्चित रुप से पहली बार लोगों का लगा है कि भारतीय समाज की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखते हुए कुछ बिन्दु सुनिश्चित किए जा रहे हैं जिसके आधार पर पढने वाला बालक अपना आधार अच्छी तरह से मजबूत कर सके। लेकिन, मान्यवर, दुर्भाग्य यह रहा कि उसको लेकर के बडा हो हल्ला मचाया गया। जबकि यह कहा गया था कि इसमें एन.सी.ई.आर.टी. ने जो बात रखी थी, धर्म के संबंध में कुछ बातें आई थीं। और यह कहा गया था कि नैतिकता के विकास के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब इस बात को लेकर बड़ा शोर-शराबा मचाया गया और इसको लेकर के राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। कहा गया कि जो अपने ऐतिहासिक पुरुष थे उन ऐतिहासिक पुरुषों को जब कुछ ऐसे इतिहासकारों ने दूसरे शब्दों में निरुपित करने का प्रयत्न किया था- किसी को लुटेरा कहा गया था, किसी को डाकू कहा गया था, जब उसको बदला गया तो बड़ा शोर-शराबा मचना शुरु हो गया और यह बात कही जाने लगी कि यह सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का भगवाकरण होता जा रहा है। मान्यवर,यह बडी शर्मनाक स्थिति है। दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरोज दुबे (**बिहार**): सर,...

श्री कलराज मिश्र: आप अपने भाषण में कहें। मान्यवर, दुनिया के अंदर ऐसी कभी कोई चीज नहीं रही है। दुनिया में सम्पूर्ण विश्व में शैक्षिक विकास की प्रक्रियाओ का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि उस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक जो

विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं के आधार पर जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था होती है और उसको ध्यान में रख कर उन बच्चों को सुसंस्कारित करने का प्रयत्न किया जाता है तभी सही मायने में शिक्षा का समुचित विकास होता है।उस दिशा में अपने ऐतिहासिक पुरुषों को उनकी स्मृति करते हुए लोग चलें,यह बात कही गई तो लोगों ने यहां कहा कि यह भगवाकरण हो रहा है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे-सीधे कह दिया कि जो भी पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है वह ठीक है, उसको ठीक से आगे चलाना चाहिए और जिन लोगों ने इस पर उपद्रव किया था विशेषकर वामपंथी बंधुओं ने,मैं वामपंथी बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर पश्चिमी बंगाल के श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने यह कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को वामपंथी इतिहासकारों ने गलत तरीके से निरुपित किया है। उन्होंने जो देश के लिए किया, उसका समुचित तौर पर वर्णन नहीं किया गया है और एक तरह से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को नीचा दिखाने की कोशिश की गयी है। आज वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं-मैं पश्चिमी बंगाल के बंधुओं से कहना चाहता हूँ,सरला जी बैठी हुई हैं-दुर्भोग्य की स्थिति तो यह है कि अभी सुप्रीम कार्ट मे केस चल रहा था, उसमें सॉलिसिटर जनरल साल्वे जी ने पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रश्न पत्रों का बंडल रखा और प्रश्न पत्रों के बंडल में उन्होंने विषय है"राष्ट्रीय एकता और अखंडता झूठे राजनैतिक नारे हैं" इन्हें झूठे राजनैतिक नारे बताया जाता है और कहा जाता है कि इस पर लेख लिखो। इसी प्रकार से "भारत में हिंदुओं और हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है"- किसके लिए जगह है? कहा जाता है कि "पंचवर्षीय योजनाएं एक धोखा है" ...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरला माहेश्वरी (**पशिचमी बंगाल**): महोदय, कहां से बोल रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सबसे...(**व्यवधान**)....

श्री कलराज मिश्र:मैं जो बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक आधार पर बोल रहा हूँ।...(**व्यवधान**).... आप ये प्रश्न पत्र देख लीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जो राष्ट्रीय एकता के दुश्मन बने हुए हैं, वे आज यह बात कर रहे हैं? वे यह कह रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? कौन से पत्र बांटे गये हैं? ...(**व्यवधान**)....

कौन से पत्र थे? कहां की सरकार के प्रश्न पत्र थे? ...(**व्यवधान**).... ऐसे कौन से प्रश्न पत्र बांटे हैं? ...(**व्यवधान**).... इसे सभापटल पर रखा जाए।

श्री कलराज मिश्र: "लोकतंत्र एक षडयंत्र है" इस पर लिखो"। क्रांति ही प्रगति का एकमात्र रास्ता है...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति: ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रश्न पत्र रखे गये हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं।

श्री कलराज मिश्र: आप देख लीजिए। 1 अगस्त 2002 के समाचार पत्रों में बाकायदा उल्लिखित है। यह उनमें आया है और यह है तो बहुत दुखद है। इतना ही नहीं-8 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लीजिए।...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरला माहेश्वरी: आप इसको प्रमाणित कर दीजिए...(**व्यवधान**)....

श्री कलराज मिश्र: इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वरगिस साहब अच्छे जर्नलिस्ट हैं, विद्वान आदमी हैं उन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि इसे हटा देना चाहिए। धर्म का नाम आ गया है, बहुत खराब है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्वयं वरगिस साहब ने, जो जाने माने पत्रकार हैं,चार सितम्बर....

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड): मैं अपने वक्ता से इतनी गुजारिश करुंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न ले जो इस सदन में उपस्थित होकर अपनी पैरवी न कर सके। आप यह कह सकते हैं कि किसी ने याचिका दायर की थी।

श्री कलराज मिश्र:मैं उसको वापस लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि उन्होंने याचिका दायर की थी लेकिन उन्होंने जो पहले पत्र लिखा था, श्रीमान के.एन.सिंह जी को, जो सचिव, नेशनल फांउडेशन फॉर कम्यूनल हारमोनी थे,उन्होंने लिखा था कि कम्पैरिटिव रिलिजन ऐंड कल्चर की जानकारी सभी के लिए आवश्यक है तथा यूजीसी और एनसीईआरटी के पाठयक्रम मे इसे शामिल किया जाए और पढ़ाया जाए। बाकायदा यह पत्र उन्होंने स्वयं ने लिखा था। स्वयं श्री सिंह ने भारत सरकार को यह पत्र लिखा कि कंपैरिटिव रिलीजन ऐंड कल्चर ऐप्रीसिएशन को यू.जी.सी. और एन.सी.ई.आर.टी. के पाठयक्रम मे शामिल किया जाए। यह स्वयं याचिकाकर्त्ता बंधु की तरफ से लिखा गया है। यह पहले दिया गया है लेकिन उसको उन्होंने राजनैतिक पुट देकर- जो वास्तविकरण का दिग्दर्शन कराने के लिए शुद्ध मनोभाव से प्रेरित होकर यहां के बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा देने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा था-उसको राजनैतिक स्वरुप देकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गयी है। यह दुर्भाग्यजनक है। महोदय,माध्यमिक शिक्षा में सबको शिक्षा सुलभ हो सके, इस दृष्टि से यह व्यवस्था की गयी और समानता के साथ शिक्षा का सुलभीकरण हो, यह योजना बनाकर कार्य करने का प्रयत्न किया गया। अधिक से अधिक लोगों को सहायता और सहयोग दिया जा सके, बजट के माध्यम से वह पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए इसके लिए भारत शिक्षा कोष गठित किया गया। मैं निश्चित रुप से इस बात के लिए मंत्रालय की तारीफ करुंगा।

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुई)

इस भारत शिक्षा कोष के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति निगमित क्षेत्रों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों,अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों से दाम, अंशदान प्राप्त करना है, जो शिक्षा कोष के अंतर्गत होगा। मान्यवर, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण पद्धति संस्थान, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यमों के द्वारा शिक्षा सुलभ हो सके, सुलभीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई है और उसमें मैं कहना चाहूंगा कि 448 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, 2002-03 के दौरान 36 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे और 2003-04 में 60 विद्यालय खोलेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसी ढंग से 843 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, 627 विद्यालय स्थायी भवनों में हैं और इस वर्ष के दौरान 31 भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है तथा इस माह के अंत तक अन्य 25 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

मैडम, इसी तरीके से राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण पद्धति संस्थान, जिसमे 2001-02 में दो लाख से अधिक छात्र नामांकित थे, ने कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, परा-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 60 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरु किए हैं। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण पद्धति में जो एक नई चीज आई है, उसके लिए मैं मंत्रालय का स्वागत करुंगा, उनकी तारीफ करुंगा और उनको बधाई दूंगा। उन्होंने यह कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण पद्धति संस्थान के अंतर्गत "ऑन डिमांड परीक्षा पद्धति" शुरु की गई है यानि जो पढ़ रहा है, जो लाभार्थी है, वह जब चाहे तब परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और इस दृष्टि से यह निश्चित ही बड़ा स्तुत्य प्रयास है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।

मैडम, केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम और ग्रामीण श्रेत्रों के प्रतिभावना विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम को राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम में मिलाया जा रहा है जिससे प्रस्ताव है कि कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों को अब 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति दी जाएगी और पात्रता के लिए अधिकतम आय सीमा को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा जो इस समय 25,000 रुपए प्रतिवर्ष है। यह स्वयं बच्चों के अंदर शिक्षा की दृष्टि से प्रोत्साहन पैदा करने वाला प्रयत्न है। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह निश्चित रुप से आम जनमानस के अंदर ऐसी भावना पैदा करेंगी कि हम आगे से आगे बढकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मैडम, मानवीय मूल्य शिक्षा स्कीम मे भी संशोधन किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि सहायता की अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपए प्रति परियोजना से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परियोजना कर दिया जाए और सरकारी संगठनों के अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान आदि जैसे सरकारी संगठनों को भी इस स्कीम के क्षेत्राधिकार मे लाया जाए। यह प्रयास स्तुत्य है, इसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि यह भाव को प्रकट करता है कि हम उस शिक्षा को दिशा मे ले जाना चाहते हैं।

मैडम,केवल इतना ही नहीं,अल्पसंख्यकों के लिए भी क्षेत्र गहन कार्यक्रम तथा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण स्कीम को परस्पर मिलाकर एक स्कीम तैयार की गई है ताकि इस पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जा सके। इस नई स्कीम में मदरसा शिक्षा को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य मुक्त विद्यालय के साथ जोड़ने के प्रयास करने का प्रावधान है और अल्पसंख्यक संस्थाओं, मदरसों मे कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाएगा।

दसवीं योजना मे मुख्यतः भाषाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने पर बल दिया जाएगा और विभिन्न भाषा संस्थान भाषाओं को पढ़ाने के लिए "ऑन लाइन मॉडयूल्स" तैयार कर रहे हैं। हिंदी मे मशीनी अनुवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए शब्द संपदा तैयार करने हेतु डिजिटाइजेशन करने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। यह कोशिश की जा रही है और,मैं समझता हूँ कि यह आज के वैश्वीकरण के अंतर्गत प्राप्त चुनौतियों के आधार पर एक ऐसा प्रयत्न है जिसमे आगे चलकर हम डटकर विश्व के अंदर अपना एक जबरदस्त स्थान बना सकते हैं।

मैडम, इसी ढंग से उच्च शिक्षा के अंदर भी विशेष प्रयास और प्रयत्न किए गए हैं। यू.जी.सी. ने एक दौरा विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी। दौरा विशेषज्ञ कमेटी के अन्तर्गत

149 विश्वविद्यालयों का दौरा करने की दृष्टि से सोचा था जिसमें से 130 दौरा समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। यह विशेष ध्यान देने की बात है, इसके अंतर्गत जो आधार उन्होंने माना है, वह विश्वविद्यालय के परफोरेमेंस बेस को माना है। कार्य निष्पादन ही उस विश्वविद्यालय को विशेष रुप से सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से या उसको अनुदान देने की दृष्टि से आधार होगा। इसलिए दसवीं योजना में विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले सामान्य विकास अनुदान का एक तिहाई भाग नई योजना में विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन पर आधारित है, यानी परफोरमेंस बेस्ड है। प्रमुख पहल के रुप में विश्वविद्यालय अनुदान ने वैज्ञानिक आधार पर विश्वविद्यालयों के शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशासन कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विकास रॉडार तैयार किए हैं। गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालयों को सहयोग प्रदान करना और गुणवत्ता के आधार पर ही उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना, यह एक विशेष ध्यान देने की चीज है जिसमें गुणवत्ता भी सुरक्षित रह सकती है। विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी डाटा बेस संकलित कर लिया गया है जिससे भारतीय विश्वविद्यालयों में उदीयमान प्रौद्योगिकियो तथा उनकी क्षमताओं का पता चलता है। इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुसंधानकर्ताओ की सहायता करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ एक विशेष योजना तैयार की गई है, वह विशेष योजना है ज्ञान दर्शन चैनल, जो इन्होंने प्रारम्भ की है। विभिन्न चैनलो के माध्यम से, ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से विषय के बारे में,समुचित रुप से जो विशिष्टता प्राप्त किए हुए ऐसे विद्वान हैं, उनके द्वारा भाषण करवाना ताकि शिक्षार्थी, लाभार्थी उसको ठीक से देख सके। इतना ही नहीं एक तो मैं यह कहना चाहूंगा और इसके लिए मैं बधाई दूंगा, वह यह कि यह एकलव्य ज्ञान दर्शन चैनल है। इस एकलव्य ज्ञान दर्शन चैनल की कल्पना कहां से आई? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा प्रदान नही की थी। लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को मानस रुप से अपना गुरु मान लिया था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन और पांडवों को ही शिक्षा देते थे। लेकिन उनको मानस रुप में गुरु मानकर, उसके आधार पर उनकी मूर्ति बनाकर, उनका दर्शन करते हुए उसने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। एक अदभुत स्वरुप का दर्शन हमारे सामने होता है। यह एकलव्य ज्ञान दर्शन चैनल इसी प्रकार की एक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत इंजीनियरिंग़ का छात्र जहां भी रहें, जो भी इंजीनियरिंग़ के प्रोफेसर्स होगे, तकनीकी विशेषज्ञ होगे, ऐसे लोग,उस चैनल पर अपनी बात कहेंगे। उसको देखकर, उसके आधार पर वह शिक्षा प्राप्त करेगा और उसी आधार पर वह ज्ञान प्राप्त करेगा और विशिष्टता हासिल करेगा। निश्चित रुप से यह बडा स्तुत्य प्रयोग है और इतना ही नहीं,जिन्हें इंजीनियरिंग क्लास में प्रवेश के लिए बडी परेशानियां होती थी, उनको भी दूर करके उसको तीन स्तरीय कर दिया गया है। तीन स्तरीय कर देने पर केवल तीन स्थानों पर उसको परीक्षा देनी पड़ेगी और उसके आधार पर केवल देश मे कही भी तथा बाहर के देशों में भी वह जा सकता है, उसका प्रवेश हो सकता है। इससे वह अनेक प्रकार की जटिलताओ से भी मुक्ति पा जाएगा। इस ढंग से उच्च शिक्षा के बारे में, तकनीकी शिक्षा के बारे में और माध्यमिक शिक्षा के बारे में उसकी गुणवत्ता को स्थापित करते हुए, गुणवत्ता भी बराबर बनी रहे, शिक्षकों को प्रशिक्षण बराबर होता रहे। इन सारी बातो को ध्यान मे रखकर, मंत्रालय की तरफ से जो लगातार प्रयास हो रहा है, वह निश्चित रुप से स्तुत्य है। मैं मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ और साथ मे एक सुझाव भी जरुर रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी इस सुझाव पर ध्यान दे। मैंने पढ़ा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यूजीसी के एक समारोह मे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर भाषण देते हुए कहा था कि यूजीसी केवल अनुदान ही नहीं देती है, यूजीसी विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी अनेक

प्रकार के उपक्रम कर रही है। उसका विकास हो, कॉलेजेस का विकास हो, इसके लिए चिंता कर रही है। यू.जी.सी. का नाम बदलकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलेपमेंट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा विकास आयोग रखा जाए तो ज्यादा समीचीन होगा, ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं चाहूंगा कि इस प्रसंग पर मान्यवर मानव संसाधन मंत्री ध्यान देंगे तो बडी कृपा होगी। मानव संसाधान विकास मंत्रालय के अंतर्गत और भी कई चीजे हैं। इन्होंने महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तीकरण के बारे में अनेक प्रकार की योजनाएं निर्धारित की हैं ताकि महिलाओं में स्वाभाविक रुप से आत्मनिर्भरता का निर्माण हो, स्वावलंबन का निर्माण हो। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के आधार पर अपने को समान रुप से महसूस करते हुए आज इस पुरुष प्रधान देश और समाज के अंदर स्वयं को आगे प्रस्तुत करते हुए वे आगे बढ़ें,इस दिशा मे अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। इतना ही नहीं बाल विकास के लिए, बच्चों के लिए, बाल विकास की दृष्टि से भी कुछ व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय बालक आयोग बनाने का फैसला किया गया है। बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए, बच्चों में जो विकृतियां आ रही हैं, अनेक प्रकार के दुर्गुण आ रहे हैं। उन्हें ध्यान में रखकर कि कैसे इसको व्यवस्थित किया जाए, कैसे उसकी आधारशिला मजबूत की जाए, सुसंस्कार विकसित किया जाए, इसको ध्यान में रखकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है कि हम राष्ट्रीय बालक आयोग बनाएंगे। राष्ट्रीय बालक आयोग के जो प्रस्तावित कार्य होंगे...(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरला माहेशवरी बाल आयोग होगा।

श्री कलराज मिश्र:हिंदी में राष्ट्रीय बाल आयोग।

श्रीमती सरला माहेशवरी बाल होगा।

श्री कलराज मिश्र: बाल आयोग कर लो। इसे शुद्ध कर लो आप तो हिंदी की विदुषी हैं। मान्यवर, इस आयोग के अंदर इस प्रकार के कार्य है:

(क) विद्यमान विधियों के अधीन बालको के लिए उपबंधित रक्षोपायो से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना,उनकी जांच करना।

(ख) केंद्रीय सरकार को उन रक्षोपायो के कार्यकरण के बारे मे वार्षिक रुप से और ऐसे अन्य अंतरालो पर, जिन्हें आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) बालको की बाबत विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का शोध करना और उनका सावधिक पुनर्विलोकन करना तथा उनके सर्वोतम कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(घ) लोकहित में ऐसे वाद वित्त पोषण करना, जिसने बालको को प्रभावित करने वाले विवाद अंतर्वलित हो।

(ङ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारी के नियंत्रणाधीन बालको के लिए तात्पर्यित किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य आवासिक स्थान या संस्था का, जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाई जाने वाली संस्था भी है, जिसमें बालकों को उपचार, सुधार या

संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना और यदि आवश्यक पाया जाए तो उपचारिक कार्यवाही के लिए इन प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना।

(च) निम्नोक्त से संबंधित शिकायतों की जांच करना और इन मामलों पर स्वप्रेरणा से विचार करना:

(I) बालको के अधिकारो का वंचन।

(II) बालको के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों को कार्यान्वित न करना।

(III) बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए नीतिगति विनिश्चियों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों की अनुपालना न करना तथा ऐसे बालको का अनुतोष प्रदान करना या ऐसे विषयों से उदभूत विषयों पर समुचित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना।

(छ) उपरोक्त कार्य के आनुषंगिक कोई अन्य विषय होंगे तो उन्हें भी लिया जा सकता है।

अर्थात बालक का चतुर्दिक विकास हो सके, वह समुचित तौर पर आगे बढ़ सके, अपने सारे संस्कार और शिक्षा को ग्रहण करते हुए इस बात को ध्यान में रखकर यह आयोग बनाने का फैसला किया गया है। यह निश्चित रुप से इस बात को अभिप्रेत करता है कि मानव संसाधन सही मायने मे अपने नाम को चरितार्थ कर सके, इस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं। मंत्रालय को उस दिशा मे अग्रसर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान्यवर ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: माननीया।

उपसभापति:मान्यवर हो सकती हैं।

श्री कलराज मिश्र: माननीया।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (**डा. मुरली मनोहर जोशी**): मान्यवर मे दोनो शामिल हैं।

श्री कलराज मिश्र: पूर्वोत्तर राज्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने की दृष्टि से विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 2001-02 में 60 करोड़ रुपये की लागत से 4800 आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके साथ पूर्वोत्तर राज्यों में आईसीडीएस परियोजनाओं को उन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओ के बराबर ला दिया गया है जिनमें निर्माण कार्य अतिरिक्त प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 हेतु 95 करोड़ रुपये की लागत से 7800 आंग़नबाडी केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस उद्देश्य से 44.60 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त वर्ष 2002-03 के दौरान निर्मुक्त की गई है। महोदया, आंगनबाडी कार्यकर्मियों के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जो बेचारी बहुत कम वेतन के आधार पर काम करती थीं,

लेकिन इस प्रकार सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए यह चिंता की है और इस राशि को बढ़ा कर एक हजार तक करने का सुनिश्चय किया है। निश्चित रुप से यह एक अच्छा प्रयत्न है और लोग प्रोत्साहन से आ सकेंगे।

कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं, जो कि विभिन्न राज्यों के पिछड़ेपन को देखकर बनाई गई हैं, विशेष कर जो लोक जुंबिश कार्यक्रम है। यह बात सही है कि यह विदेशी अनुदान के आधार पर चलने वाला कार्यक्रम है और राजस्थान को विशेष केन्द्र मान कर वहां जो विशेष पिछड़े जिले हैं उनको हम ठीक से शिक्षित कर सके और उनके अंदर आत्म-निर्भरता का निर्माण कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था इस योजना के माध्यम से बनाई गई है। इस कार्य में पूरे देश के अंदर हम लोगों को साक्षर बना सकेंगे, उन्हें शिक्षित कर सकेंग़े और जहां भी लोगों के अंदर हीनता का भाव है उसको दूर करते हुए आत्म-निर्भरता निर्मित कर सकेंगे, आत्म –विश्वास पैदा कर सकेंगे। उसको ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के , चाहे विश्व बैंक से, चाहे और भी स्थानों से प्राप्त जो अनुदान हैं उन अनुदानों का उपयोग करते हुए, विभिन्न एनजीओज के माध्यम से, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से,विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से, कार्य करने का प्रयत्न किया गया है। मैं यह कह सकता हूँ कि जन शिक्षण संस्थान इसमें एक विशेष महत्व रखता है। जन शिक्षण संस्थान मे जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, श्रमिक हैं, गरीब हैं, गरीब लोगों के बीच में उनके अंदर आत्म-विश्वास कैसे पैदा किया जाए उनको भी शिक्षित करते हुए उनके अंदर अज्ञान की जो छटा है उसको कैसे दूर किया जाए, इस दिशा मे भी उसके माध्यम से एक प्रयत्न किया गया है। सतत शिक्षा अभियान को चलाने के लिए जो भी साक्षरता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत जो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वें लगातार सतत शिक्षा में लीन रहें इसके लिए सतत शिक्षा की दृष्टि से पुस्तकालयो की व्यवस्था, उसके अनुरुप किताबों की व्यवस्था, यह भी करने की कोशिश की गई है। महोदया, केवल इतना ही नहीं, यह भी किया गया है, बालभवन के नाम पर कि जो वीरोचित भाव के बालक हैं, जो किसी कार्य विशिष्ट में स्थान रखने वाले बालक हैं या विशेष वाद-विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत अपना प्रथम स्थान रखने वाले बालक हैं, जो प्रतिभा सम्पन्न लोग हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी बाल भवन की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से मैं यह कह सकता हूँ कि सब तरफ ध्यान देने के पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, यह स्वयं मे बड़ा स्तुत्य है। उसको और प्रभावी स्वरुप प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न हो रहा है। लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि सही मायने मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपना कार्य सुविचारित ढंग़ से, सुनियोजित ढंग से और प्राथमिकताओं के आधार पर, कहां कौन सी प्राथमिकता है, उसको ध्यान मे रख कर, शिक्षा एक बुनियादी स्वरुप है, उस बुनियादी स्वरुप का एहसास करते हुए और आम आदमी उसको प्राप्त कर सके, इस दिशा मे आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय बडी तेजी के साथ काम कर रहा है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो सके, इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था और विशेष व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण हों, जो शिक्षक सेवारत है उस के लिए भी और जो शिक्षक अवकाश प्राप्त है, उस का कहां उपयोग किया जा सकता है, इस दृष्टि से गुणवत्ता के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं। महोदया, इन योजनाओ के माध्यम से शिक्षक गुणवत्ता युक्त हो, शिक्षार्थी गुणवत्ता युक्त हो, पुस्तकें समुचित और व्यवस्थित हो और पढ़ाई करने का स्वरुप भी ठीक हो- इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर एक विशेष प्रकार का मानदण्ड सुनिश्चित करते हुए मंत्रालय की तरफ से जो प्रयत्न हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि निशिचत रुप से आने वाले काल में

वैश्वीकरण की प्राप्त चुनौतियो का सामना करने मे यह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। महोदया, भारत मे जहां आज सर्वाधिक स्नातक पैदा होते वे स्नातक गुणवन्त युक्त स्नातक होंगे और एसे स्नातक रोजगार प्राप्त कर के समुचित तौर पर आत्म-निर्भर होकर स्वयं के रोजगार का सृजन करते हुए आगे बढ़ सकेंग़े, ऐसा स्वरुप चलाने का मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मानव संसाधन मंत्रालय अपने नाम के अनुरुप अपने को चरितार्थ करने में सफलता प्राप्त करेगा। महोदया, इतना कहकर, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया , इसके लिए आप के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, we will continue with the discussion after lunch. There are only four minutes left for 1 o'clock. The next speaker is Shri Eduardo Faleiro. So, I adjourn the House till 2 o'clock and then we will continue with the discussion.

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair]

THE V'CE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Eduardo Faleiroji, you will continue.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Sir, if you permit me, I will start before continuing.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : All right, you start.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Jvlr. vice-Chairman, I thank you for giving me the opportunity to speak on the discussion of the working of the Ministry of Human Resource Development. It has been truly said that 'knowledge is power' and in any human development index, education is a major factor for computing such an index. A country is truly powerful, and, it has always been so, only when its population is highly educated. This is even more true today, at this point of time, when we are living in a "knowledge society", where knowledge is the key. In the next generation -the generation that comes after me, after us a man who is illiterate, even in India, will have very little scope. He will have hardly any employment. A person must be, at least, able to read the instructions as to how he should act in the factory. Or even in agriculture, he must be able to read the instructions. What is-written on the label, at least, he must be able to read

that. If he does not have this basic literacy, the man is at a loss and we as a country will be consigned to the ghetto of the global community, if we do not overcome the serious problems that we have today, in terms of illiteracy. I need not point out that in just terms of quantity India has the largest number of illiterate people in the world. Considering all these facts, over the last 50 years, we have taken steps to pay particular attention to education. This, I must say, was very much true particularly at the time of Shri Rajiv Gandhi. Shri Rajiv Gandhi's Government did two things. Firstly, increased quantitatively the funding for education. He was actually the person who created the Ministry of Human Resource Development to give a focus and importance to this subject in its totality. It was he who gave an increased funding, in spite of all difficulties, to education and human resource development. At that point of time, during Shri Rajiv Gandhi's time, we reached almost 4 per cent -- or maybe even we surpassed 4 per cent -- of the GDP. This was unprecedented and it has remained unprecedented, upto stage, as a percentage of GDP. The commitment in the National Education Policy was to move, as early as possible, to 6 per cent of GDP for education and for human resource development in general. This was advised by the Kothari Commission and it had been accepted by the Government itself. Then, it was not a question of acceptance. It was a question of doing. This is what he did actually in terms of, as I have said, increasing the funding and in terms of giving a focus to policy on education so that we actually develop a society which is in tune with the Constitutional objectives of secularism, democracy and egalitarianism, the main focus being on quality education. That is what the National Education Policy, 1986 was all about; quality education, equal opportunity in access to education, gender equality and really moving towards or at least within a comparatively limited period of time halving the rate of illiteracy in this country. These are the things that were done then. The National Education Policy was debated in detail by the Central Advisory Board of Education where the representatives from the State Governments were represented. We can never forget when we discuss education that education is in the Concurrent List of the Constitution. Therefore, no Government should forget it. Unfortunately, this Government does forget and does not care about complying with this mandate. Education being in the Concurrent List of the Constitution, the States must be consulted; their views must be elicited. If they disagree, then some sort of agreement must be reached, a national consensus must be reached. If there is no national consensus, there is no national policy. You can't call a policy a national policy only because it is

made by the Government of India, if it does not have the support of the State Governments. We are living in a federal or a quasi-federal structure and we can never forget that. Therefore, what I am saying here is that this tremendous boost that we had given, and rightly so, to education and human resource development, particularly at the time of Shri Rajiv Gandhi by increasing funding substantially to unprecedented levels, as I have said, almost to 4 per cent or a little above 4 per cent of GDP, a level which had not been reached before nor after, and then also focusing on the National Education Policy of 1986 which is still in force and was debated in great detail by the State Governments in the Central Advisory Board of Education and was debated in great detail in this Parliament itself and the Parliament passed it unanimously, the matter of deepest concern is that all these things that were done then and should have continued with the same emphasis, if not greater emphasis, are now being given a go-bye. The Constitutional objectives as set up in the Preamble of the Constitution are being forgotten. Secularism, democracy, egalitarianism, etc. are being forgotten. What we had done in terms of funding, that is not done any more. The focus we had given to equal access to education, common school system and all these things are necessary if the country has to really progress and to join the comity of nations as an important member of the global knowledge society. All these things have been given a go-bye. This is a disaster. There is no other word to express it, but this is a disaster and I will appeal to the Government to reverse these policies. Now, the hon. mover of the debate had made a very good speech, very good in term of rhetoric, but the rhetoric is very far away from the reality and this Government - I must admit it and I must concede - is very good at rhetoric. But, then, the reality doesn't seem to matter, the reality doesn't seem to matter to this Government and that is how in November, 2001, mind you, one-and-a-half year ago, in greatest haste, the Government brought in Parliament, introduced, considered and passed, all in the same session, in that short session of Parliament, the 93rd Constitution Amendment Bill for the universal compulsory education. Now it is the 83rd Constitution Amendment Bill. Now, one-and-a-half year have passed. What has happened? Of course, at that point, the four Assembly elections were on the anvil, you see, the elections to Punjab, Uttar Pradesh, Uttaranchal and Manipur, and, therefore, this must be a coincidence, or may be more than a coincidence. It is for the Minister to explain. What was the hurry? Up to now, one-and-a-half year later, this provision, which is now In 83rd Constitution Amendment, has not been implemented and it is not in sight

when it will be implemented, if at all. I asked a question from the hon. Minister on the universalisation of elementary education on 21^{s1} February, 2003; and this is Unstarred Question No.394, and there I asked the Minister and the. Government, now that you have passed the Bill in such a tremendous haste one-and-a-year ago, when are you going to implement it? And, what was the hurry? I got from the Minister a reply saying that this 83^{lj} Constitution Amendment is not going to be implemented until and unless a Central legislation is being brought in. Now, what he says here, and I quote, "it is to be followed by Central .legislation with detailed mechanism to implement the Constitution (Amendment) Act." Now, the question is: what was the hurry in passing the Act? And, then, when are you bringing this Central legislation, please tell us Mr. Minister. I am going to ask another specific question - apart from making a speech here, the whole point is getting information from the hon. Minister - when are you going to bring here the Central legislation to implement this Act? It is a question. One-and-a-half year have passed, and then, how are you going to do it? You have no way of doing it, Mr. Minister, and I don't largely blame you, you see, because the Government doesn't listen to you. I read in the paper that the Government is not giving you the money. The short point is this, Mr. Vice-Chairman, the Government has no money, whatsoever to implement this Act which was brought with such a great fanfare, and I will point out how this happens. To begin with, look at the shocking facts, let us forget their rhetoric and let us look at all our facts, and the shocking facts are these that after passing the 83rd Constitution Amendment, the Department of Elementary Education gets less money this year than it got last year. If this is not shocking, what is? I must point out here that the Tapas Mazumdar Committee had assessed the requirement for universalisation of elementary education at something like a little more than Rs. 13,000 crores. It was, as a matter of fact, Rs.13,700 crores per year according to the Tapas Mazumdar Committee. Then, comes the Government with the 93$^{r:l}$ Constitution (Amendment) Bill, and in the Financial Memorandum, you must have noticed that it mentions, what we require is just Rs. 9,800 crores. How, you have broughj down from Rs.13,700 crores to just Rs.9,800 crores is a matter which has never been explained to this House, and having Rs. 9,800 crores per year, and having done this, where is the money now? As I have said, you have given less money, this year, than you gave last year. Now you have brought in Sarva Shiksha Abhiyan. And, for that Sarva Shiksha Abhiyan, you have allocated something like Rs. 1,500 crores or thereabout. From where do you get this money? By

destroying very good schemes and programmes which were there in the field of education! The major programme which was trfere in primary education created by the National Education Policy, 1986, as revised in 1992. was the Operation Blackboard. The Operation Blackboard was to the effect that all our schools would have proper classrooms, that our schools would have sufficient number of teachers. And this was done. This was actually started with the objective that our schools would have primary education for at least four years. And, this necessary, wonderful programme has now been abolished. Of course, a politically correct expression is used saying, 'merged in Sarva Shikshan Abhiyan'. 'Merged' means and in effect, in substance, abolished. 'Merged' means that you are now substituting this programme 'Operation Blackboard', which was so necessary, by something known as "alternative" education or "informal" education, where, according to your own Government reports, there are no classrooms, only three years' education at the maximum, and no teachers. There are only para-teachers. Who is a para-teacher? A para-teacher is somebody who is recruited on a contract for a period of time; maybe, one year at the most. Usually, it is either a local grocer or a baker or maybe even a student who is recruited: He has no future in this profession because he is on a contract. He doesn't apply his mind. He is not even there. Very often, the reports are — from Government -- that they are collecting the money without' even going there. And this is a disgraceful thing to do, to give to the people of this country, in the name of education, a total absence of education; a caricature of education, a tragic caricature of education, that goes by the name of informal or alternative education. Now, Sir, this is what is being done. You have removed this good, essential programme 'Operation Blackboard', taken out (Rs. 58 crores or thereabout, and put it in Sarva Shiksha Abhiyan. And, you have also removed many other programmes including the Central Plan for the North-Eastern States. A sum of Rs.328 crores was allotted last year for this. This is a commitment made by the Prime Minister. Our Prime Minister, when he goes there, always .makes commitments everywhere. And, immediately, promptly, the Government follows it with an allocation, which, promptly, the Government cancels. An example is this Central Plan .for the North-Eastern States. Now, the North-Eastern States' Plan has been cancelled this year. They say, it has been 'merged'. That means there will be no attention paid, when the North-Eastern States require so much attention. Illiteracy is rampant there; excepting, perhaps, Mizoram, all the North-Eastern States require this Plan. I am sure, the people-from the North-Eastern States will

rebel and register their strongest protest against the cancellation of this programme which was for their benefit and was essential for the people of that area to come up to levels in which they can compete nationally to begin with, and then, all of us can compete globally. This is a question to which I will come in a moment. Therefore, this is the tragedy. Now, let us assume for a second that even this Rs. 1,500 crores will be available. Where rs this Rs. 1,500 crores and where is that Rs. 13,000 odd crores which, according to Tapas Majumdar Committee, is required? And, where is Rs. 1,500 crores or thereabout in your Sarva Shiksha Abhiyan and where is Rs.9,800 crores which, according to yourself, will be required? Yes; it is expected that 75 per cent will be contributed by the Centre and 25 per cent will be contributed by the States. The States are broke. The States are not being consulted. We have asked for this hundreds of times. Two out of three judges of the Supreme Court - Justice Dharmadhikari and Justice Sema -- in the Aruna Roy's case have urged the Government to reconstitute the Central Advisory Board of Education (CABE), where all the State Governments are represented, and to convene it - and, they have said -before the next academic year. Now, the Government is disrespecting the order of the Supreme Court! Why, Mr. Minister, have you not reconstituted and convened CABE? I appeal to you to do this. I appeal to you to carry the States along with you. Otherwise, this policy cannot be a national policy. We are adding to the division. We are dividing people on the basis of religion. We are dividing people on the basis of economic classes. Now, we are dividing ourselves, as the Union and the States also. I mean, how ' much can we divide people who will rue after us? The Prime Minister has said, "Iraq has a lesson for all of us." Iraq is one side of the coin. There is another side of the coin, which is economic aggression. And, for that, we must be all united to fight economic aggression from any quarter whatsoever, from outside our borders.

Now, the point is as follows. You have allotted for Sarva Shiksha Abhiyan something like Rs.1500 crores. Let us forget about the Tapas Mazoomdar Committee Report. Let us look at your own financial memorandum to the 93rd Constitution Amendment Bill which is now 83rd constitutional amendment. And there you say Rs. 9800 crores. Where from are you going to get that? Twenty-five per cent from the States! They are not going to give you 25 per cent, because they do not have money. States are broke. And you are not consulting them. You have not held any conference of the State Education Ministers since 1998. Why, Mr. Minister? You had not consulted the State Education Ministers, you had not convened

their meeting and not met them for the last four or five years. Since 1998! When will you do that? When will you have interaction with the State Education Ministers in the forum that has been provided for this purpose? And, therefore, they are not going to contribute 25 per cent, they have no money and you are not consulting them. Assuming they contribute, still you have to come out with Rs.8000 crores *or* so. Where is that money? I know you are going to the Ministries, we read in the papers, asking them, urging them, cajoling them and they are ignoring you. They are not giving you the money. You must explain to us what you are going to do. Things are bad. This year it is awful and it is going to be 'awfuller', if I may use the term, much worse, next year, because now there is a programme known as 'District Primary Education Programme' fully funded by external agencies. Rs.1500 crores or so have been allotted for this. It gets over this year. This is the last year. Next year, you are going to have Rs. 1500 crores less. So, this Government just has no money. I read in some quarters, many people calling this 93.[cl] Constitution Amendment Bill, a fraud on the Constitution. As you can see, Mr. Vice-Chairman, I am not used to strong words. But I. cannot disagree either because that reflects the reality. You bring things in such haste on the eve of elections, and having done so, you do not even get the President's assent. It took you to December 2002, more than a year, to get the President's assent. Now, you have no money and you are going to have even less money next year. You have no way to implement this constitutional amendment of universalisation of primary education. If you have, please, tell us. From where are you going to get the money and how much money? When are you going to bring in this Central legislation, which according to your reply here in Parliament is necessary for implementing this constitutional amendment. Now, this is what is happening. Now, this is the situation with which we have to deal, Mr. Vice-Chairman, on this crucial element of elementary education. Just last November, the UNESCO produced a report, that is,- Education for All, a report where, out of about 200 countries, India comes at the bottom with *27* other countries which will not achieve any of the three criteria which have been earmarked at the earlier conference of the UNESCO in Senegal to be achieved by all countries by the year 2015. And the three criteria are: Universal and compulsory elementary education, gender equality and halving illiteracy rate. We have the dubious distinction of the company of the countries of sub-Saharan Africa, and, of course, Pakistan - if it gives us any satisfaction - is also there. In this tragic situation, in this open world - I am coming to that in a- minute - competitive world of open competition, how

can we survive? Forget about the big rhetoric of 'we being the light of the rest of the world,' how can we survive in this open competitive world which the WTO and the GATS -- I am coming to that in a moment - have now created? Therefore, Sir, this is the tragedy of our elementary education in the hands of this Government. It has reversed all the good things we had done and limits itself to rhetoric and I will mention now talking about rhetoric and religion and things of that sort. I had asked the Minister that there was a report, and there was a Committee constituted in the 1990s known as the National Steering Committee on Textbook Evaluation. Now, this Committee submitted two reports quite some years ago. It indicted, among other things, several textbooks and several organisations, some of them affiliated to the Sangh Parivar, for producing material on communal and sectarian line which will poison the minds of the children. Therefore, I asked the hon. Minister what action had been taken on these two reports, and the Minister was kind enough to reply, through his letter of 6^{m} April, 2001. I quote: "The two reports of the Committee were circulated to the State Governments by NCERT for the necessary follow-up action. No feedback has been received from the States". This was on 6^{lh} April, 2001. Two years have passed. Therefore, I am asking the hon. Minister now whether he has got this feedback. If he hasn't, will he please remind the States? Mr. Minister, with your intelligence and ability, if you pay some attention, you will appreciate that we cannot divide this country. As it is, we have problems. We have to unite this country. We have to homogeneise this country. We have no option but to live together.. Either we live'together, or, we die separately, especially now, during these times of globalisation, when forces are just waiting, as the Iraq war has shown, to pounce upon countries like ours. We have to unite as a country, not just as a country, but the region as a whole. The European Union has shown how a region can become a potent defence against the pressure of globalisation. The answer to globalisation is regionalisation, to a very great extent. So, you have got to forget these things. God will take care of all of us, or, only those of us who are Godfearing. Maybe, others also...*(Interruptions)...* I cannot speak for them.

Therefore, I will appeal to you: Forget about these things for a moment. Let us strengthen unity. Let us advance economic progress. That is the key. When everybody is economically happy, everything is all right. It is when there is economic unhappiness that such questions arise. Therefore, let us concentrate on these things.

The short point at this stage is as to what has happened in terms of the follow-up on those two important Reports of the National Steering Committee on Textbook Evaluation. And, if nothing has happened, what steps are you going to take, hon. Minister, to see that the States send you the reports and you take action in the matter -- whether they are affiliated to the *Sangh Parivar* or not. Such organisations cannot, and should not, be allowed to continue with their sectarian motivation and bias in the education of small kids, because the small kids do not forget what they get in education. "A child is really the father of the man", as has been said.

What has been happening in elementary education is a disaster. But even worse has been happening at the level of higher education. Never before have there been so many agitations and strikes by teachers and students in universities all over the country, as have taken place over the last few years. Education, in general is being commercialised, is being privatised; disinvestment' is a big thing for this Government; they. are disinvesting everything; they are now disinvesting education also. But, Mr. Minister, education is not a commodity. It is a human right. Therefore, the Government cannot disinvest education. It is not a commodity. Education has been held as a right of everybody. Education has been held as a precondition for any country to be truly strong. It is not weapons that make a country strong, as examples have shown in the recent past. It is education, knowledge, ability to innovate, creativity and so on. Now, you have disinvestment in higher education. Teachers are being ill treated, just as higher education is being ill treated. I will mention here the problems of teachers, and make an appeal. Mr. Minister, those organisations are trying to meet you. They have asked for appointment with you any number of times, over a period of years. Why don't you talk to them? You don't talk to the States. You don't talk to this Parliament. As I have said, the policies, which are being pursued by this Government - you will admit -are a part of your agenda. 'You are a party with a difference!'; therefore, your policies are different. Your policies are not in consonance with the National Policy on Education, which has been approved by this Parliament unanimously, and which is still in force. You have to come to this Parliament to get its approval, if you want any change in the NPE. You have to come to this Parliament for an endorsement of the changes that you want to bring in the NPE. You are not taking Parliament into confidence. You are not taking the State Governments into confidence. Following the Fifth Pay Commission recommendations, the UGC had recommended to the Government pay-scales and promotions that

would have made the teaching profession less unattractive in relation to comparable professions. However, the Ministry of Human Resource Development refused to implement the UGC recommendations, leading to countrywide protests. In September, 1998, the Ministry entered into a written agreement with the striking teachers. Since then, however, the Ministry of Human Resource Development has gone back on its commitment one-by-one. It has refused to implement what it committed and withdrawn promotional avenues that ti<ey had officially notified. The plans, to downgrade the teaching profession now envisage making all appointments contractual. These plans are clearly part of the policy to convert the public-funded universities and colleges into commercial enterprises with hire-and-fire service conditions, and teachers who are forced to serve the interests of private profit rather than help the students to develop their abilities to think independently, critically and creatively. Not only the. Human Resource Development Ministry has targeted negatively the service conditions of the teaching profession, but the Minister, Dr. Joshi, has refused to have any dialogue with teachers. Repeated representations and agitations by teachers across the country have been arrogantly ignored. So, this is no way. You have to talk, Mr. Minister. You' are only talking to yourself, and three or four persons around you - three or four persons! You have to talk to this Parliament; you have to talk to the State Governments; you have to talk to the academia and you have to talk to these teachers, in this particular case. I appeal to you and urge you to have a dialogue with these teachers so that you can solve whatever grievances there exist, and there are plenty of them of a fundamental nature.

Now, this is the approach - disinvestment, disinvestment from everywhere, from education also. As I have said, this is not possible. Education is a human right. Education is not a commodity, and, in this, this Government is. aided, abetted by the international organisations. This Government is going even, beyond these organisations. It is aided and abetted by the WTO and GATS. GATS, General Agreement on Trade in Services, which makes education a commodity and puts it in the market place, is not in the interest of India, at this point of time because then we Can only buy and send our money out. We cannot compete at all. At this point of time, we are not in a position to compete internationally. What does GATS say? GATS says that you must open your educational market - and health also, of course, and other services, but education is, what we are talking about - to.everybody else; there cannot be any restrictions; and whatever treatment you give to your own national institutions, you must give

to the foreign institutions. So, if you give some sort of subsidy to your universities and colleges, the same subsidy you must give to any foreign university who wants to come and olant itself here. GATS says, therefore, 'no subsidy'. But, they have it in good style. What happens in the WTO, what happens in the world today, in the political and economic front? This applies only to us - no subsidies; it does not apply, for instance, to the United States. Here, the Government expenditure in education, the UNESCO has calculated it, is less than 10 dollars per person. In the United States, it is 1400 dollars per person. We are talking about a capitalist country, free enterprise, who tells all of us about free trade, who tells all of us not to have subsidies! The subsidy of the Government alone is 1400 dollars per person! You see, they have all these big Rockfellers, Fords and so on, which we don't have. The only hope for us here is the Government funding. There is no other source, and therefore, GATS, at this point of time, until and unless we become competitive and we can benefit from GATS, should not be acceptable to this country. What are the categories in GATS? One is cross-border services, that is, the Internet and things of this sort. We have, the IGNOU, Indira Gandhi National Open University; quite a good thing, but internationally, it cannot compete. We cannot compete in open universities. Then, you have 30,000 students who are going abroad and paying there, and the number of Indian students going abroad is increasing. Whilst in India, the number of foreign students coming here has decreased by almost half, and I will give you, the exact figures. The number of foreign students coming to India in 1994-95 -- Government statistics, all my statistics are Government - was 11,888; by 1999-2000, it had gone down to 6,988. So, 30,000. going up, and 9,000, going down! Where are we competing? Then you have commercial presence of foreign educational organisations who can come here. Nobody is coming here. They are giving franchises *(Time-bell)* I will take two minutes more. They are giving franchises. There is no investment of anything by them. They just give a franchise where you can use their name and they do not care further. How many foreign universities and colleges have a presence here at the moment? How many are there? Some known and most of them unknown? They are making big money out of education. What we are doing at the most we have some schools in the Gulf for our own Indian children. We cannot do anything more. We cannot compete with them. The only place, the only slot where we could do something is "movement of natural persons". We have teachers and academicians who could go abroad and earn something. But that is not permitted by the developed countries. They have blocked GATS.

Therefore, until and unless we become internationally competitive, we have to go slow on GATS. And I am suggesting a strategy. Before that let me ask the hon. Minister what commitments have we made under GATS in the field of Education. Why is this tremendous secrecy? We as Members of Parliament do not know even what GATS is. A colleague was asking me the other day, "Are you talking about the GATT?" GATT is over; it is history. GATS is the present and the future. Why don't you create awareness here on this subject? Why don't you improve on the quality of advice you get from your experts? The developed countries have a plethora of expertise. They know all the loopholes. They create loopholes to benefit them. We hardly know anything. So, you have to increase on the expertise available to you. First and foremost create awareness in Parliament, carry the State Governments, and the academia with you explain to them what GATS'is all about. That is number one. Number two, I would strongly suggest that we should not make any commitment under GATS in a hurry and no commitments until you are able to tell Parliament how the country is specifically benefited by any such commitment. The essential thing to take advantage of GATS is to be internationally competitive. At-this rate, we are nowhere in the picture. We are not going anywhere except to a complete disaster, unless we increase government's funding for education at all levels and increase it very substantially. Let us not blame the WTO or the GATS for our problems. I will give you an example. Much before we made any commitment under GATS, much before GATS asked us anything, a Circular was issued by the Ministry of Human Resource Development on 14" January, 2002, which gave permission to all and sundry to carry school teaching ,mind you, 'at school level' of foreign degrees. This particular Circular concerns permission to take up GCE, IGCSE examination of the University of London, IGCSE examination of Cambridge in India. It also permits the IBO, that is international Baccalaureat organisations to hold examinations here. There is something known as a "core curriculum". We are discussing here and accusing each other on the curriculum. The Minister is bravely talking about Indianisation of education, indigenisation of curriculum, about the spritualisation of the curriculum. None of these organisations are bothered about your curriculum. They have nothing to do with your curriculum. And with these foreign school certificates, students get admission to our universities. How do you permit this? Where is the reciprocity? Every international agreement is based on reciprocity. If we recognise the IBO and these degrees, they have to recognise the CBSE qualification for entering their universities. Without reciprocity, you cannot

do this. What we are creating here is two classes of people. I must say it again, one class of people who can pay lakhs of rupees and will get all these foreign qualifications even at school level which was never permitted before. Before, unless you were a son or daughter of a foreigner or of a diplomat who has to move from country to country or you intended to take a course not available in India, only then you could get such education at the American school or British School, etc. And that also, on a case-to-case basis i.e., by submitting an application and getting approval of the Ministry. Now, no such thing is required. Now, it is open for all. Indianisation, indigenisation, spiritualization is only rhetoric to- tell the birds and the Members of Parliament, I suppose. We are doing such type of things without any accountability, without any regulatory mechanism, and, what I am saying here to conclude, is these policies are disastrous. This is taking us to a deep pit of the ghetto of the world. I demand and urge and appeal and beseech the hon. Minister to reverse these policies and return to our policies, increase funding for education so that it becomes nationally strong and internationally competitive and this is to be done without hesitation. If the Government does not listen to you, there is always a way for you, Mr. Minister. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल):माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर चर्चा शुरु करते हुए सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि शिक्षा प्रसार के नाम पर शिक्षा पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, माननीय मंत्री जी कम से कम उसे वापस लें। प्राचीन काल से 'सा' विद्या या विमुक्तए' तथा 'विद्वान सर्वत्र पूज्यएत' कहते हुए मनुष्य के जीवन में शिक्षा की भूमिका व्याख्यापित की गई है। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने शिक्षा को सर्वागीण विकास का साधन माना तो बंगाल के मनीषी शिक्षाविद विद्यासागर ने कहा, यदि कुछ महीनों के लिए फसल चाहिए तो गेहूं और धान बोएं, कुछ वर्षों के लिए फसल चाहिए तो आम के पौधे लगाएं और अगर आप हजारों वर्ष तक उजाले की फसल काटना चाहते हैं तो शिक्षा के बीज बोएं। हम पीढी दर पीढी फसल काटते जायेंगे। इसी धन को हम निरंतर बढ़ता हुआ पायेंगे | ज्यों ज्यों बांटेगे रोशनी और फ़ैलती जाएगी यही कारण है, आजादी की लड़ाई के दौरान सभी ने एक स्वर से शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। यहां तक कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहला शिक्षा बजट पेश करते हुए कहा था। I quote, "The expenditure on education should be at par with the Defence."

डा. डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित हुआ था। उसने 29 जून, 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और कहा था,

I quote, "The destiny of India is now being shifted in her classroom. This, we believe, is no more rhetoric. In a world, based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of people."

यह अत्यन्त दुखद है कि आजादी के बाद के इन 56 वर्षों में शिक्षा को विविध आयामों और कोणों से जांचने-परखने के लिए कमोबेश 119 कमेटियां और आयोग बनें। पर सभी रिपोर्ट कागजी पुलिंदा बन कर रह गई और संविधान निर्माताओ का हर बच्चे को शिक्षा देने का सपना,सपना ही रह गया। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों के रख-रखाव, उन्नति श्रीवृद्धि के लिए यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इस देश के भावी नागरिकों का विकास भी उचित हो। शिक्षा मंत्रालय की परिधि विस्तृत हो गई और उसमें शिक्षा के साथ महिला बाल विकास भी समेकित कर लिया गया, लेकिन सरकार क्या अपनी सूझ-बूझ को विस्तारित कर पाई, अपनी दृष्टि को विस्तारित कर पाई? वह तो और संकीर्ण, संकुचित और मध्यकालीन बर्बर मानसिकता से पोषित सांप्रदायिक,कुसंस्कारमुखी और अवैज्ञानिक हो गई। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर संघ की शिक्षा व्यवस्था हावी हो गई। आजाद भारत में पहली बार शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में एक निजी संस्थान की अनुशंसाओ को सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जबकि इस संस्था की विवादित विचारधारा से कौन परिचित नहीं हैं। मंत्री जी उत्तर देते समय कहेंगे कि यह चैप्टर तो क्लोज हो गया है लेकिन यह बार-बार हमें याद दिलाता रहेगा। मंत्रालय ने अत्यंत चतुराई के साथ इस संलग्न प्रपत्र को राज्य शिक्षा मंत्रियों के विचाराधीन एजेंडे का मुख्य बिंदु बना दिया। विद्या भारती के अध्यक्ष चित्तलांगिया जी को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी अधिक प्राथमिकता दी गई। इसमें जो अनुशंसाएं थीं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरीण मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्कूली शिक्षा के निर्णय प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी एवं विकेन्द्रीकरण, उच्च शिक्षा की फीस का ढांचा एवं उसकी पहुंच को सीमित करना आदि ये सारे तो ऊपरी दिखावे के लिए थे, असली एजेंडे को छिपाने की अधकचरी कोशिश की गई। इन्हें यदि संघ परिवार के इतिहास और दर्शन के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षा को हिन्दुत्व एजेंडे में उलझाने की असली साजिश जाहिर हो जाएगी। इसी में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम के भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण एवं आध्यात्मीयकरण जैसे शब्दजाल के साथ-साथ हर स्तर पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को शामिल करने तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर सभी के लिए भारतीय दर्शन का कोर्स अनिवार्य करने जैसी सिफारिशें जो पहले नई नहीं थीं, एक बार फिर से दी गयीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि संघ परिवार की भाषा ने भारतीय एवं राष्ट्रीय जैसी अवधारणाओं को ब्राह्मणवादी तथा कट्टरपंथी हिंदुवाद का पर्याय बना दिया गया है। इसके जरिए संकीर्ण सांस्कृतिक **...(व्यवधान)...**

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the word 'Brahamanwad' should not be used. No derogatory term, against any caste, should be allowed. *...(Interruptions)...*

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: आप इसे पुरोहित तंत्र कर लीजिए। भाषा बदल लीजिए **...(व्यवधान)...** ब्राह्मण तो मैं खुद हूँ,ब्राह्मण बोलने मे क्या बुरा है**...(व्यवधान)...**

श्रीमती सरला माहेश्वरी:महोदय, यह इन लोगों की नीति है**...(व्यवधान)...**

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh) : The Chair should kindly give a ruling. *...(Interruptions).,.*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...** आप इधर कहां देख रही हैं? कम-से-कम देखिए इधर, चाहे बात उन की बोलिए। अब आप बैठ जाइए। वह बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

SHRI BALBIR K. PUNJ : I am only requesting that the term like 'Brahamanwad' should not be used. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सरला माहेश्वरी: यह बहुत गलत परंपरा है कि कोई आदमी अपनी बात रख ही न पाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): फिर आप उन को देखकर बोल रही हैं। आप को जो बोलना है, इधर बोलिए।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Use of any such term should not be allowed because they may cause dissatisfaction among various sections of the society. *...(Interruptions)...* It is my humble request, if you could kindly withdraw the word 'Brahamanwad' *...(Interruptions)...*

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : I have heard you. If it is unparliamentary, it will be removed. We will see the record. *...(Interruptions)...*

श्रीमती चन्द्रकला पांडे:इसके जरिए संकीर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल:सर,एक तो शुरु से ये स्पीच पढ़ रही है **...(व्यवधान)...** मैं जब पढता हूँ तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अब आप एक महिला के पीछे मत पडिए। आप बैठ जाइए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: सर, मैं महिला के पीछे नहीं पड़ता। **...(व्यवधान)...** मैं कभी नहीं पड़ता।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): बोलिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: इस प्रपत्र में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का जिक्र आता है जिस में हिंदुत्व को एक जीवन शैली के रुप में परिमाणित किया गया है न कि एक संप्रदाय के रुप मे जिस की आड़ में विद्या भारती नें "भारत की अमूल्य विरासत" का केवल यह संकीर्ण अर्थ निकाला है कि पाठ्यक्रम मे सांस्कृतिक विरासत के बतौर मात्र वेदों, उपनिषदों का अध्ययन कराया जाए। संघ परिवार की इस सोच को हमारी समृद्ध विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत और समकालीन भारत की मिली-जुली संस्कृति के आधार को दरकिनार करने के एक सुनियोजित षड़यंत्र में देखने की जरुरत है।

महोदय, इस सिलसिले में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की चर्चा मैं करना चाहूंगी। विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं की गयी है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में पाठ्यक्रम परिवर्तन की घटना अपने आप में न भूत में हुई, न भविष्य में होगी। महोदय, राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में किए जाने वाले बदलाव पर कुछ बुनियादी सवाल उठाते हुए यह कहा था कि बच्चों के मानसिक विकास पर इस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक नहीं सुनी गयी और अब ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध भी नहीं हैं। जो किताबें उपलब्ध हैं, उन में हिटलर, गांधी, गोलवलकर आदि के बारे मे जो विचार दिए गए हैं, जो धारणाएं दी गयी हैं, उन को देखने से ऐसा लगता है कि जब आप के मन में आता है आप किसी को देशप्रेमी सिद्ध कर देते हैं और जब आप के मन में आता है आप किसी को देशद्रोही सिद्ध कर देते हैं। जब आप की इच्छा होती है तो राष्ट्रवाद की अलग परिभाषा देते हैं, जब इच्छा होती है तो अपने मनचाहे ढंग से काम करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षा सत्र शुरु हो जाने के बाद भी एन.सी.ई.आर.टी. की किताबें बाजार में नहीं हैं।

बच्चे, अभिभावक शिक्षा सभी परेशान है। संसद में भी प्रश्न उठा दिया गया है। किताबें न मिलने के कारण जो व्यापारी हैं, जो माफिया तंत्र है, वे इस क्षेत्र में घुस गए हैं और किताबें छापकर नोट गिनते हुए मुट्ठी भींच रहे हैं। दिल्ली के नकली किताबों के पुराने माफिया जिनका अंग्रेजी के बेस्टसेलरों का जाली संस्करण छापने का धंधा सख्ती की वजह से नहीं चल रहा है, वे एनसीईआरटी की जाली किताबें छापकर चांदी बटोरने में लगे हुए हैं। इधर अभी आज के अखबार में ही था कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा एकाउंट सील कर दिया गया है क्योंकि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें इन लोगों ने नहीं मानी हैं।

मान्यवर, यू.जी.सी. की स्वायतता भी पूरी तरह से खतरे में है। अनेक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनेक पद खाली पड़े हैं और उनको भरने की कहीं गुंजाइश नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। मैकाले की शिक्षा नीति के जरिए क्लर्क पैदा करने का काम हुआ था, लेकिन आप इन ठेकेदारों को बुलाकर किस तरह की शिक्षा देंगे, किस तरह के ठेकेदार पैदा करेंगें? इस तरह तो वे न घर के होंग़े और न घाट के।

मान्यवर, मैं थोडी सी चर्चा बजट के बारे में करना चाहूंगी। अतीत के समस्त जिम्मेदाराना कार्यों से आंखे बचा दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुल आवंटन 19,68,815 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमे से शिक्षा के लिए केवल 43,825 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कुल बजट का मात्र 2.2 प्रतिशत है।...(**व्यवधान**)...

SHRI BALBIR K. PUN J: Mr. Vice Chairman, Sir, Rs. 19,00,000/- crore can't be allotted for Education. *...(Interruptions)...*

श्रीमती चन्द्रकला पांडे:मैं बजट में से देखकर पढ रही हूँ। यह टोटल बता रही हूँ।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री संतोष बागड़ोदिया**): फिगर में भी आपको ओब्जेक्शन है। बोलने दीजिए उन्हें।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, I was always interested in figures. *...(Interruptbns)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): फिगर का जवाब मंत्री जी देंगे। ...(**व्यवधान**)... फिगर के बारे में आप बात मत करिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: मान्यवर, इसमें विगत वर्ष से एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा का भविष्य क्या होगा? इस वर्ष के आर्थिक सर्वे में स्वीकारा गया है कि पूरे देश मे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं की संख्या 19 करोड़ 30 लाख है, इनमें 3 करोड़ 70 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। भरती होने के बाद बहुत से बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते हैं और उससे भी अधिक बच्चे आठवीं क्लास पहुंचने से पहले स्कूल जाना बंद कर देते हैं। हमारे देश मे दुनिया के कुल निरक्षरों का 34 प्रतिशत है। निरक्षरों की यह सीमाहीन भीड़ अब तक उस जगत मे है-

वह संसार जहां पर अब तक पहुंची नहीं किरण है।
काली है धरती अब तक अंबर भी तिमिर वर्ण है।

इस घोर अंधेरे से आबादी के इस बड़े हिस्से को निकालने के लिए किसी भी तरह का बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का भी यही हाल है। केन्द्रीय बजट में शिक्षा पर वृद्धि दर केवल 0.7 है। तिरानवां संविधान संशोधन विधेयक, पिछले साल पास करा लिया गया। आप 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन 6 वर्ष से छोटे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? यह उम्र का वह दौर है, जहां विकास की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। उन बच्चों के लालन-पालन, उनकी नर्सरी और शुरुआती सालों की शिक्षा के मामले में ये बच्चे हाशिए पर छोड़ जाएंगे। इस मामले में यह कानून जीरो से छह साल के बच्चों के लिए भेदभाव को मान्यता देता है। इससे वे शेष जीवन मे भी अक्षमता का शिकार होते रहेंगे। बच्चियां घर संभालेंगी और बाल श्रम को भी अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मान्यवर,मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा का यह हाल है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा से तो सरकार ने पूरी तरह से हाथ ही खींच लिये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और कुमारमंगलम बिरला की एक कमेटी बनाई गई थी और उनकी सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा में कम हो गई है क्योंकि उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उन्हें शायद सरकार ने मान लिया है। ऐसा इस बजट से ही लग रहा है। साम्राज्यवादी देश विश्व व्यापार संगठन के उपबंधों के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर भी अपना एकाधिकार कायम करके अपने मुनाफे को बढ़ाने की होड़ में है। कैपिटेशन फीस बढाकर आज हमारे अपने ही परिसरों में विदेशों इंस्टीट्यूट स्थापित हुए जा रहे हैं। यह भी पता नहीं चल रहा है कि इनकी अपने देश में मान्यता है या नहीं? कुछ पढे-लिखे लोग, नवयुवक अगर कोचिंग सेंटर चलाकर कुछ पैसा उपार्जित करना चाहते हैं तो आप उन पर भी टैक्स लगाने में बाज नहीं आते हैं।

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में एक फैशन बन कर रह गया है। यह समझ में नहीं आता कि सर्व शिक्षा अभियान साक्षरता, दूरवर्ती शिक्षा, इन सब की मोडेलिटीज क्या हैं और किस तरह कार्यरत होंगे? दोपहर के भोजन का पूरा बजट देखा जाए तो हर बच्चे के लिए 50 पैसे से 68 पैसे आते हैं। उनमें क्या भोजन दिया जाएगा? पता नहीं। अगर दो टॉफी भी खरीदी जाएं तो वह भी नहीं मिलेंगी। 33 पन्नों के लम्बे बजट भाषण में शिक्षा के बारे में एक लाइन है- "Education is the central vein of our life-time concerns." इसमें तो यह बताया गया है कि जो अभिभावक अपने एक बच्चे पर 12,000 सालाना और बच्चों पर 24,000

सालाना खर्च करता है, उसको इन्कम टैक्स में कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो किसी भी प्रकार से इस इन्कम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तो क्या उनके बच्चों के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कोई बात नहीं सोची है?

प्रौढ शिक्षा के लिए भी जो रुपए रखे गए हैं, उसमें भी एक छोटी सी राशि, प्रति व्यक्ति 8.80 रुपए आती है जिससे शायद प्रौढों को पूरी वर्णमाला भी न सिखाई जा सके।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहुंग़ा कि मैं आपको पूरे भारत का मंत्री बनने की सलाह देती हूँ, संघ परिवार का नहीं। आपसे मेरा अनुरोध है कि स्कूली पाठ्यक्रम की धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक विषय –वस्तु पर हमले, मूल्य आधारित शिक्षा के नाम पोगापंथीपन को बढ़ावा देना, देशी ज्ञान की आड़ में कुसंस्कार युक्त कट्टरपंथी शिक्षा के प्रसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से थोपे जा रहे ज्योतिष –पुरोहित स्पिरिच्युअल कांशसनैस आदि में अपनी ऊर्जा का आपव्यय न करें। कुछ ऐसा सकारात्मक काम करें जिससे इस देश के उदास बचपन और दिग्भ्रमित युवकों के होठों पर मुस्कान लाई जा सके। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): श्री उदय प्रताप सिंह जी। उदय प्रताप जी, आपके पास 9 मिनट का समय हैं।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश):महोदय, यह इनकी मेडन स्पीच है, इसलिए थोड़ा इनके साथ आप उदार हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): यह खुद तो मेडन नहीं हैं न। इन्हें बोलने दीजिए आप। हमने तो इन्हें समय बताया हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा बोलें ही नहीं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मेडन स्पीच में थोडी सी सुविधा दे देनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैंने सुविधा कहां रोकी है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपने शुरु मे इंगित कर दिया कि शायद वह कही उससे ज्यादा न बोलें।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैंने उन्हें समय बता दिया है, अब देखते हैं वे कितना बोलते हैं। मेडन में अनलिमिटेड टाइम भी नहीं है, इसलिए बोलने दीजिए। अगर आप कहें तो सबका समय बढ़ा दें, आपको ही बैठना पड़ेगा 8:00 बजे तक।

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसका जवाब तो कल देना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अगर आप 8:00 बजे तक बैठना चाहते हैं तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह मेरी मेडन स्पीच तो नहीं हैं, मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ। मैंने यह सोचा कि मैं शिक्षा पर बोल रहा हूँ तो सच से शुरु करुं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, हो सकता है कि मैं 8-9 मिनट से भी कम बोलूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कृपा करके मेरी बात को सुना जाए।

3.00 p.m.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, कभी-कभी जब मैं गांव से दिल्ली आता हूँ और दिल्ली से गांव जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमे डबल फेटेसी का सामना करना पड़ा है। हम यहां पार्लियामेंट में शिक्षा के बारे मे बडी-बडी बातें सुनते हैं और जैसे आज आदरणीय मिश्र जी ने चर्चा का आरम्भ करते हुए जो-जो दावे किए थे, जो-जो योजनाएं बताई थीं, वे विद्वान हैं और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने जो कुछ कहा तो लगा कि अगर वह सच है तो हिन्दुस्तान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है लेकिन जब हम अपने गांव मे जाते हैं और जब हम वहां पर हालात देखते हैं तो मालूम होता है कि यहां पर जो चित्र प्रस्तुत किया गया है असलियत उससे बहुत दूर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के महत्व पर मुझसे पूर्व आज तीन वक्ताओं ने अपनी बात कही। इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा के उन्नयन के बगैर किसी देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती और खासतौर से जिन समस्याओं से हम आज जूझ रहे हैं, उनमें तो शिक्षा का महत्व और भी बढ जाता है। इसके लिए भी हम अपने आपको बधाई दे लेते हैं, अपने देश को, अपनी पार्लियामेंट को कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 मे जो कल्पना की गई थी, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, कि मौलिक अधिकार शिक्षा का मिले, वह भी अभी जो संविधान में संशोधन हुए हैं, उनसे प्राप्त हो गया है। लेकिन हम जब गांव में जाते हैं, मैंने तो अभी अखबारों में भी पढ़ा और समय-समय पर आपको जो आंकड़े मिलते रहते हैं उनसे भी पता चलता है कि 50 जिले तो सरकार की स्वीकृति के अनुसार ऐसे हैं जिनमें अभी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। जिनमें है भी, उनमें न के बराबर है। मुझे यू.पी. के गांवों का बहुत अच्छा अनुभव है और खास तौर से उस इलाके का जिससे मैं आता हूँ। वहां पर कई ग़ांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का प्रबंध नहीं है और अगर है भी तो भवन नहीं है, अगर भवन है तो अध्यापक नहीं है, अगर भवन और अध्यापक दोनों हैं तो जो जरुरी इन्फ्रास्ट्रक्चर है जैसे पेयजल, शौचालय, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम बडी-बडी बातें करके यह कल्पना करें कि शिक्षा का उन्नयन हो रहा है, यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, पूरी शिक्षा की बुनियादी है। जैसे अच्छी नींव के बगैर कोई भवन अच्छा नहीं हो सकता, वैसे ही अच्छी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किए बगैर, किसी भी देश में उच्च शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थिति यह है कि बिना मनमोहक स्कूल के, जब स्कूल में कुछ आकर्षक है ही नहीं तो न तो स्कूल में बच्चे आते हैं,अगर आते हैं तो आधे रास्ते से ही भाग जाते हैं, पूरा स्कूल शायद ही कभी उपस्थित रहता हो। ऐसी स्थिति में उनको जो मिल रहा हैं, **वह केवल कागज पर मिल रहा है हम चाहे कितना ही खुश हो लें कि इतना स्कूल हैं** इतने अध्यापक है, उनमें इतने बच्चे पढ रहे हैं लेकिन स्थिति यह है कि जिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, मैं स्वयं चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बात का अच्छा अनुभव है कि बहुत से बच्चों के नाम स्कूलों में सिर्फ इसलिए लिखाए जाते हैं कि उनको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए और उनको कुछ लाभ हो जाए। न वे बच्चे कभी स्कूल आते हैं और न कभी सोचा जाता है कि वे आएं।

मान्यवर, हम लोगों ने एक कल्पना की थी, हमारे समाजवादी आंदोलन का एक नारा हुआ करता था कि शिक्षा मुफ्त हो जिससे कि वह सब तक पहुंच सके। आज सभी जगह शिक्षा की बात की जा रही है लेकिन बगैर शिक्षा को मुफ्त किए हुए उसे आम जनता तक नहीं पहुंचाया

जा सकता। जब तक महंगी शिक्षा और ज्यादा फीस के प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, तब तक शिक्षा को आम जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता।

मान्यवर, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि इस निजीकरण के आह्वान से जो समय-समय पर प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, सरकार करती रहती है, उससे यह हो रहा है कि हमारे यहां कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। गांवों की शिक्षा अलग है, शहरों की शिक्षा अलग है, अमीरों की शिक्षा अलग है,गरीबों की शिक्षा अलग है, हिंदुओं की शिक्षा अलग है, मुसलमानों की शिक्षा अलग है। इतनी तरह के स्कूल हो गए हैं कि दिल्ली में ही ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जिनमें तीन-तीन लाख रुपए फीस ली जाती है और उससे सस्ते स्कूल भी हैं। जो शहरों के स्कूल हैं , वे उनसे नीचे हैं, फिर नगरों के स्कूल हैं, फिर गांवों के स्कूल हैं। महोदय, मैं संसद के माध्यम से सिर्फ़ एक सवाल इस देश से कहना चाहता हूँ कि जब इन स्कूलों से इतनी तरह की धाराएं निकलेंगी, इतनी तरह के लोग निकलेंगे तो क्या आप इन सारी धाराओं के रहते, इतनी तरह की शिक्षा के रहते, इतनी तरह के लोगों के रहते एकता और अखंडता के सपने देख सकते हैं? महोदय, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में देश एक और अखंड रहेगा? उन सबको समान अधिकार नहीं मिलते।

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]

महोदय, मैं एक नया प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आंकड़ों में बहुत कुछ कहा। मेरे पास भी आंकड़े हैं लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ़ एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों में तीन-तीन लाख रुपए लिए जाते हैं, उनमें वह क्या खास चीज पढ़ाई जाती है जो दूसरे विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती? मेरा संसद के माध्यम से देश के सामने यह सवाल है और माननीय मंत्री जी से भी है कि इन स्कूलों में वह क्या चीज पढ़ाई जाती है जिसके कारण तीन-तीन लाख रुपए लिए जाते हैं? क्या वहां गिनती दूसरी है? क्या वहां दो और दो चार नहीं होते? क्या वहां पर सूरज पूरब से नहीं निकलता? क्या वहां साइंस के नियम वे नहीं है जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं? क्या उनमें व्याकरण अलग है? क्या उनका इतिहास अलग है? यह बात दूसरी है कि अब आप इतिहास में परिवर्तन कर रहे हो लेकिन मेरा प्वाइंट यह है कि जिन स्कूलों में तीन-तीन लाख रुपए लिए जाते हैं, उनमें कौन सी चीज ज्यादा पढ़ाई जाती है कि जिसकी इतनी कीमत अदा की जाती है?

महोदय, मैं संसद का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चले जाएं तो यह मुल्क आजाद नहीं होगा। यह मुल्क उस दिन आजाद होगा जिस दिन यहां से अंग्रेजियत और अंग्रेजी चली जाएगी। और माफ करिएगा जिन स्कूलों में तीन लाख रुपए फीस ली जाती है उनमें एक्स्ट्रा कुछ और नहीं पढ़ाया जाता, उसमें केवल यही दो चीजें पढ़ाई जाती हैं-एक अंग्रेजी और एक अंग्रेजियत। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के चलते यह हिन्दुस्तान आजाद नहीं होगा ऐसा गांधी जी ने कहा था। मैं नहीं जानता कि इस देश को आप आजाद मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि शिक्षा मे समानता पैदा की जाए, शिक्षा सस्ती की जाए जिससे कि सब को उन्नति के समान अवसर मिले। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ईसामसीह को सूली पर इसलिए चढ़ाया गया था-जिसमें उनका दोष नहीं था,उनकी कोई और खता नहीं थी, उनकी केवल एक खता थी- कि उन्होंने कहा था कि जिस समाज के अंदर बराबरी नहीं होती वहां

नैतिकता कभी नहीं रहती। There cannot be any morality in a society where there is no equality बस, इतनी सी बात पर जो यथास्थितवादी लोग थे उन्होंने उनको साफ कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब शिक्षा में इतनी गैर बराबरी होगी और फिर इस मुल्क में एकता और अखंडता की बात की जाए तो कभी-कभी हास्यापद लगता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि नीति में परिवर्तन करके जहां तक हो सके जो हमारे कोठारी कमीशन ने, डा. राधाकृष्णण कमीशन ने, जाकिर हुसैन कमीशन ने और जो तमाम कमीशन ने नैबरहुड के स्कूल की कल्पना की थी वह हो कि एक ही क्षेत्र में एक ही तरफ के विद्यालय हो जिससे कि कई बातें होती हैं, गांव का आदमी दूर भाग भी नहीं सकता और इतना पैसा भी नहीं दे सकता। बहुत सोच-समझकर ही ये आयोग बनाए गए थे। उन आयोगों की रिपोर्ट भी आई थीं। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कायम रहने के बजाए उनको ठंडे बस्ते में कहीं डाल दिया गया है और सरकार उन पर काम नहीं कर रही है। मैं निवेदन करुंगा कि उन बातों को फिर से एक बार ले लिया जाए। हमारे मित्र है कलराज मिश्र जी, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। आज उन्होंने खामखाह एक बात कह दी कि कुछ लोग भगवाकरण के नाम पर बडी बात करते हैं। श्रीमान जी, अगर आप देश की सांस्कृतिक विरासत को जो अभी तक बच्चों को नहीं मालूम हो उसको बच्चों तक लाएं तो बडी कृपा होगी। एन.सी.ई.आर.टी. को जरुर कर देना चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी-कभी इतिहास को इस तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता है कि यह लगने लगता है कि या तो जो हमने पढ़ा था वह गलत है या अब यह गलत है। हमारे आदरणीय भाई बैरागी जी बैठे हैं, गौतम जी भी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि राणा प्रताप एक बहादुर राजा थे, इसमें कोई शक नहीं हैं। उन्होंने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। हम उनकी बहादुरी की और उनके स्वाभिमान की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि घास की रोटी खाने के बाद भी उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नही किया। यहां तक हमने उनकी तारीफ पढी है और हमने भी की है। लेकिन हमने भी की है। लेकिन हमने उन्हें हिन्दु कुल तिलक नहीं माना। उन्होंने हिन्दुओं के लिए कोई खास काम नहीं किया। महाराणा प्रताप एक राजा थे तथा अकबर भी राजा थे। उनका अपनी-अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम था, अपनी-अपनी सीमाओं की रक्षा का काम था। सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनकी आपस में हिन्दु मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। अकबर का सेनापति मानसिंह था और राणा प्रताप का सेनापति हाकमखान सूर था। हिन्दू राजा का सेनापति मुसलमान और मुसलमान राजा का सेनापति हिन्दू और अगर इस तरह से यह बात कही जाएगी तो बडी मुश्किल होगी। .... (समय की घंटी).... बस आधा मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):अब आपने अपने हक को स्वयं ही छोड़ दिया तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी से कि हम भी छत्रपति शिवाजी के बड़े प्रसंशक हैं तथा हम कवि हैं तथा उनके बारे में हमने कविता भी लिखी है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमको बड़ा अच्छा लगता था कि जब हमने इण्टरमीडिएट की किताब में पढ़ा था कि जब एक बार शिवाजी के दरबार में किसी मुसलमान महिला को लाया गया तो उन्होंने कहा कि- हे मेरी मां, तू बहुत सुंदर है। अगर मेरी मां भी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। इसके ऊपर एक किताब लिखी है। उस किताब को पढ़ कर हमे लगा था कि मनुष्य हो तो ऐसा हमारा वीर पुरुष होना चाहिए। लेकिन आज जिन किताबों में शिवाजी का चित्र खींचा जा रहा है क्षमा करिएगा हमारे दिमाग में जो चित्र है उससे वह छोटा

चित्र है। हमें पता नहीं कि इस बदलाव के नाम पर आप देश की क्या सेवा करना चाहें ग़े और क्या कर रहे हैं? मैं बहुत लम्बा नहीं बोलूंगा किन्तु मेरे पास बहुत सारी मिसाले हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की नवीं कक्षा की पुस्तक में 1857 की क्रांति को हलचल कहा गया है, क्रांति नहीं कहा गया है। अभी आज के अखबार में आया है कि 12वीं कक्षा की पुस्तक आयी है जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों की रक्षा करने के लिए था। मेरे पास वह अखबार भी है किन्तु उसे मैं क्या प्रस्तुत करुं। यह आज के अखबार में है।

श्री बलवीर के. पुंज: मान्यवर, वैसे यह बात सही भी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): पुंज जी, आप बैठिए। जब आपको मौका मिले तो आप अपनी बात कहिएगा।

श्री उदय प्रताप सिंह: यही मैं कहना चाहता था कि आपकी दृष्टि मे ऐसा होगा किन्तु एन.सी.ई.आर.टी. को अपनी दृष्टि से किताबें लिखनी चाहिए और घटनाओं को देखना चाहिए, आपकी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की अपनी नजर होनी चाहिए और वह देखे कि किसलिए किया गया था। महोदय, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहां ह्यूम पैदा हुआ था। उसने कहा था, शायद आपको मालूम नहीं होगा और अगर मालूम न हो तो आप पंडित सुंदरलाल का "भारत में अंग्रेजी राज्य" को पढ़िए, ह्यूम ने पहले 75 लोगों को एक पत्र भेजा था और यह कहा था कि हम एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जिसमें जनता की अपेक्षाएं सरकार तक और सरकार की योजनाओ को हम जनता तक पहुंचाएं लेकिन जब किसी ने नही किया तब उसने एक क्रांतिकारी मंच की रचना की। इसलिए ऐसा नहीं है, आप ऐसे मत करिए। आपने मेरी बडी मदद की, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मैं यही कहना चाहता था कि एनसीईआरटी अपने चश्में से इन घटनाओं को देखें, आपके चश्में से घटनाओं को देखना बंद कर दे वरना अगर यह परम्परा चल पडी और आगे आने वाली सरकारें भी अगर ऐसा ही करेगी तो आज से सौ वर्ष बाद जो बच्चे पैदा होंगे, उनको समझ में ही नही आएगा कि क्या सच है और क्या सच नहीं है, क्या किसकी दृष्टि है और स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह इसलिए कि जो हमारे राजनैतिक गुरु और दार्शनिक थे, लोहिया जी, वे एक वाक्य कहा करते थे। वे कहते थे कि साम्प्रदायिकता चाहे अल्पसंख्यकों की हो या बहुसंख्यकों की, साम्प्रदायिकता दोनों की बहुत खराब होती है और बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता तो और भी खराब होती है क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा होती है। मै आज यह कहना चाहता हूँ कि छठी कक्षा की एक पुस्तक में प्रमुख धर्म बताए गए हैं कि प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं। उसमें मुस्लिम और सिख धर्म का नाम नही है। उसमें पारसी धर्म का नाम है, ईसाई का है, हिन्दु का है, बौद्ध का है। बोद्ध धर्म का भी कहा गया है, वह अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा किन्तु मुस्लिम धर्म को प्रमुख धर्मों मे नहीं गिनाया गया। 18 करोड़ मुसलमान जिस देश में रहते हो, उसमें वह प्रमुख धर्म न माना जाए, यह कौनसी दृष्टि है? हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं? हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं या अज्ञान दे रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ मे नहीं आ रहा। सिखों का भी उसमें नाम नहीं है। चलिए, सिखों के संबंध में तो बहाना यह हो जाएगा कि सिख तो हिन्दू का ही रुप थे लेकिन वह बात भी सही नहीं है, उनको भी अलग मानना चाहिए। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुधर्मी, बहुभाषा का यह देश है। इसमें सबके हितों का ध्यान रखकर हम अगर आगे बढ़ेंगें तो यह देश आगे बढ सकता है। यह देश इन बातों के चलते बड़ा कमजोर हो रहा है। इन किताबों में कहीं जिक्र नहीं है कि वर्टीकल सिस्टम ऑफ सोसायटी

है जिसके चलते यह देश इतना कमजोर रहा है कि 2000 साल में हमने तीन युद्ध जीते हैं। कनिष्क ने एक युद्ध जीता है या अभी बंगलादेश से एक युद्ध जीते हैं और एक चन्द्रगुप्त सिकंदर द्वारा जीते थे। इसके बीच इतने हमले हुए कि हम एक युद्ध नहीं जीते- इसी जात-पात के चलते, इसी ऊंच-नीच के चलते, इसी गैर बराबरी के चलते। इसके ऊपर कभी हमला नहीं होता। मान्यवर, हो सकता है कि मेरा स्वर बढ़ गया हो पर वेदना के साथ स्वर बढ जाया करता है। आप बहुत विद्वान हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करता हूँ, जैसा अभी मेरी बहिन ने कहा कि कभी देश के शिक्षा मंत्री और ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर बनकर इन सब बातों पर आप विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मिश्र जी पढ़ रहे थे तब मुझे एक कविता याद आ रही थी कि:

तुमने यह क्या किया, बत्तियों की जगह नन्हें दीपों में आंधी का डर रख दिया।
और अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आइना बेवजह तोड़कर रख दिया।

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu) : Mr. Vice Chairman Sir, I am very happy to participate in the debate on the working of the Ministry of Human Resource Development. Sir, I begin with a Tamil saying, a very old saying, which says, 'a king will have respect only in his kingdom; whereas a scholar will have respect wherever he goes." That is the importance that education is being given- in our State, Tamil Nadu. It is not only Tamil Nadu, which lays stress upon education. Our Constitution, our forefathers, had belief in us, and laid down what we should all be. The Preamble of the Constitution itself, which is key to Constitution, says that we should achieve justice, liberty, equality and fraternity. All the four can be achieved only when we grow in education. A man without education is like a blind man. He may be clinically alive, but socially, he is a dead person. So, education has got its importance. Sir, the above is being laid stress on in the further provisions of the Constitution, namely Article 21 - dignity to life; not merely animal living, but living with dignity. It can be achieved only by improving social standards, which in turn, can be achieved only by education. Sir, Article 37, the Directive Principles of State Policy, insists upon the governing people, the people in the Treasury Benches, to bear it in mind that in their governance, they should make every endeavour to see that children of tender age are given education and it is spread everywhere. These are all the visions that our forefathers had, while framing the Constitution. Fifty years have passed. Let us see what is going on around us. Education is now being commercialised. It is being commercialised like anything; I shall come to it a little later. How it is being commercialised - I shall show it with examples - with the connivance and concurrence of the Central Government authorities. I shall say it with illustration. Before that, I will have to say one thing. Tamil Nadu is a forerunner in giving education, with the meagre funds allotted to it. Upto 10+2, everyone is given free education. As far as the

Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, we owe a responsibility to them; we owe a duty to them because of the suppression for 3000 years that we have subjected them to. We are aware of that duty; so, for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, for whatever duration they wish to study, whatever course they wish to study, whether it is Engineering, Medica! or Ph.D., education is free in Tamil Nadu. As far as girls from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, free bicycles are being given to them for going tot the schools. We do all this with the meagre resources available with us. What is the assistance that we get from the Government of India? Nothing. I say this with a great burden on my heart, especially, when a scholarly person like Dr. Murli Manohar Joshi is there. I know he is a scholarly person. He ie an academic person. He knows the importance of education. He has been very rightly chosen for this Ministry. Personally, I bow to him, I respect him; he is like a guru to me. But, unfortunately, the necessary assistance is not forthcoming as far as our State is concerned, even though we are forerunners in education. We have been providing f[r]ee food for the past 25 years to the children in the schools. And we have been doing all this with our own meagre resources, tightening our belts.

Sir, I shall tell you a recent incident. Please, look at the person who is now running the Government in Tamil Nadu! Our leader, Dr. J. Jayalalitha, while on, her way to the Secretariat from her residence, around 10 o'clock, saw at a particular vantage point, some children gathering together, applauding her, and shaking hands with her. Instead of/feeling happy about that, she thought, 'at 10 o'clock in the morning, these Children should be in their schools, in their classrooms; why are they gathering on the streets?' She immediately summoned officers to get hold of the children and their parents, and enquire as to why their children were not put in the schools. Then they realised that poverty is the reason. She gave money to them from the^JW^ funds and from the personaHunds, and they are now put in the school. This is the Chief Minister we have got. This is the State we are running. And what is the reciprocal assistance we are getting from the Centre? Sir, kindly think about us. Kindly pick and choose which State Government is doing well in this country, and please help us. You are there to help us. When we are good, please help us.

Sir, I want to make a specific complaint on a particular aspect. I request the scholarly Minister to look into this. There is an- organisation called AICTE. They are giving permission for starting engineering colleges.

In our State, we have got 275 engineering colleges. They are all private engineering colleges, not the State Government run colleges. There are 275 private engineering colleges. Almost all of them are denied permission by the State Government, of course, for obvious, correct reasons--either the purpose is not good or they do not have monetary resources or they have not fulfilled the norms required for the purpose. The State Government is denying permission to them, but they get permission from the AICTE. How they get it, we do not know! They come and start engineering colleges. Who are they? People who sold soda water and soda colour at the bus-stands! .They are running engineering colleges! A police constable dismissed frOm service for his misbehaviour is running five engineering colleges today with the blessings of the Central Government! What social obligations wi!l they discharge? Will they not sell education to the public? In order to see that the seats are being sold in a particular slot, for a particular sum of money only, they make a click, they join together. They say "this course - this much; this course - this much; this course - this much!" They themselves fix up the norms and allot seats to them. They extract money! Unless you pay the next year payment-which will not be less than a lakh of rupees-- hall tickets for this year will not be given. We have warned them, we have taken action, we have done everything. And unfortunately, the same length of area- I know a particular case-is shown for an engineering college, same is shown for a polytechnic, same is snown for some other purpose! Sir, this is happening right before your eyes and under your nose. We have got specific complaints. We have been complaining to the Central Government, and we have been requesting, "Please withdraw the recognition." They are not doing it. I will be the last man to believe that a paint merchant who has been running a painting shop will be a philanthropist in education; I cannot believe it, because I have seen who they are, and I am a lawyer, of 27 years' standing. I am seeing who they are, how they are running it. AICTE is something whose functioning should be immediately looked into by the Minister of Human Resource Development. It should be thoroughly revamped.

Sir, I have read "Oliver Twist" in my school days. Oliver has got a character in that novel, called "Fagin". Fagin is to train how to pick pockets, how to commit thefts. He will try young students. I will not hesitate in comparing the AICTE with Fagin's academy. That is equal to them. I am saying this because when the State Government is objecting to a particular college being given recognition, sitting 2,000 kms. away, how could you give recognition? Are you consulting the State Government?

Have you merited their objections? This is very strange, Sir. They may have money with them, but that does not mean the soda-colour people and the dismissed police constable can be allowed to run five colleges. This is very strange and very shocking. This is a very sorry state of affairs. , Sir, I would like to invite the attention of the hon. Minister to an important issue because his Ministry is very big like the Banyan tree. I am not having any specific grievance against the Minister. Personal grievance? No. When he came over to Tamil Nadu some time ago and suddenly developed illness, we all felt very sad, and we all prayed that he should recover and go back because he was a guest of our State. A guest who comes to our State should go back in a healthy condition. I have nothing against Mr: Murii Manohar Joshi. I only request him, 'Please tone up the Department". There are seme people, especially in this particular forum which I have now indicated. Sir, Mahatma Gandhi has said -- I am born after his death; I have net seen his face; I have not seen him alive I have read his wo^ds --"the soul of India lives in villages". The Tamil Nadu Government reserves 15 seats in engineering colleges, medical colleges and in certain other se'ected cou'ses for rural public. The convent educated people, the IAS ofrlcers' sons, the IPS officers' sons, who want to take everything, they went to court, and the court struck down that particular notification. Court is there. I am a .awyer and I bow to that. But if the court is stopping the progress, you must come forward, the Ministry should come forward. Tne Ministry should have its eyes open everywhere. They must get information fro^n various sources as to what is going on at a particular place in respect of education. Collection of material should be there. They should come forward. We have approached them and we should ma><^{0} some legislation to make at least 15-20 per cent seats being exclusively r< served Ibr rural people so that they can also become doctors and engineers. Otnerwise, it will agam be cornered oniy by those oeople, defeating the very purpose of the Constitution, of the Directive Principles of the State Policy and the Preamble enunciated in the Constitution. We are not having much attention on building of libraries. Library is one particular sector which is being neglected everywhere and no thought is being given to it at all. A man can never be^built up only by education, only by reading other books and other works of great authors the worldover as well as of our country. The library is one particular aspect which we should think about. We are collecting a cess, called library cess, alongwith municipal tax, and we are to some extent managing the libraries. Sir, I appeal to you, to begin with a Central Library Fund, that would be given in a gracious manner, in a liberal

manner. Please select our State and give liberally to have a cemralised library, to have a good library. I feel that a library should be there in every village and there should be a Central assistance to the said extent and to serve this purpose, there should be some formula worked out by the Ministry. Mr. Faleiro said about implementation of UGC scales. He said that the scales should be implemented. I am against it and I will tell you the reasons. . Sir, this UGC is already granting lot of money. The salary of college teachers is very high. It is eating the State Government's money like anything. It is eating the State Government's money. The school teachers, to begin with, they are recruited as primary school teachers and they carry home an amount of Rs. 8,000, which the villagers do not get. And, the professors are being paid very heavily. In fact, I want a moratorium on their salary for quite sometime.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Only on their salary?...*(Interruptions)...*

SHRI N. J07\HI: Sir, this is my view. I have not interrupted you. This is my view. I heed a moratorium on their salary because of the working hours of teachers. Why am I saying this? I have not learnt by post. I have learnt it from teachers. My friends are teachers. Still I say this. The reason is, when you ask them to evaluate the examination paper, They say, "We are on strike. No, we will not evaluate". All students' strikes nowadays are instigated by the teachers. The teachers are instrumental in causing strikes all over the country. Tamil Nadu has witnessed such a strike very recently. Recently, we have witnessed a particular strike, the Queen Mary's College strike. It was being kindled and blown out of proportion by the teachers for their convenience. We know that. ... *(Interruptions)...* The person who is laughing is not from Tamil Nadu. He knows only laugning. He has no information.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया आप समाप्त करें।

SHRI N. JOTHI: I am summing up, Sir. We say *mata, pita* and *guru* are equal to God. *Mata* gives us birth, *pita* brings up -us and *guru* teaches us. I am not against the teachers. But teachers should realise their social obligation. They should realise their obligation to the country. They should serve. They should not say that they will not evaluate the answer papers. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिश): कृपया आप समाप्त करें।

SHRI N. JOTHI: I am not accusing all the teachers. *...(Interruptbns)...*\ am not accusing all the teachers. *...(Interruptions)...*

SHRI EDUARDO FALEIRO: Everything is collapsing? What guru? ... *(Interruptbns) ..* You give money to guru! ... *(Interruptions)....*

SHRI N. JOTHI: The *guru* will never say, "I will not evaluate your papers". The *guru* will never instigate a strike. The *guru* should teach the students He is an example of a good *guru.* He was teaching. I don't think *hat he had instigated the students of the Allahabad University. I have heard very good things about him. I am only saying about those *gurus,* those people who instigate the students to go to the road and organise a *hartal.* I am only saying about those people. This is a country where we should make some sacrifice. The teachers also should come forward to make some sacrifice for the benefit of the students. I am only appealing to them; I am only requesting them. Mere implementation of the UGC policies will not make the whole issue a different one. It would not help the country grow up in education. The teachers should realise their responsibility. That is all what I am advocating.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):कृपया समाप्त करें। अब आप आसन ग्रहण करें।

SHRI N. JOTHI: My only suggestion is that whenever you increase the salary of teachers, kindly give matching grants to the State Governments. Don't make the State Governments to bear the burden. *...(Interruptions)... A* matching grant should be given to the State Governments so that the burden of the State Governments is mitigated. The State Governments are already kneeling down so badly under the pressure of financial burden. Don't make them bear further burden. The LTC has now come back. All State Government employees have already started asking for LTC. You give them matching grant. Don't burden them.

Finally, I have a humble request that up to the School Leaving Examination, that is, higher education, let the Central Government interference be taken away fully. Initially, according to our Constitution, education was not a Central subject at all. It was not in the Concurrent List. In 1952, it was purely a State subject. I don't know under whose guidance it was brought under the Concurrent List. But from the day it was brought under the Concurrent List, problems cropped up. I only request and appeal to the Minister that up to school education, it should be exclusively a State subject and thereafter education like technical education,

scientific education, etc., should be under the Central Government's jurisdiction. Whenever a State Government objects to the establishment of a particular college on technical grounds, the AICTE, without the concurrence of the State Government, should not automatically, or, in an authoritative manner grant any affiliation. That is all I would like to say. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): श्री के. रहमान खान। आप थोडा ही बोलिए। आपके दल का कम समय रह गया है और कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा कम बोलिए।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. vice Chairman, Sir, the nation is yet to achieve six per cent expenditure on education. If this is our predicament, as a nation, how can we build the nation's human resource?

We have recently passed the Constitutional Amendment Bill and given the Right to Education for children in the age group of six to fourteen. It is more than a year and the Government is yet to come forward with legislation and give effect to the constitutional right. I request the hon. Minister to assure us as to when the legislation is going to be introduced to achieve this objective.

Sir, the Government has introduced several new schemes for universalisation of education, what is called, Government Education Guarantee Scheme and Alternative Innovative Education Scheme in addition to the existing schemes to achieve the total literacy. They are yet to take off and reach every section of the society. It is not enough to draw up schemes. What is necessary is that the benefit should percolate to all sections of the society and not to a particular section. Sir, the per capita expenditure on education should reach proportionately to all the groups in the society. If. the benefit reaches only to certain groups and does not reach all groups, then, there will not be social justice and it will not be possible for the Government to achieve the objective of providing education to every section of the society.

Sir, often, the statistics, which are presented to demonstrate the achievement, are deceptive and misleading. Certain sections of the society will be worst affected, if we go by the overall statistics, ' ead'of group-wise statistics. There is a statistics unit in the departr it, which is the nodal agency for collection, completion, processing and dissemination of the educational statistics in the country. But, there are no data or statistics available about the most depressed sections of the society, the minorities,

the backward classes. There is no statistical data given as to what is the condition of thci education.

It is not that I am pleading that a particular section should be taken care of and a particular section should not be taken care of. All should be taken care of. Jt is the responsibility of the Government to ensure that every section of the society should get their educational right.

The statistics are not complete. There are no statistics available regarding the Muslim community. I was searching for this statistics because the Muslims, the minorities are the worst sufferers in- the field of education. It is an accepted fact. Even, at the time of framing of the Constitution, it was felt that the minorities woutf be neglected. That is why, a fundamental right under Article 31 was introduced. Now, even after having a fundamental right, we do not have the statistics, today, to demonstrate as to what is the percentage of literacy of a particular group, which is deprived. There are no statistics available.

Sir, I cite an example. As per the statistics given, the drop out percentage in the 7[h] standard is 50 per cent in the country. In the case of minorities, it is 93 per cent at the 7[m] standard. *Ham* are you going to bridge the gap? I am talking about the survey conducted by the Government of Karnataka. In a progressive State like Karnataka, the drop out percentage at the 7[th] standard is 93 per cent. If that is the case, how are we going to bridge this 40 per cent gap between the Muslim community and other communities? According to the statistics, this figure is 50 per cent. It is totally misleading. We have to take this into consideration. Sir, the Indian nation cannot march forward when a major segment of the • largest minority group remains backward, illiterate, unenlightened, weak and unhealthy. It is the duty of every section of the Indian society, the State and civil society to uplift this group, which has fallen by the wayside in the race; and bring them to the mainstream of progress and educational development. Instead of bringing them back to this direction, certain vested interests and fundamentalists are trying to throw them on the wayside. The Government talks of modernisation of Madarasas. The initiator of the debate just now was saying that the Government has a programme to modernise the Madarasas. This programme is just on the paper. It is not achieving the desired results. Yes, there are certain programmes. The Minister will definitely claim that tnere are such programmes. On the one hand, they talk of modernisation and on the other hand, there is a systematic campaign to malign the Madarasas. What is a Madarasa?

Madarasa is an educational institution for teaching Arabic. In Sanskrit, we call it *Pathshala* and in English we call it school. There is a perception that in Madarasas only fundamentalism is taught. These Madarasas are existing since centuries. There are Madarasas which also participated in the national movement. There are Madarasas which are more than 100 years old. If one or two Madarasas are indulging in anti-national activities, punish them severely. Identify those Madarasas which am indulging in such activities. Let the people know which are the Madarasas which are indulging in such activities. There are thousands of Madarasas. Children are going to these schools. Are you in a position to replace them with modem schools? Children are going to these schools because they cannot go to the Government schools. There are no schools for them. They want to get primary education in their mother tongue. If you say that they have to take education in their - mother tongue, where are the Government schools for them? Would you assure that all these Madarasas would be replaced by modern sd>x)ls? It is not possible. Under the Constitution, it is my fundamental right to get religious education. Nobody can prevent me from getting religious education. Where should I go to get my religious education? Can you prevent me from'taking religious education? No, it is not the intention of the Constitution. If any Madarasa or a school or a Pathshala indulges in certain activities.. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) : Please conclude.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, I have taken only five minutes, पांच मिनट भी नहीं हुए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं। सात, आठ मिनट हो गए हैं।

श्री के. रहमान खान:सर, मैंने तो अभी बोलना ही शुरु किया है। आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ। यह तो सब्जेक्ट ऐसा है, जिस पर हमें बात करनी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): सही है, लेकिन जो आपकी पार्टी का टाइम है, उसी अनुसार चलना है।

श्री के. रहमान खान: मैं दायरे में ही बात करुंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। मैं भी इस बारे में जानना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण विषय है, जितनी जानकारी आप हमे दे सकेंगे तो उससे हमें भी सुविधा करने में और सहायता करने में।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): माननीय मंत्री जी, मैं इस विषय पर इन्हें रोक नहीं रहा हूँ। उन्हें अपना भाषण करने से अभी रोक नही रहा हूँ, लेकिन उन्हें सचेत कर रहा हूँ कि अपनी पार्टी के समय का भी ध्यान रखे।

श्री के. रहमान खान: सर, मैं उसी के दायरे में बात करुंगा, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। मैं यह कह रहा हूँ कि ये जो हमारे मदरसे हैं, ये नए नहीं हैं, सेंचुरी से है, इनको मोडर्नाइज करने की बात अलग है। यह एक परसेप्शन है कि यहां कुछ नहीं सिखाया जाता। मैं बताना चाहता हूँ कि इन मदरसों में हिस्ट्री सिखाई जाती है, ज्योग्राफी सिखाई जाती है, फिलोसफी सिखाई जाती है, मैथमैटिक्स सिखाया जाता है और एस्ट्रोनोमी सिखाई जाती है। आप सैलेबस मंगवाकर देख लीजिए। कम्प्युटर भी यहां सिखाया जाता है। ये मदरसे इतने सालों से चल रहे हैं, इतना प्रोपेगंडा पहले नहीं था। आज यह प्रोपेगंडा क्यों शुरु हुआ? अगर है, सही है तो हम मानने को तैयार हैं कि ऐसे मदरसों को आप बंद कीजिए, सख्ती से बंद कीजिए। हम आपका साथ देंगे, मगर यह कह देना कि मदरसों के जरिए से फंडामेंटलिज्म है, अब क्या आप मेरी बात मान लेंगे कि संस्कृत की पाठशालाओं को बंद कर दो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं बंद करना चाहिए। इस तरह से आप मदरसे कैसे बंद कर सकते थे?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): एक मिनट। सर,मैं चांदनी चौक क्षेत्र से आता हूँ और मेरे यहां बहुत सारे मदरसे है। मैं कोई मदरसे के खिलाफ नहीं हूँ, किन्तु जब भी किसी ने कोई बात की है वह मदरसे को मोडर्नाइज करने की है, मतलब आज के कंपटीटिव युग में जो एजुकेशन है वह भी दी जाए। अलग-अलग तरह के मदरसे हैं, कहीं पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही है और जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं, वहां वे नहीं होते। चूंकि यह मेरी कांस्टिच्यूएंसी में है और मैं खुद सब लोगों के साथ मिलकर उसको उठाना चाहता हूँ लेकिन कई बार यह भी दिक्कत आती है। अब अगर हम उनको मॉडर्नाइज करना भी चाहे तो कही हम पर यह इल्जाम तो नहीं आएगा कि हम इस्लामी शिक्षा को बंद करना चाहते हैं? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपसे जानकारी चाहता हूँ।

श्री के. रहमान खान:मैं मानता हूँ,लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी ऐजुकेशन में आप हिस्ट्री कहां से सिखाएंगे? जो मेजर मदरसे हैं, जो उनको अलिफ, बे सिखाते हैं, थोड़ा फंडामेटल सिखाते हैं। मस्जिद मे एक अरबी मदरसा होता है, मदरसा आप उसको तसव्वुर करे, उसकी क्या गलती है? आप बोलते हैं और दारुल उलूम, देवबंद की बात करते हैं। बड़े-बड़े मदरसों मे यह सब सिखाया जाता है। तो एक बात यह मदरसों के बारे में थी।

दूसरे, अब मैं माइनॉरिटी ऐजुकेशन पर आता हूँ। माइनॉरिटी ऐजुकेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक मानी हुई बात है कि हम बेकवर्ड हैं, वीक हैं और इसके स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट को कैसे और किस तरह से मालूम हों कि इनकी क्या कंडीशंस हैं। हमारा जो फंडामेटल राइट है- जस्टिस, इक्विटी, इक्वेलिटी, फ्रेटरनिटी एंड लिबर्टी आफ राइटस, अगर हम इन्हें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर डाटा नहीं है, स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं तो वह कैसे होगा। आपने तो कह दिया कि सेन्सस मे यह स्टेटिस्टिक्स नहीं लिए जाएंगे लेकिन आपके पास डाटा क्या हैं कि हि बिलॉग्स टू ए परटिकुलर सैक्शन आफ दि सोसाइटी। मुसलमान को छोड़ दीजिए, रिलीजियस ग्रुप को छोड़ दीजिए। Muslims, as a group of the society. I am not asking Muslims as a religious group, Muslims as a group within the

society. Should they not get justice, should 'hey not have the equality? मैं रिलीजियस ग्राउंड पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहां बात कर रहा हूँ ऐज ए सिटीजन। 15-18 crores group of citizens. We have no statistics; we have no data and whenever we call it, you just say that कि इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकेंगें। हम नहीं पूछ रहे हैं इस्लाम के नाम पर, हम नहीं पूछ रहे हैं मुसलमान के नाम पर, हम पूछ रहे हैं as citizens of this country. A group, a section, -backward section, which has remained weak, which has remained illiterate, उसको आप किस तरह से आगे लाएंगे? मैं यह सवाल आज मुल्क के साथ करना चाहता हूँ । गवर्नमेंट के साथ करना चाहता हूँ कि इस ग्रुप को आप कैसे आगे लाएंगे? क्या चन्द उर्दू के लिए प्रोग्राम करके, चन्द मदरसों के लिए प्रोग्राम करके इस ग्रुप को आगे ला सकेंगे? क्या आप चाहेंगे कि 93 परसैंट सेवंथ स्टेंडर्ड में ड्रॉप हों? मैं मानता हूँ कि आपकी यह इंटेशन नहीं है, मैं मानता हूँ कि यह किसी का इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर यह हमारी इंटेशन नहीं है तो किस तरह से हम इनको आगे लाएंगे? इसके तरफ कहां तवज्जों दी गई है? आपकी इस बुक मे एक लफ्ज नहीं है। आप हरेक पर लेजिस्लेशन बनाते हैं, आर्टिकल 30 पर क्यों लेजिस्लेशन नहीं है? जब एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको ऐचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमारे पास लेजिस्लेशन कहां है? अब कोई अपना हक लेने के लिए हर वक्त कोर्ट तो नहीं जा सकता। तो आपको चाहिए था कि आर्टिकल 30 पर आप एक लेजिस्लेश लाएं और इस तरह से माइनॉरिटीज को उनका हक हासिल हो। यह हरेक गवर्नमेंट को, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यह उसका फर्ज है कि वह एक लेजिस्लेशन लाए और उसके द्वारा फंडामेंटल राइट हासिल करें, लेकिन वह नही हो रहा है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करुंगा और कहूंगा belonging to a group of muslims कि उनको सोशियल जस्टिस नहीं मिल रहा है, **अब यह अलग बात है कि मैं बहस कर सकता हुं कि किस तरह से उसको सोशियन जस्टिस नहीं मिल है** मगर मेरे पास वक्त नहीं हैं। इक्वेलिटी नहीं मिल रही है, मेरे पास वक्त नहीं है आपको बताने का, मगर मैं यह कह सकता हूँ कि उनको इक्वेलिटी नहीं मिल रही है। अपरच्युनिटी नहीं मिल रही है, बढने के लिए अपरच्युनिटी नहीं मिल रही है। हमारे लिए। हां, मैं यह कहता हूँ कि हिन्दुस्तान मे लिबर्टी ऑफ थॉटस है, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है, मैं इससे इंकार नहीं करता। फ्रीडम आफ रिलीजन है,मैं इससे भी इंकार नहीं करता, मगर मुझे डर है कि यह कब तक रहेगा। अगर यही अनासिर बढते रहे तो मुझे डर है कि यह कब तक रहेगा। अगर यही सब कुछ होता रहा, यही मिसइन्फारमेशन कम्पेन चलते रहे, तो मुझे डर है कि यह फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ वरशिप कहां तक रहेगा? आज है, मैं मानता हूँ क्योंकि जब तक आर्टिकल 25 और 26 इस कांस्टीट्यूशन में है, मुझे इस कांस्टीटयूशन पर भरोसा है, मुझे फेथ है कि मुझे मिलेगा लेकिन क्या यह हो सकेगा? हमारे मदरसों की तरह RSS के भी बहुत से स्कूल चल रहे हैं, हजारों की संख्या में चल रहे हैं, क्या हमने कभी कहा? क्या हमने कभी अंगुली उठाई। क्या कभी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने कहा कि RSS के स्कूलों में यह चीज हो रही है, फंडामेंटलिज्म वहां भी पढ़ाया जा रहा है। हमने कभी अंगुली नहीं उठाई, आप क्यों हमारी तरफ अंगुली उठाते हो?

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करुंगा। in Another decision which has b HI i taken is to have the National Action Plan for Human Rights. Now, what aption has been taken? There are 12 issues which have been

mentioned in the National Action Plan for Human Rights, यह बहुत जरुरी है। If we go through this, it is a laudable one हमें बच्चों को ह्यूमन राईटस सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे यह सीख ले तो कोई फंडामेंटलिज्म नहीं आएगा। ह्यूमन राईटस सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे यह सीख ले तो कोई फंडामेंटलिज्म नहीं आएगा। ह्यूमन राईटस के बारे में NCERT को कोई फिक्र नहीं है। ह्यूमन राईटस हम किस तरह से हासिल करें, हर नागरिक किस तरह से ह्यूमन राईटस हासिल करे, इसकी तरफ किसी की तवज्जुह नहीं है। आपकी तवज्जुह सिर्फ इस तरफ है कि हिस्ट्री को कैसे बदला जाए? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि नेशनल ऐक्शन प्लान फॉर ह्यूमन राईटस जो हैं, उसको किस तरह से आप ऐश्योर करेंगे, किस तरह से उसे प्रमोट करेंगें?

महोदय, मैं आखिर में यह बात कहना चाहता हूँ कि अब हमारा पूरा ध्यान हॉयर एजुकेशन की तरफ है। इसके लिए ऐलोकेशन भी देखना चाहिए। प्राईमरी एजुकेशन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भी 10+2 तक है, उससे ज्यादा नहीं है। अब हमारा पूरा ध्यान हॉयर एजुकेशन पर है। यहां यही बात हो रही है लेकिन आप गरीब बच्चों की प्राईमरी एजुकेशन को नैग्लैक्ट करके हॉयर एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हॉयर एजुकेशन होनी चाहिए, आप हॉयर एजुकेशन के लिए हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए और उसे ऐनकरेज कीजिए और उसे ऐनकरेज कीजिए लेकिन आप देखिए कि आज अगर एक बच्चे को प्राईमरी स्कूल में जाना है तो उसको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं but to get a B.A. graduation, he need not spend anything, मेरी आपसे गुजारिश है कि हॉयर एजुकेशन जो है, आप इसे self-sustaining बनाइए। हम IITS मे खर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज पर खर्च कर रहे हैं। आज ही एक अखबार में आया है कि हमारे बच्चे डाक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, आई.ए.एस. बनते हैं। यह पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि हमारे यहां के बच्चे MBBS डॉक्टर बनते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसी तरह से इंजीनियर बनते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं और वे सीधे कंपीटीटिव ऐक्जामिनेशन में चले जाते हैं। Even for llfvls and IITs, he will have to spend a lot. Give pay scholarships, like the dine which exists in the U.S. आप उनको फ्री लोन दीजिए क्योंकि प्रोफेशनल बनकर वे उसे वापस कर सकते हैं। You subsidise the loan. Give interest-free loan to those who want to take up higher education, say, in IITs. You give them interest-free loan. Treat it as a loan, but don't charge interest on it. Let the Government bear the interest portion. And, the rest of it, when he starts earning, let him pay in 15 or 20 years in instalments. Then, he will have the seriousness. Even at the time of selection of courses, he will realise, "I have to pay so much. I cannot waste my time. I will have to earn." He will then have a duty. Now, with what the State spends on educating one engineering-graduate student or one medical-graduate student, it can educate 500 children at the primary education level. That is important, or, one medical graduate, or, one NT graduate is very important. So, let them pay because there is no social obligation. *(Time-bell)* तो मैं यह चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब जब रिप्लाई देंगे तो …(**व्यवधान**)…

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):कांग्रेस पार्टी का पूरा समय आपने ले लिया, यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री के. रहमान खान:ऐसे ही होता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):आपके और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री के.रहमान खान: बस इतना कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): माननीय श्री एस.एस. अहलुवालिया। आपके दल का भी बहुत कम समय शेष है। कृपया समय कम लें।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर आज इस सदन मे चर्चा हो रही है। चर्चा के साथ बहुत सारे मुद्दे मेरे पूर्व वक्ताओ ने उठाए हैं और जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो शिक्षा की बात आती है। भारत आदिकाल से शिक्षा का केन्द्र रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जिस राज्य को बीमारु स्टेट में गिना जाता है उस राज्य से मैं आता हूँ, जो कभी एक दिन सारे विश्व में शिक्षा के कारण जाना जाता था और नालन्दा विश्व विद्यालय भी वहां था, विक्रम शिला भी वहीं थी और शिक्षा का एक केन्द्र था जहां देश-विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पर दुर्भाग्यवश जब हमारे मुल्क पर पहले हमलावर आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पूरी तरह से तहस-नहस किया। जो बचा-कुचा था उसको भी तहस-नहस करने की कोशिश की। उन हमलावरों के बाद व्यापारी के रुप में अंग्रेज आए ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के नाम पर और उन्होंने पुनः हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल डाला और जो शिक्षा प्रणाली हमें आजादी के साथ-साथ मिली उस शिक्षा प्रणाली में क्लर्क पैदा करने के स्कूल और क्लर्क पैदा करने के कॉलेज थे। मैंने अपना राजनीतिक जीवन छात्र आंदोलन से शुरु किया है और मैं समझता हूँ जहां तक शिक्षा की बात है...**(व्यवधान)**... डा.साहब, अगर आप मुक्त कर दें मंत्री जी मेरे सुझाव भी सुन ले।

सबसे बडी, सर्वोपरि शिक्षा मे जो चीज है वह है समाज मे नागरिकों के मॉरल वेल्यूज कैसे बढे। अगर मॉरल वेल्यूज उसके ऊंचे होते हैं तो मेरे पूर्व वक्ता ह्यूमन राइट की जो बात कर रहे थे और दूसरी बातें कर रहे थे तो इन बातों की चर्चा नहीं होती। दूसरी चीज की जरुरत होती है कि राष्ट्र-प्रेम की भावना कैसे जाग सके शिक्षा के माध्यम से , राष्ट्र के प्रति नागरिक कैसे समर्पित हो सके। ये दो चीजें मूलतः उसके साथ होनी चाहिए और तीसरी चीज जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आदमी अपना रोजगार कमा सके। पर दुर्भाग्य से पिछले 50 वर्षों में आधी सेन्च्युरी गुजर गई, हमने बहुत सारे कॉलेज खोलें, इंजीनियरिंग़ कॉलेज खोले, पौलीटेक्नीक खोले किन्तु आज भी नौजवान लोग अपनी डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं परन्तु उनको नौकरी नहीं मिल पाती तथा जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उस शिक्षा का उपयोग वे किसी नौकरी में नहीं कर सकते। मैं खुद एक बी.एस.सी. ग्रेज्युएट हूँ, उसके बाद मैंने वकालत पढ़ी। बी.एस.सी. करने के बाद मुझे कौन सी नौकरी मिल सकती है? और मैं नौकरी आज तक नहीं पा सका। अगर मैंने केमेस्ट्री में ऑनर्स किया होता तो शायद मैं केमिस्ट बन सकता था। किन्तु प्योर साईंस, मेथमेटिक्स, केमेस्ट्री और फिजिक्स पढ कर मैं क्या बन सकता था। मेरे लिए कोई एवेन्यू नहीं था।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): इसीलिए राजनीति में आ गए क्या?

4.00 p.m.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हां, वैसे लोग कहते हैं। बंगाल में एक कहावत है कि जिसकी कोई गति नहीं है वह वकालत पढ़ता है और जब वकालत नहीं चलती तो वह राजनीति करता है। पर दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, मेरे 14 पुरखों में कोई भी राजनीति में नहीं है। अच्छे घर से खाना-पीना मिलता है, उसके बावजूद देश प्रेम की भावना से मैं राजनीति में आया था और आज आपके सामने हूँ। महोदय, बडी साधारण सी बात है, बिना किसी खून खराबे के किसी सभ्यता को अगर समाप्त करना है तो उसका इतिहास बदल डालो। चीन का अपना इतिहास है पर उस इतिहास को सिमट कर रख दिया जब माओ-से-तुंग ने लाल किताब निकाल दी। उस रैड बुक से मोहित होकर नौजवानों ने दीवारों पर लिखना शुरु कर दिया, "चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, माओ-से-तुंग लाल सलाम" और एक नयी सभ्यता का उदभाव हुआ। मेरे कहने का मकसद था कि अगर किसी देश को कमजोर बनाना है, विभ्रांत करना है, पथभ्रष्ट करना है तो उसका इतिहास बदल डालो क्योंकि मनुष्य अपने इतिहास से ही अपनी रीढ़ की हड्डी मे ताकत पाता है और सीधा खडा होने का साहस करता है। अगर उसका इतिहास ही बदल दिया जाए तो सब कुछ बदल गया होता है। पढ़ाई लिखाई की जहां तक बात आती है तो मुझे रुबी मैनीकन की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा है कि, if you educate a man, you educate an individual; and if you educate a woman, you educate a family, अर्थात महिलाओ को शिक्षा देने से एक पूरे परिवार को शिक्षित किया जा सकता है। उसकी कमी हम लोगो के यहां रहीं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध की जा सके। मंत्री महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठाए हैं। अगर महिलाओं के लिए, बालिकाओ के लिए ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो सके, सिर्फ बीए या बीऐड की नहीं, उनको और तकनीकी-पॉलिटैक्नीक में भी, इंजीनियरिंग़ में भी, कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी में, आईटी में, हार्डवेयर में, सॉफ़्टवेयर में ,आर्टीटैक्चरल इंजीनियरिंग़ में अगर शिक्षा दी जा सके तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम और कोई नहीं होगा। महोदय, एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरह इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था और आज तक पढ़ाया जा रहा था, दुर्भाग्य से इस पर ख्याल नहीं किया गया। जब रहमान साहब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि शायद रहमान साहब ने वह इतिहास की पुस्तक नहीं पढ़ी जो उनके साथ साथ मुझे भी धक्का पहुंचाती है। महोदय, यह मध्यकालीन भारत की ग्यारहवीं कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक थी जो पढ़ायी जाती थी। इसमें मैं जिस सम्प्रदाय से आता हूँ, सिख धर्म से, उसके नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर ने जब कश्मीर के उच्च कुलीन पंडितों के जनेऊ उतारे जा रहे थे, बोदियां काटी जा रही थी, तिलक पोछे जा रहे थे और लोगों के धार्मिक अधिकार छीने जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने आकर दिल्ली सल्तनत औरंगजेब के सामने बैठकर धार्मिक अधिकारों के लिए तर्क-वितर्क किया और उसके लिए उनको शहादत देनी पडी। उसकी गवाही देने के लिए यहां वहां जाने की जरुरत नहीं है। लालकिले के सामने शीशगंज का गुरुद्वारा खड़ा है जो उस कुर्बानी का गवाह है। पर दुख उस वक्त होता है जब इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों मे लिखा कि गुरु तेग बहादुर एक लुटेरे थे।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Which historian wrote what? All that the book says is, "According to some sources of the then Government, like all Government bluffings..f//7terrjpf/bns;...this was also said. Also, the book

says that the Guru really defended the Hindus, the oppressed, and that he was a great man. *.(Interruptions)...* That is what the book says. *...(Interruptions)...* You can read that. *...(Interruptions)...*

SHRI S. S. AHLUWALIA: Have some patience, Eduardobhai.

SHRI EDUARDO FALEIRO: That is what the book says. You read the book.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am not saying that you have the influence of the Portuguese, because you are a pure Indian. You must read the history of Guru Teg Bahadur and his sacrifices. That reads the history book. उन्होंने इतना ही नहीं कहा। आज पूरी दुनिया में जहां-जहां सिख रहते हैं, सिखों की बात तो छोडिए, अभी कुछ वर्ष पहले जब पुनः कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तो कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरुद्वारा सीसगंज में मत्था टेककर अरदास करने आया कि हमारी मदद पुनः कीजिए और उनके बारे मे यह कहा जाए कि लुटेरे हैं। उस किताब को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उसमे एन.सी.ई.आर.टी. की तरफ से सुधार लाने की कोशिश की गई तो कहा गया कि इसका भगवाकरण हो रहा है। **...(व्यवधान)...** सरोज दुबे जी, मैं जब कांग्रेस की गई तो कहा गया कि इसका भगवाकरण हो रहा है **...(व्यवधान)...** सरोज दुबे जी, मैं जब कांग्रेस में था तब आप बाहर थीं। मैं इस सवाल को इस सदन में उठा चुका हूँ। इन्हीं के दुबेजी कि जनेऊ बचाने के लिए तो कुर्बानी दी थी और अब वही कहें कि नहीं मानते हैं तो फिर क्या करें?

श्रीमती सरोज दुबे:जनेऊ बचाने के लिए किसी की मदद की जरुरत नहीं है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया:दुबे जी के जनेऊ के लिए तो कुर्बानी दी थी और अब वही कहे कि नहीं, हमारे लिए नहीं दी, वे तो लुटेरे थे।**...(व्यवधान)...** यह किताब में लिखा है। किताब पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। आपको भी दे देता हूँ। मैं यहीं पर बैठकर कहता था।**...(व्यवधान)...**

श्री के.रहमान खान:इस तरह से दूसरे समुदाय के बारे में....

श्री एस.एस.अहलुवालिया: मैं सभी समुदायों के बारे में कह रहा हूँ।

SHRI K. RAHMAN KHAN : Let there be an objective and correct assessment of history. It should not be done from one point of view only. इसी तरह से दूसरे समुदायों के बारे में भी सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है।

श्री एस एस. अहलुवालिया: रहमान साहब सुनिए, मैं सही तरीके से ही बता रहा हूँ। फिर कहा गया-"तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते और मांस खाते थे ।" अब तमिल ब्राह्मण बताएं कि क्या मांस खाते थे और क्या मदिरा पीते थे?एक इतिहास की किताब यह है जो पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है और एक इतिहास की किताब जो हरी राम गुप्ता की लिखी हुई है, उसमें History of Sikhs में जो लिखा है, वह मैं पढकर सुना देता हूँ। अगस्त ,1787 में जब उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, उसके बारे में लिखा है। "In all the contemporary records, mostly in Persian, .written generally by Muslims, as well as by the Maratha agents posted at a number of places in North India, there is not a

single instance, either in Delhi or elsewhere in which the Sikhs raised a finger against women in circumstances where there was no external check on them. The Sikhs did not carry their women with them in their raids, दूसरी बात लिखी है-- The Sikhs were notorious drunkards जो सैनिक थे, वे शराब पीते थे और लोग कहते हैं - it is said, wine and woman go together. Even then, the Sikhs exhibited marvellous self-control and respect to womanhood. In this respect, no other soldier in the world stand any comparison with the Sikhs of those days, such were the *Khalsa* of Guru Gobind और ये यहीं पर खत्म नहीं करते, ये आगे भी कहते हैं। जो गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनके पिता का बलिदान हुआ, गुरुद्वारा रकाबगंज गवाह है जहां उनके शरीर का संस्कार हुआ था और गवाह है वह सरहद की दीवारें जहां उनके सात साल और नौ साल के बच्चों को दीवार में जिंदा चिन दिया गया था। यहां किताब में कहते हैं कि "नही" , उनकी गरदन काट दी गई थी"। सरहद की दीवारें गवाह हैं, बंदा बहादुर ने आकर उन सरहद की दीवारों की ईंट से ईंट खड़काई थी और उनके दो बच्चे जंग में शहीद हुए थे, उनके बारे मे लिखते हैं कि "वे एक सिख स्टेट की कल्पना करते थे"। ये वे गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो कुर्बानियां दी और देने के बाद दशम ग्रंथ में लिखते हैं। महोदय, इतना कुछ हो जाने के बाद वे ऐसा कहते हैं, 'मोतो परमपुरख का दासा, देखने आया जगत तमाशा। जो मुझको परमेश्वर उचरे है वो नरक कुंड मे परे है'।यह गुरु गोबिन्दसिंह जी की लिखी हुई बात है। हम अपने रोज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कभी किसी को समर्थन देना होता है, कुछ करना होता है, किसी का काम करा देते हैं तो कहते हैं कि मेरी पार्टी का फ़्लैग लगा लो, अपने घर के बाहर या मेरी फोटो लगाओ, उस पर तुम धूप बत्ती दिखाओ। ....(समय की घंटी)....

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**): आप कृपया समाप्त करें।

श्री एस.एस.अहलुवालिया:इस किताब में सिर्फ उन गुरुओं के बारे में ही नही है...

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**): काफी हो गया है, आपकी बातें आ गई हैं।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: जैन धर्म के बारे में भी है, लोग कहते रहे कि भारत में बीफ खाते थे। हिन्दू लोग बीफ खाते थे, ऐसी बातें लिखी गईं। जब इस पर परिवर्तन किया गया तो लगा कि आसमान टूट पड़ा है और प्रचार हुआ कि साहब ये भगवाकरण हो रहा है। सच को सच कहने की हिम्मत और सच को सही रुप में जनता के सामने पेश करने की हिम्मत...

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**): अब कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री एस.एस.अहलुवालिया:सरकार में नहीं थी और नहीं की। किस तरह से, कैसे वामपन्थियों से और वही वामपन्थी आज बुद्धदेव भट्टाचार्य श्याम बाजार के चौराहे पर पांच रास्ता, पांच माथा रोड़ पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्टेच्यू पर माला चढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमने आज तक अन्याय किया है जो इनको पहचाना नहीं है। रबीन्द्रनाथ टैगौर, जिसको कहते थे कि यह प्रेम के गीत गाता है, आज उसको सम्मानित करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुद रबीन्द्रनाथ संगीत के अपने बच्चों द्वारा गाए कैसेट डिस्ट्रिब्यूट कर रही है। ये गलतियां क्यों की? वामपन्थियों के कहने पर भारत ने पिछले पचास वर्षों में जो गलतियां कीं, आज उन पर सुधार

हुआ है। इसके लिए हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री बधाई के पात्र हैं और यह सरकार बधाई की पात्र है कि इन्होंने सही वस्तुस्थिति सामने रखी है और अपने राष्ट्र के जो हीरो थे या राष्ट्र प्रेमी थे, जिन्होंने अपनी जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी, उनके लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करके सही इतिहास को छात्रों के सामने रखा, इसके लिए धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): श्रीमती वंगा गीता, आप तेलुगू में बोलेंगी?

'SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Vice Chairman Sir for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Human Resource Development Ministry. This Ministry covers a wide range of areas. Many of my colleagues were speaking about education. Education includes basic education, UGC level education, technical education, higher education etc. The same way the Ministry looks after women and child welfare too. In this way -the Ministry covers a wide range of subjects including sports. But Sir, the most important among all these is education because it moulds the human being into a civilized citizen and thus becomes important in nation building process. This is how everyone feels that education is important. There have been many reforms in the field of education. Both the central and State Governments have introduced a number of schemes to improve the quality of education at every level. In particular the 'San/a Shiksha Abhiyan' or 'Education for' All' compaign launched by the Central Government is very useful especially in the construction of new school buildings.

Lately,-I had an opportunty to go through a report Sir. the report says that two hundred million students in the age group of 14 to I6yrs have enrolled in schools and among them only 120 million are actually going to school. This is the sum and substance of the report. It means that though a number of students join schools, many of them drop out. there are a number of schemes introduced by the Central and State Governments. In Andhra Pradesh Schemes like Malli Badiki (Back to school), Chaduvual Panduga (Festival of education) were launched. A Mid day Meal scheme has Jalso been introduced with the assistance of the Central Government, through this scheme the Andhra Padesh Goernment is able to provide food to lakhs of students everyday. For this programme the State Government is spending Rs.230 crores more, in addition to the funds allocated by the Centre for the purchase of rice, the main reason for the success of this programme is the role played by the Mother's associations/societies set up

*English translation of the speech delivered in Telgu.

for the this purpose. These societies are responsible for running the Midday meal schemes. There is a school committee formed, the President of which is the mother of one of the school studerits. This Committee sees that all the students enrolled cntinue their studies and the percentage of admission is stable.

Sir, if we look into the different schemes introduced through out the country, we find that there has been progress, if we compare, in 1950-51 there were 2 lakh 10 thousand primary students and in the year 2000 their number has gone up to 6 lakh 40 thousand, the number of upper primary students has increased by as many as 15 times. It was 13,600 in 1950-51, which went up to 1,90,000 in the year 2000. Sir, we have introduced a number of schemes to educate every child of our country. The State Governments have constructed a good number of school buildings with the financial support of the Centre. But there is still a need to construct many more school buildings. Sir, through you I request the Hon'ble Minister to increase the allocation of funds to states under the 'Sarva Shiksha Abhiyan' programme. If there are more schools, there will be more students.

Andhra Pradesh has already recruited 2 lakh teachers, in addition it has also appointed 60 to 70 thousand private teachers in order to ensure that there are enough number of teachers to teach all the subjects included in the curriculum.

But sir, what is lacking is the infrastructure. Especially the students of classes 8^{th} to 10^{th} have to face many problems. There are schools'where even benches have not been provided. The syllabus prescribed for'classes IX and X includes laboratory work. They have to do practicals. But the schools do not have properly equipped laboratories. There are no proper libraries. I request the Hon'ble Minister to see that there is an improvement in infrastructure of schools too. Andhra Pradesh has started 12 Urdu Schools in twelve districts of the State to accommodate Muslim Children. Along with the construction of more school buildings with improved infrastructure, we have to being about a change in our education pattern too. Sir, present day education makes a student eligible to participate in the competitive examination but is not training him to be a good citizen. This is my opinion. So, we should see that our education would also inculcate a sense of patriotism, and moral values among our students. We find that the present day students, by and large are loosing respect for elders and do inot have any love for the country. So, it becomes our responsibility to

cultivate moral values in them through education. These points should be considered while framing the syllabus and setting examination papers, the syllabus should always be relevant to the present day situations.

Sir, another important area relates to women and child welfare. Women constitute more than 60 per cent of total population in our country. The funds allocated for various programmes related to the welfare of women are encouraging but in sufficient. 40 to 45. per cent of total allocation should be earmarked exclusively for programmes related to women. We are encouraging the DWACRA (Organization related to Development of Women and Child Rehabilitation). We are creating self employment through the DWACRA organisations. We are making efforts to make them financially self-sufficient. A part from this e have to help women to be able to face the social and cultural problems. Even today we find women are suffering on account of dowry system. We should create a society where women can move forward independently and freely. Gender discrimination also persists in many places. You can find this discrimination prominently in many offices, educational institution etc. Proper-action is required to be taken against this discrimination.

In Andhra pradesh, Sir, eighty lakh people are engaged in there DWACRA Societies. 5,50,000 societies have been established. The Andhra Pradesh Government lay a lot of stress on the upliftment of women. Every scheme includes the participation of women. If residential flats are given they are in the name of women. A number of committees have been formed by women. Even in villages women are given very important positions and are entrusted with highly responsible jobs. Women need to be protected at every stage. As a child, an adolescent, a teenager, an adult, and also as an old lady she had to be provided with all facilities, so substantial allocation need to be made for the betterment of women, because if women are given the pride of place in society, which they deserve the country will prosper. As far as education is concerned. I have a suggestion to make to the Hon'ble Minister. Apart from elementary education, higher education and vocational training should also be given free of cost to women. This will result in more and more women being educated.

Sir, as far as Health and family welfare is concerned, there is lot of improvement in the infrastructure. We have all the modern equipment a large number of doctors and para Medical personnel to support. But in rural areas doctors are not available in hospitals and so people are unable

to have proper medical care. If we do not have healthy citizens, we cannot attain the development of society in the real sense of the term. So, health and nutrition are equally important. Sir, as far as health is concerned trioais are the worst affected. Medicines are not available for them, doctors are not available. If Panchayati Raj institutions are given the responsibility, they will be able to monitor and see that the tribal community gets all these facilities. Additional funds need to be allocated for this purpose. In villages medicine for a dog bite is not e.isily available, there is no proper medicine for rabies. An injection costs Rs.3C0 to Rs.500. since it is expensive the rural people prefer to die with pain rather than buy the injection. It is an important medicine, which should be made available in sufficient quality in villages in order to save the lives of rural peopie. Relatively more effective steps shouid be taken regarding family welfare programmes and Panchayati Raj institution should be entrusted with the responsibility of implementing them. Then they will take more pains tc see that doctors are available in the hospitals for people to have proper medical care. They would act as facilitators between the community and the doctors.

Lastly, I would like to make a mention of the food distribution though this belongs to the Ministry of agriculture. Food plays a vital role and is very important for the existence of a human being. Its distribution is being done properly. The worst affected are the weaker sections who are in dire need of nutritious food. They shouid not be neglected. If necessary rules and regulations should be amended immediately in order to facilitate proper food distribution to these sections. People should get nutritious food. So that they can lead a healthy life.

Sir, I request the Hon'ble Minister to consider all my suggestions. Thank you.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice Chairman, Sir, the development of a country depends upon the talent, intellectual skill and the ability of its people to rise to a level, which a country expects from its people. The skilled technological efficiency of our people; their scientific advancement, which is comparable with that of the world standard, and their devotion to the cause of our country will, certainly, take us on a par with developed countries of the world. Each and every person, born in our country, should be so moulded as to reach this level of expectation. In brief, the Human Resource Development Ministry must aim to achieve this end.

We are committed to provide free and compulsory primary education to all our children. It is more than half-a century since we achieved our Independence; still we have not been able to achieve any commensurate progress in thij vital field. We are committed to provide free and compulsory elementary education to all the children between the age group of 6 to 14 years. Primary education should be imparted in the Government Institutions, and they should have a uniform syllabus throughout the country. The State Governments and the Central Government should evolve a joint policy; since Education is in the Concurrent List, both should bear the burden equally, and joint monitoring should be done periodically. Up to the eighth standard, mother tongue should be the medium of instruction, and any other regional language, or, even English, should be taught only as a special subject. Now, the private institutions have developed a sort of mania for English as a medium of instruction. This Is not a healthy sign. This really neglects the rural poor people, who can never compete with the rich urban students. Learning subjects through a foreign language is Just like a married couple, who are living separately, a thousand miles apart, leading their family life over phone.

At high school and higher secondary levels, that is, from g"' to 12" standards, at present, it is oriented towards university education. The need of the present-day society is a comprehensive and integrated plan for improving the quality of school education. Vocational subjects should find a place in the curriculum. Two or three allied subjects like stenography, accountancy, computer application and other technical subjects should be included in the syllabus. Commercial subjects like accountancy, auditing, etc. should also be taught. For all these, practical training should also be given. Having infrastructural facilities must be the precondition for starting such schools. Let the NCERT be given a free hand to evolve a useful integrated system for school education. The NCERT has experimental, research and developmental wings at its command. At this stage, every year, nearly 60,000 software engineers and Diploma holders are produced in our country, of which 25,000 accounts from Tamil Nadu. To create employment opportunities, the then Tamil Nadu Government planned for tidal parks at Chennai and the same was inaugurated by our hon. Prime Minister in the year 2000. The then Chief Minister announced at the inaugural function itself, " Tidal phase II and III are planned" but that has not materialised till now. I request the Central Government to see that the innovative scheme is implemented. The Scheme of the then Tamil Nadu Government to impart computer education in all high schools has to be

completed. To start with, the then Government started hundred high schools. It has to be completed now.

Moreover, university is regarded as a temple of devotion to the advancement of higher learning. Since the days of our ancient universities of Nalanda, Taxila and Vikramshila, our country has undergone a lot of changes; therefore, the style of education has also to be changed. We have raised the number of universities, that is, from 19 at the time of Independence in 1947 to 219 in 1997, in a period of 50 years. The quality of higher education has to be preserved at any cost. In this connection, I wish to bring to the notice of the Government the answer given by the hon. Minister for Human Resource Development on 7.8.2001 to a Starred Question No. 221 on the floor of the Lok Sabha, and I quote, "The University Grants Commission has identified 19 fake universities functioning in the country." See what kind of havoc they have played with our youngsters. Such kind of criminal activities should be dealt with severely.

In recent years, India seems to be undergoing a revolutionary change in higher education. If the take-off is in the right direction, we can welcome the same, but, unfortunately, the take-off is in the wrong direction. Thousands of spurious colleges and dozens of spurious universities, without minimum infrastructure and resources, have sprung up like mushrooms, despite the existence of monitoring mechanisms like the U.G.C., AICTE, the task force of the Government and all powerful committees of the Universities. These are responsible for maintaining education standards. Some of the private technical colleges are minting money and they are run as an industry of profit. By all means, this should be put an end to by the State and the Central Governments, with full coordination and understanding. All the engineering colleges and other technical colleges should have industries and factories of their own. The courses should be limited to such a level that the students studying there should be trained in their factories, to be trained in such a way that the outgoing students must be competent to work in factories, or, start their own industries, instead of seeking white-collar jobs. The existing private engineering colleges be advised to start industries to cope up with the norms prescribed. After two years of theoretical classes, all the students should be given apprentice training for two or three years in their industries itself.

The Industrial Revolution of the I8^{lh} Century in England created a great demand for skilled engineers. *(Time-bell)* Sir, I will just finish. The

engineering colleges in England started courses with less theoretical syllabus, and more practical training and apprenticeship in a factory was a part of the course. It was highly successful to meet the situation in the 18* Century. This kind of education has to be adopted with regard to the technical education in our country also. Recently, the Railway Ministry has adopted a system of informal education for their mechanical engineers in their cadre. Some ordnance factories have also adopted similar informal education for their staff. Our graduates are more theoretical than practical. That is why entrepreneurship scheme has failed miserably. They need practical training, which shapes and builds their confidence necessary for success.

The National Policy on Education was evolved in May, 1986. After a comprehensive appraisal of the then existing scenario of education, this was published in about 14 languages for a national debate. The National Policy on Education was unanimously passed by Parliament.

Presently, the Ministry of Human Resource Development is under the able guidance and leadership of our great scholar and scientist, Dr. Murli Manohar Joshi. Now,- he has to lead the country in this direction, which I mentioned above. The challenge before us is to plan for education towards human resource development from a holistic perspective for nation building in our pluralistic secular society. Let all of us contribute our might for this noble cause under the leadership of eminent scholar, Dr. Murli Manohar Joshi.

With these words, Sir, I conclude. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): माननीय श्रीमती सरोज दुबे। दुबे जी, थोड़े ही समय में, गागर मे सागर भर दीजिए। पांच मिनट हैं आपके पास, गागर मे सागर भर दीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे: कोशिश करुंगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस समय हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्य-निष्पादन पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय बदलते हुए समय के साथ कई आयामों को तय करता हुआ मानव संसाधन के स्वरुप में ढल चुका है और एक महत्वपूर्ण विभाग बन चुका है। यह बहुत ही वृहत मंत्रालय है। देश का चहुमुखी विकास, मानव संसाधन के सुनियोजित विकास पर निर्भर करता है। मानव संसाधन विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है क्योंकि शिक्षा मानव जीवन को सुसंस्कृत करने का दायित्व निभाती है। महिला एवं बाल कल्याण मातृत्व सुरक्षा तथा राष्ट्र के बचपन को संवारने के साथ-साथ नागरिकों के चरित्र के गठन के लिए भी प्रयास करता है और खेल विभाग में , स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की प्रक्रिया को

क्रियान्वित करते हुए विश्व के परिदृश्य में अपनी प्रतिभा के अनुसार देश के महत्व को बढ़ाता है, गौरव को बढ़ाता है। यह इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि इसकी जरा सी तनिक सी भी लापरवाही, तनिक भी नादानी, तनिक भी उदासीनता देश के बढते हुए कदम को लड़खड़ा सकती है। माननीय जोशी जी शिक्षा जगत से जुड़े हैं और मानव संसाधन मंत्रालय के महत्व को और उसकी बृहत्तता को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डा.जोशी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, सरकार का एजेंडा न लागू करके आर.एस.एस. का एजेंडा, संघ परिवार का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है और हमारे देश के तमाम प्रतिष्ठित, शैक्षणिक संस्थानों पर एक खास विचारधारा के लोगों का कब्जा होता चला जा रहा है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान से जुड़े सभी स्थानों का भगवाकरण किया जा रहा है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुविख्यात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त इतिहासकार किसी पार्टी, किसी दल के नहीं हुआ करते हैं। वे देश की धरोहर होते हैं। उन पर भी सुनियोजित ढंग से हमले किए जा रहे हैं।

महोदय, शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिससे देश का विकास जुड़ा है। इसीलिए समय-समय पर शिक्षा की महत्ता को देखते हुए अनेक समितियां और आयोगो का गठन किया गया और उनसे बड़े-बड़े मनीषियों के नाम जुड़े हैं। डा. संपूर्णानंद , डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा. दौलतसिंह कोठारी और आचार्य सममूर्ति जैसे लोगों ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इन सभी ने संविधान मे निहित उन भावनाओ को उजागर किया है कि शिक्षा में सभी को समानता के अवसर मुहैया कराने की दिशा में लगातार प्रयत्न होने चाहिए। हर, बालक की चाहे उसकी आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में समानता के अवसर पाने का मूलभूत अधिकार है। स्वतंत्र भारत मे एक भी बच्चे को इससे वंचित रखना क्रूरतापूर्ण होगा।

महोदय, आज हमारी शिक्षा अमीर और गरीब के बीच में बंट चुकी है। भारत में 5 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं जिनका कोई घर-बार नहीं है, जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। इन बच्चों को विकलांग बनाकर भीख मंगवाने वाले ठेकेदार उनसे भीख मंगवाते हैं। इसी तरह बाल मजदूरी की संख्या एक करोड़, तेरह लाख आंकी गई है। महोदय, 93वें संशोधन का बड़ा शोर मचा, बड़ा हल्ला मचा कि अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा। मैं उस समय भी कह रही थी कि यह एक सम्मोहित करने वाला नारा है और वही हुआ। अब साल से भी ज्यादा निकल गया है लेकिन कही कोई सुधार नहीं हुआ, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, सब कुछ जैसे का तैसा चल रहा है। सड़कों पर रहने वाले बच्चे आज भी उसी प्रकार से घूम रहे हैं। यह जो एक सुंदर कल्पना थी कि वर्ष 2003-2004 आते-आते ये बच्चे सुबह-सुबह यूनीफॉर्म पहनकर, बस्ता टांगकर,पानी की बोतल लेकर स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे, वह सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

महोदय, वास्तविकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा के वजट मे और कटौती कर दी गई है। वर्ष 2002-2003 में इसके लिए 9,861करोड़ रुपए दिए गए थे लेकिन वर्ष 2003-2004 में इसके लिए 9,751 करोड रुपए दिए गए। इसकी वृद्धि दर पहले 2.39 थी, वह घटकर 2.28 हो गई। दोपहर का भोजन देने की घोषणा इसलिए की गई थी ताकि इसके लालच ने गरीब बच्चे स्कूल में आएंगे लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई। सर्व शिक्षा अभियान को भी झटका देने से यह सरकार बाज नहीं आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए 7,096 करोड़ रुपए की मांग़ की थी जिसमें दोपहर के भोजन के लिए 1,600 करोड़ रुपया मांगा गया था तथा सर्व

शिक्षा अभियान के लिए 2,200 करोड़ रुपया मांगा गया था लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के लिए मात्र 1,951 करोड़ रुपए मिले जो कि विगत वर्ष के बजट से केवल 439 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह दोपहर के भोजन के लिए, 1,175 करोड़ रुपए मिले जो कि पिछले साल के बजट से केवल 118 करोड़ रुपए ज्यादा है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, हालांकि वह असफल हो गया था लेकिन फिर भी विद्यालयों में उपकरण और तमाम सुविधाओं को दिलाने वाला था, उसको जीरो कर दिया गया।

महोदय, जिला प्राथमिक शिक्षा के बजट मे भी कटौती कर दी गई। मौलिक शिक्षा को लागू करने के लिए 40,000 अध्यापकों की भर्ती होनी थी लेकिन उसके बजट में कटौती हो गई। स्कूलों के लिए भवन बनाए जाने हैं , उपकरण लाने हैं, तमाम स्कूलों में कुर्सी –मेज की व्यवस्था करनी है लेकिन बजट मे कटौती होने से ही हमें अंदाजा हो गया कि इस सरकार की नीयत क्या थी। केवल एक हल्का-फुल्का नारा लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का रुप दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार शिक्षा के लिए कितनी गंभीर है। संसाधनों की कमी के नाम पर वह पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप देना चाहती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव में एक तरफ जहां उच्च शिक्षा को व्यावसायिक घरानों को सौंपने की तैयारी हो रही है, वही प्राथमिक शिक्षा को 6-14 वर्ष के दायरे मे समेटकर, 0-6 वर्ष के नौनिहालो को दिवालिया राज्य सरकारो और साधन-विहीन निर्धन माता-पिता के हवाले करके सरकार अपने दायित्वों से निवृत्त हो जाना चाहती है।

महोदय, वास्तविकता यह है कि आंख खोलने के साथ ही बच्चा कुछ सीखना चाहता है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि वह मां जो दिन भर खेतों में खटती है,जो दिन भर मेहनत करती है और रात को घर के कामकाज करती है, उसके हवाले एक जाग्रत बच्चे को छोड़कर ये क्या सिखाना चाहते है और उस मां से वे क्या उम्मीद रखते हैं? वह मां उस बच्चे को 6 साल तक क्या सिखाएगी? यह 6 साल तक के बच्चों को किसके हवाले कर दिया गया है? हर कोई जानता है कि लाखों गांवों में स्कूल नहीं है। स्कूल हैं तो मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो किताबें नहीं हैं। आप स्कूलों की बिल्डिग को तो देखे कि कोई उसके दरवाजे को उखाड़ कर ले गया है। कोई बकरी बांध रहा है, कोई भैंस बांध रहा है। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ रहे हैं। मौसमी स्कूल चल रहे है। अगर पानी बरस गया तो बच्चे उठ कर भाग जाते हैं। अध्यापकों की भारी कमी है। एक कक्षा कक्ष मे तीन-तीन क्लास लगती है। एक ही मास्टर पढ़ाने वाला होता है और हम यह उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं, उत्तम नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अध्यापक को 40 बच्चे पढ़ाने चाहिए वहां उसे 80-80 बच्चे पढ़ाने होते हैं। अगर कहीं स्कूल चलता भी है तो मास्टर लोग पढ़ाते नहीं हैं, वे दो सौ रुपए मे किसी बेरोजगार नवयुवक को टीचर रख देते हैं, खुद पौलिटिक्स करते हैं और वे बेरोजगार नौजवान वहां बैठ कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर यह मौलिक अधिकार बनाने का ख्वाब दिखाया गया था इस देश को, परियों की कहानी सुनाई जाती है कि बस ख्वाब देखते रहो और उसी मे घूमते रहो और जब वास्तविकता, धरातल की जमीन पर हमें ...(समय की घंटी)... क्या हुआ सर, बस दो मिनट।

6 से 14 साल तक के सवा चार करोड़ बच्चों ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा।

प्रो. रामबरुश सिंह वर्मा(उत्तर प्रदेश): बिहार में यही सब कुछ हो रहा है।

श्रीमती सरोज दुबे: आप अपने उत्तर प्रदेश मे झांक लीजिए न। बिहार में तो बच्चों के साथ हो रहा है पर उत्तर प्रदेश मे तो बूढ़े, जवान, बच्चे सब के साथ भारी जुल्म हो रहा है। अपने गिरेबान मे झांक कर तो देखिए। बिहार मे तो चरवाहा विद्यालय चल रहे हैं। आपके यहां का भूखा बच्चा तो सड़क पर कोयला बीन रहा है, होटलो और ढाबो मे मार खा रहा है। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप। आप हमको बोल लेने दीजिए।

36 करोड़ गरीब परिवारों में बच्चा पढने के लिए नहीं बल्कि दो हाथ लेकर कमाने के लिए पैदा होता है। इसलिए इस देश मे शिक्षा को जो मौलिक अधिकार बनाने की बात की गई है वह बहुत भुलावा देने वाली बात थी। सर, वर्तमान केन्द्रीय सरकार अम्बानी, बिरला, विश्व बैंक के रिमोट से चलने वाली सरकार है। इसी कारण डा. सम्पूर्णानन्द जैसे शिक्षा शास्त्री के देश मे प्रयग से गुजरते हुए शिक्षा जगत मे डेढ दशक के बाद फिर से एक नई शिक्षा नीति की जरुरत महसूस की गई तो दो बड़े उद्योगपति मुकेश अम्बानी और कुमारमंगलम बिरला की अगुवाई मे समिति गठित की गई। "पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन" शीषर्क से इन पूंजीपतियों ने रिपोर्ट तैयार कर दी। अगर आप रिपोर्ट को समग्र रुप से देखे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उदारीकरण के तहत शिक्षा जगत को निजी हाथों में सौंपने की पूरी वकालत की गई है। वैसे प्राथमिक शिक्षा को भी निजी हाथों मे सौंपने की पूरी स्थिति बना दी गई है। साधन विहीन स्कूलों के साथ-साथ जो निजी स्कूल सुविधा सम्पन्न खोल दिए गए हैं उसके कारण सरकारी स्कूल अपने आप ही बैठ जाने वाले हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि शिक्षा को बाजारोन्मुखी बनाया जाए ताकि निजी क्षेत्रों मे विकास हो सके, उसे पूरी तरह से बाजार के हवाले कर देने का संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कम करने और आत्म-निर्भर बनाने पर ही जोर दिया गया है और यह कहा गया कि 2015 तक कुल पढ़ने वाले 45 करोड़ बच्चों मे से केवल 11 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा के लायक होंगे जिससे 20 करोड़ बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगें। नतीजा यह होगा कि केवल उच्च वर्ग के साधन सम्पन्न लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और गरीब सुविधा से वंचित रह जाएगा। उद्योगपतियों से इससे ज्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। सरकार के शिक्षा सलाहकार सरकारी अधिकारी हैं। जब कोई कमेटी बनेगी तो उसमें उद्योगपति को बैठा दिया जाएगा। तो शिक्षा का यही हश्र होना है। शिक्षा निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। एक तरफ तो पेड़ के नीचे पढ़ने का प्रयास करता और पानी की एक बूंद को तरसता हुआ हमारा ग्रामीण छात्र और दूसरी ओर फुली एयरकंडीशंड-सम्पूर्ण रुप से वातानुकूलित स्कूलों में पढने वाले बच्चे। एक तरफ बच्चा पेड़ के नीचे पैदा होता है नाले के बगल में पलता है और दूसरी तरफ एयरकंडीशंड अस्पतालों मे पैदा होता है तथा बंगलों में पलता है। यह भेद यह सरकार न मिटाना चाहती है, न उसकी कोई नीयत है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि देश में असंतोष व्याप्त होता चला जा रहा है। शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में हमारी सरकार का यह वायदा था कि 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का खर्च करेगी। लेकिन यह चार परसेंट भी पूरा खर्च नहीं कर रही है। यह इन लोगों का हाल है। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा के मद में जहां पिछले बजट मे 1.698 और .08 करोड़ आवंटित किया था इस वर्ष उसको घटा दिया गया है। महोदय, सालों के प्रयास के बाद हम वैज्ञानिक जगत में अपनी धाक जमा पाए थे। आज एक बार फिर से ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमें उन्हीं नक्षत्रों की दुनियाओं में भेजा जा रहा है जहां पर अपने प्रयास या आपके प्रयास को भाग्य का खेल और नक्षत्र का खेल कह कर इस दुनिया को भरमाना चाहेंगे। पिछड़े

कुछ साल से स्कूली पाठ्यक्रम मे इतिहास को गलत तरीके से पेश करने को लेकर अखाड़ा खुल गया है। आज स्कूली शिक्षा भ्रम के दोराहे पर खडी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब कृपया समाप्त करे।

श्रीमती सरोज दुबे: स्कूली शिक्षा विसंगतियों से जूझ रही है। सूचना तकनीक के विस्फोट ने बच्चों को तार्किक बना दिया है, मुखर बना दिया है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टीकल मे लिखा गया है कि "कंटैम्परेरी इंडिया" जो एन.सी.ई.आर.टी. की नयी किताब है, उसमे हिटलर को हीरो बनाया गया है। जिन्ना ने जो गांधी जी के बारे में कहा, उसका तो विवरण उसमे दिया गया है लेकिन जो सावरकर और गोलवरकर ने गांधी जी को ऍटी हिन्दू कहा, उसके बारे मे कुछ भी नहीं किया गया। इस प्रकार से ये ऐसी भावना पैदा कर रहे हैं कि हमारी स्मृति मे हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, उसको बदलकर, उसका भगवाकरण करके गोलबरकर और सावरकर –इन लोगों को बिठाकर वीर सावरकर के नाम पर उन्हें सदन मे तो प्रवेश करा लिया है-इस देश में भी उन्हीं को बैठाना चाहते हैं। यह सोच देश को पता नहीं कहां ले जाएगी? हमारी देश को धर्म के नाम पर दिन-रात बांटने की जो साजिश चल रही है, वह बहुत गलत है। एन.सी.ई.आर.टी. का रवैया बिल्कुल तानाशाहपूर्ण हो गया है, वह जो चाहता है, कर रहा है। पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल रही हैं। शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाता है। उसमें चाहे सर्वसम्मति हो या न हो, लेकिन **एन.सी.ई.टी. अपनी मर्जी को जबर्दस्ती लागू करना चाहती है। इसको** अतिरिक्त एन.सी.ई.आर.टी. की जो किताबें आयी हैं, वे पाठ्यपुस्तकें मार्केट मे नही मिल रही हैं और जो मिल रही है, उनमें भी प्रूफ की गलतियां हैं और तथ्यों की भी गलतियां हैं। आज का बच्चा जो स्कूल मे पढना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वह गलत प्रूफ की किताबों, गलत तथ्यों की किताबों को पढकर किस प्रकार का नागरिक बनेगा और इस प्रकार के नागरिकों से देश कैसे आगे जाएगा, यह एक बड़ा भारी प्रश्नचिन्ह है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया आसन ग्रहण करें।

श्रीमती सरोज दुबे: महोदय, दो मिनट के लिए केवल महिलाओ के संबंध मे कहना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण वर्ष आया और एक गरम झोंके की तरह हमे झुलसाता हुआ निकल गया। बहुत सुंदर-सुंदर नामों से सुस्ज्जित कर योजनाएं चलाई गयीं कि महिलाओ को स्वावलंबी बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार की लापरवाही का नतीजा देखिए कि जिस "राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम" के लिए वर्ष 1999 और 2001 के प्रत्येक वर्ष में 160 करोड रुपया तथा 2001-2002 में दस करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान था योजना के लागू न किए जाने के कारण उपयोग नहीं हो सका। यानी एक तरफ तो महिलाएं रोजगार पाने के लिए सिसक रही हैं और दूसरी ओर इनका बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से मेरे पास और कई उदाहरण हैं। इसके साथ-साथ माचिस, पटाखा जैसे खतरनाक उद्योंगो मे 88 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं काम कर रही हैं जो अशिक्षित हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के कारण वे शिक्षा नही ले पाती हैं। आई.सी.डी.एस. का जो हाल है, अगर डिसटैंस ऍजूकेशन शुरु हो गयी तो आइ.सी.डी.एस. जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में काम कर रहा है, वह बंद हो जाएगा। कम्प्यूटर की बात आप करते हैं। गांव में बिजली नहीं है, साधन नहीं है और ये कम्प्यूटर की बात करते हैं। पौष्टिक आहार की भी यही स्थिति है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि आपका मंत्रालय बहुत वृहत है और देश के विकास, देश को जोड़कर रखने की, देश के अंदर एक सुयोग्य और अच्छे नागरिक बनाने की

पूरी जिम्मेदारी मानव संसाधन मंत्रालय पर है इसलिए कृपया पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर आप देश के हित में सोचिए और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करें ताकि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो और हम अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कर सकें और उससे प्रेरणा लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ...(समय की घंटी)... हम यह नहीं कहते कि इतिहास को लेकर हम अपनी गौरव गाथा गाते रहे। हम आने वाले दिनों में इस मंत्रालय से उम्मीद करेंगे कि देश हित में यह काम करेगा, पार्टी के हित में नहीं।

श्री गांधी आजाद (**उत्तर प्रदेश**): धन्यवाद महोदय, सबसे पहले मैं माननीय कलराज मिश्र जी को बधाई दूंगा इतने महत्वपूर्ण विषय को यहां चर्चा मे लाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में मनु विधान व्यवस्था को उद्धृत करना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत "स्त्री शूद्रो ना ध्यताम्" को चरितार्थ किया गया और जिसका परिणाम आज भी डायरैक्ट और इनडायरैक्ट किसी न किसी रुप में दिखाई देता है। महोदय, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्यादात्री सरस्वती देवी की अमवरत् आराधना के बाद भी सबसे ज्यादा निरक्षरता हमारे देश में है। यदि शिक्षा और सुविधा सारे लोगों को मुहैया कराई गई होती तो इस देश में बहुत सारे लोग पंडित जवाहर लाल नेहरु, डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस बन जाते लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा और सुविधा के अभाव में सारे नौनिहाल मात्र हलवाई और चरवाहे बनकर ही सिमट गए।

महोदय, भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के बारे मे व्यवस्था दी थी कि-

> "राज्य इस संविधान के आरंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर ही सभी बालको को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा"।

लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड रहा है कि 51-52 साल तक इस तरफ अनदेखी की गई। मैं अपनी तरफ से इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 पास कराकर छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का काम कम से कम इनकी सरकार और इनके द्वारा किया गया लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर आज शक उत्पन्न होता है क्योंकि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में, जहां पांच करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते,सन 2005 तक उन्हें शिक्षित करने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। वैसे माननीय मंत्री जी ने 2010 तक इस देश से निरक्षरता भगाने का अभियान चलाया है लेकिन इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम की जरुरत है।

महोदय, सामाजिक रुप से जागरुक और साक्षर समाज की लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निरक्षरता का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय चिंतन रहा है। किंतु इस चिंता का निदान क्या हुआ? आज बिहार मे साक्षरता की दर 47.53 प्रतिशत है। उसी के आस-पास उत्तर प्रदेश की भी हालत है और इतना ही नहीं, 2001 मे कुल शिक्षा 65.38 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि 2001 में भी 34.82 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। अनुसूचित जाति में 53 प्रतिशत साक्षर लोग हैं और 47 प्रतिशत आज भी निरक्षर हैं। अनुसूचित जनजाति में 49 प्रतिशत साक्षर लोग हैं और आधे से अधिक 51 प्रतिशत निरक्षर हैं।

5.00 p.m.

महोदय, शिक्षा व्यवस्था की दोहरीकरण की नीति के कारण तथा शिक्षा के क्षेत्र के निजीकरण के कारण भी शिक्षा क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ रहा है। आज शिक्षा मे जो विषय पढाए जा रहे हैं, उसमे भी भ्रम पैदा करने की बात की जाती है।प्राथमिक विद्यालयों में गंगा नदी को ब्रह्मा के कमंडल से निकाला गया है लेकिन वही विद्यार्थी जब आगे की कक्षाओ में जाता है तो गंगा को हिमालय पर्वत के गंगोत्री स्थान से निकाला जाता है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश मे दो गंगा हैं या सचमुच गंगा के निकलने का क्या स्थान है, सारे पाठ्यक्रमों मे एक होना चाहिए। आज भी इसी तरह के अनेक भ्रमित तथ्य स्कूलों में पढाए जाते हैं। मेरी समझ मे उन्हें पढ़ाने से कोई लाभ नही है। महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के संबंध मे सरकार ने काफी प्रयास किया है। इन समुदायों के बाहुलता वाले क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर शैक्षिक संस्थान खोलने का प्रावधान, छात्रवृत्तियों का प्रावधान, शिक्षण शुल्क की माफी...(समय की घंटी)... मध्याह्न भोजन, निःशुल्क वर्दियां, पुस्तकें, लेखन सामग्री शैक्षिक संस्थाओं की सीटो पर आरक्षण देने का उपाय किया है। लेकिन इनके क्रियान्वयन के ढंग को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 109 विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोष्ठ स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति लागू करने के लिए आरक्षण समिति बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि कुलपति सहित प्रोफेसर, रीडर आदि मे भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। महोदय, हमारी शिक्षा आज अमीर और गरीब के बीच में बंट गई है। इस असमनता के कारण एक वर्ग के हाथों में अवसर सिमटते जा रहे हैं। शिक्षा बाजार के हाथों में खेल रही है जो ठीक नहीं है। इस पर अंकुश लगाने की जरुरत है। माननीय मिश्र जी ने अपने वक्तव्य में एकलव्य का जिक्र किया था। महोदय, मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे द्रौणाचार्य, बहुत सारी संस्थाओं मे पैदा हो गए हैं जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजातियों रुपी एकलव्यों को उनके अंक कम करके, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करके, उनके साथ एकलव्य का अंगूठा काटने का काम करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम इस लोकतंत्र में अब एकलव्य का अंगूठा काटने वाला द्रौणाचार्य पैदा न हो। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):कुमारी मैबल रिबैलो आप थोड़े समय मे अपनी बात कहने की कृपा करे।

कुमारी मैबल रिबैलो (मध्य प्रदेश): महोदय, कितना समय है, मैं उतने समय मे ही अपनी बात बोलूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): पांच मिनट हैं।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मैं पांच मिनट में क्या बोलूंगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक):आप सात मिनट बोल लीजिए।

MISS MABEL REBELLO : Thank you, Sir. Hon. speakers before me have spoken on various aspects of education in our country. In the first instance, you allowed me to speak only for five minutes. But on my request to increase the time a little bit, with your gracious attitude, you said, "Okay; you can speak for seven minutes." So, at the very outset, I would like to thank you for that.

Sir, I would like to speak just on a few things, that is, first on the elementary education and then on the higher education and on the mid-day meal and, maybe, something on Self-Help Groups concerning women. Sir, in today's globalised world, where distances have crumbled, we live in a global village, knowledge generation has become very important" One who dominates in the knowledge generation, will also dominate in the economic, military and social terms as well. We see it all over the world. For knowledge generation, education is critical. All the three levels of education, whether it is elementary, secondary or collegiate, are definitely critical and must be given top national priority. But, what is happening in our Budget? The countries, which became independent along with us like Korea, Malaysia, Singapore, they had a title of Asian Tigers. How did they achieve this title? It is because of their economic superiority. From where did it come? It is because they spent a lot of money on education, 10 per cent of their Budget on education right from the day one of their independence. They have faith in human resource. Take the case of Singapore. It doesn't have any natural resources, but they spent on human resource and enriched their human resource, and today they can claim to be a superpower. But what have we been during over the last 50-5.5 years? We have been spending hardly 3.5 per cent of our GDP on education and, as a result of that, 50 per cent of our people are still poor, though these people would say only 30-35 per cent of our people are poor. In absolute terms, I think, 50 crores of people are Below the Poverty Line. They don't have even a proper meal today. Then, how do you expect them to go to school? How do you expect them to be robust? How do you expect them to contribute to the nation building? It is not possible. Therefore, I request the hon. Minister, Dr. Murli Manohar Joshi - he is supposed to be in the inner core of the NDA - to prevail upon the hon. Finance Minister and the Prime Minister and ensure that, at least, six per cent of our GDP is allocated for education. He brought forth a Bill six months ago to make elementary education compulsory. What is happening to that? He had asked for an amount of Rs. 7,800 crores to make the Sarva Shiksha Abhiyan a success. Has he got that amount? Not at all. He is getting an amount of Rs.-4,800

crores. So, will he get this amount of Rs.3,000 crores to bridge this gap and ensure that the Sarva Shiksha Abhiyan becomes a success? Can he tell us that? I don't know. If you put a question to him here, he has always an answer. But why is he not able to prevail upon the Finance Minister and the Prime Minister and get adequate money to ensure that the Sarva Shiksha Abhiyan, which is a glamorous term, becomes realty a success so that the future generation of India becomes really enriched people? He is not doing that. Why is he not doing that?

Similar is the case with the Mid-Day Meal Scheme. It was introduced in 1993-94, when the Leader of the Opposition was the Finance Minister. But these people neglected it. Now, the Supreme Court has given directives to ensure that the Mid-Day Meal Scheme is implemented in all the States of India. In spite of that, it is not being implemented. Recently, as you are aware, the FCI refused to give grains for the Mid-Day Meal Scheme because they have not paid an amount of Rs. 500 crores TO the FCI. Their yearly requirement of Mid Day meals is Rs.1,700 crores. The allocation is Rs.1,175 crores. There is a deficit of Rs. 500 crores. If you have a deficit Budget, how do you ensure the implementation of the Mid-Day Meal Scheme and every-child gets the meal? The idea of Mid-Day Meal Scheme is to give the poor children a meal, not only to attract them to the schcoi but also to ensure that they are physically robust. But it *<s* never done. These are all false promises. They make promises. When they go to the dais and pulpits, they speak very well. When it comes to actualisation of programmes, all are half-baked programmes. I request the hon. Minister of Education, who is sitting here, who is supposed to be a very important person in the NDA, to ensu[r]e the fulfilment of the promises that he has made in the House so that the future generation may thank him. Otherwise, a time will come, when the future generation will Le cursing him. Let him remember that. *...(Interruptions)...* Yes, I, of course, do that. I need not say that.

Comjng to higher education, why are we speaking about higher education? What is happening in higher education today? Adequate funds are not allocated for higher education and because of that we do not have labs, libraries and classrooms. Our teachers are not being paid well. Sir, speakers before me have been speaking about capitation fee. In our own country today we have got 1,100 engineering colleges churning out approximately four lakh students. We must be having three - four thousand other science and arts colleges and we must be bringing out, at least,

millions of students as graduates. But what is the quality? These colleges don't have buildings, they don't have libraries. *(Time-bell)*

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): बोलिए। वैसे सात मिनट हो गए।

कुमारी मैबल रिबैलो: बस, क्या सर, अभी तो मैंने बिल्डअप किया। आप तो मेरा टेंपो ही खत्म कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): सात मिनट हो गए।

MISS MABEL REBELLO: So, when it is like that, what will happen? Today, the Government medical and engineering colleges, 30 per cent of them, do not have staff. Why is it? Is it because our colleges do not bring out quality employable people? Besides those who are doing very well, they want to go abroad. Why is that? We have been spending on our students. What are we doing? If we do not have the money, then, allow education for the privileged and give scholarships for the poorest of the poor, for the needy, give them the scholarships. Don't give' scholarships to the students of universities like the JNU. In JNU, the well-off students also pay Rs. 15 per month. What is this mockery? You charge those who are well-off, those who belong to upper-middle class and middle class and can afford to pay. You give scholarships to the poorest of the poor. Give them free education in good colleges. You change your system. Why are you carrying on the same type of system for the last fifty years? I just dc not understand.

What happens in the advanced countries is that people spend on research. Here in our country, people hardly do research. Nobody wants to go in for research, because they are not adequately paid. All right, at least, pure research should be funded by the Government. For the applied research, you ask the corporate sector to fund them. Give the corporate sector some sort of tax concession and encourage them so that, at least, they conduct the applied research. Otherwise, what will happen to this nation is that we will always remain *chamchas* of other countries; we will always be buying technology and we will never have our own technology. Other countries will never ever respect us.

Sir, it is not that we do not have money in this country. We have money. I will give you an example. I was told that the Vice Chancellor of the JNU has recently furnished his room with Rs. 15 lakhs. It is not that the Vice-Chancellor of JNU does not have a very good room. He had a very good room in the campus. In spite of that, he managed to spend Rs. 15

lakhs on that. Couldn't he improve the class rooms, couldn't he improve the facilities for the students and the library facilities? They will not do that when they have power, because these fellows are mediocre. They have achieved those positions, not because of excellence. They have achieved those positions because of the political patronisation. Because of that, they are indulging in this type of activities. That is why, excellence should be encouraged in colleges and in the universities so that people, who are really excellent and meritorious, hold these posts. They will change the entire structure of the university, or. of the college.

Sir, I want to give you one example. The education and poverty has correlation. In Vietnam, poverty incident in households headed by those with no education is 68 per cent. The poverty incident decreases to 54 per cent in houses with primary education and to 41 per cent in houses with secondary education. The same thing is happening in Kerala. Look at Kerala. There is nothing like absolute poverty. There is nothing like somebody is very rich. Everybody has enough to live well and lead a good quality life. If it is possible in Kerala State, in India, why can't we have the same system elsewhere in the country? We don't have a will. We don't want it. In our school system, somebody goes to an air-conditioned school; somebody goes to a school where he has to sit Under a tree and study. We are encouraging this disparity. The rich are becoming richer and the poor are' becoming poorer.. The rich will have better human resources and the poor will have poor human resources. In the days to come, what will happen is, this disparity wiil increase. At least, in our colleges we have got some sort of democratisation where both the rich and the poor come together. I hope they will not think of changing even this system. We can never trust them. We do not know what they want to do. I do not know whether they at all want the poor to live in this country. Why can't the Minister .of Human Resource Development, who is an educationist, change the system? That is his career. He is a professional man. He should be able to do something. But he is not doing it.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब कृपया समाप्त करें।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मैं महिलाओं के बारे में एक शब्द कहकर समाप्त करुंगी। सर, इन के डिपार्टमेंट में महिलाएं भी आती हैं। सर, आई.सी.डी.एस. ब्लाक्स में पैसा बढ़ा है, यह ठीक है, लेकिन सब जगह आई.सी.डी.एस. नहीं है। हमारा अभी वहां जाने का भाग्य नहीं है। सर, इन्होंने हम लोगों का एक बहुत बडा प्रोग्राम आई.सी.डी.एस. के थ्रू और राष्ट्रीय महिला कोष के थ्रू "स्व-सहायता समूह" का टेक-अप किया है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां काफी महिलाओ ने पैसा तो इकट्ठा किया है। They have saved money. That

saving habit is coming in them मगर जिस दिन यहां बजट पेश किया गया, नेक्सट डे फाइनेंस मिनिस्टर ने उन का इंटरेस्ट रेट 4 परसेंट से साढे 3 परसेंट कर दिया। महिलाओं को इन्होंने यह तोहफा दिया। उस के बाद When women go to the bank to take loan to start some economic activity क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं-12 परसेंट, 14 परसेंट और जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो हजार, 5 हजार करोड़ रुपए लेते हैं, आप उन से सिर्फ 6 परसेंट, 7 परसेंट, 8 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? सर, इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं Our women are always a disadvantaged group, आपको पता है, उस के बावजूद भी बड़े लोगों के बड़ा बनने के लिए इंटरेस्ट कम है। The rich may become richer आप उन को और ज्यादा पैसा देते हैं व उन से इंटरेस्ट कम लेते हैं और हम लोगों से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। इसलिए बड़े-बड़े कार्पोरेट सेक्टर्स ने इन से 65 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा लिया है। वहीं हमारे देश में जो एम.पी.एस. है, बैंक्स हैं, फाइनेंसियल इंस्टीट्यूटस हैं, उस के लिए ये क्या करते हैं? कहते हैं, पैसा नहीं है। मिड-डे मील स्कीम के लिए , प्रायमरी एजुकेशन के लिए, आज इतना सारा ब्लैक मनी है। If this black money of Rs. 10,00,000 erores is put into the system, it can generate a revenue of Rs. 4,00,000 erores for the Government. By using this money, they can bridge their deficit. They can pay money for elementary education, for the mid-day meal scheme, etc. They can improve the status of the Tribals, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the backward classes, etc. They can do it. But they must have the will. I would like to know from the hon. Minister: Do they have the will? The problem is, the Minister does not want to look at' us when we speak. He is just reading or writing something.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): I am writing what you are saying.

MISS MABEL REBELLO: Sir, if the Minister can take cognisance of what I have said and do something to improve the situation in this country, to improve the quality of life of women, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, backward class people and other disadvantaged people, I will be very happy. Thank you.

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, within the very limited time available to me, I will attempt.to review the progress that we have achieved in the field of education with reference to the special objectives and goals we have adopted in various education policy statements and resolutions approved by the Parliament. Every country, obviously, uses education as means of imparting knowledge? and skill. There is no country in the world, which believes in education and still forgets the responsibility for imparting knowledge and skill. I will come to that in the course of my discussions on the special objectives which our country has

adopted. The first objective, special objective, which we have borrowed from international organisations, as well, is "education for all". Let us see how far we have succeeded in this great objective. For several generations, education in India had been the monopoly of certain castes and communities. A large majority of the people of the country, not necessarily the poorer sections, but a large majority of the people in our country never had access to knowledge, never had access to education or special skills. But, with Independence, with democracy that we established in the country, we decided to go in for the goal of "Education for AH", and we incorporated in the Constitution, Article 45 which expresses the pious hopes that in ten years' time, we would have succeeded in bringing about a revolutionary change in primary education. This Government has done a great thing by making it a Fundamental Right, but still, I doubt whether we will be able to achieve this goal, taking into account the present state of primary education in our country. It is a very sad fact to know that 22 per cent of all the children out of the school in the world today are Indians. Our country contributes 22 per cent of all the children in the world outside the primary school system. There are various social reasons for it, various special reasons relating to castes and communities; there are special reasons relating to the location of villages and hamlets at far distant a place than the seat of educational facilities. Whatever may be the reason, the most important reason why we have failed in making primary education, in my opinion, is the poor manning of the schools. There are schools supposed to be imparting primary education without teachers, without buildings, without drinking water, without toilets, without playgrounds, without books, and, therefore, the schools are not able to retain the children's interest in the school. I do not know how far making it compulsory is going to help. A sort of a revolutionary approach has to be adopted in order to realise the objective of "Education for AH", at least, up to the primary stage. We have to remember that the vast disparity exists in this respect between urban areas and rural areas, between Scheduled Castes, Scheduled Tribes, on the one side, and the rest of the communities on the other, between women, as a part of the population, and men as remaining part of the population. Therefore, we have to focus on these weak spots which have already been identified and have various special attentions with enormous funds to ensure that this great dream can be realised in our country. Again, speaking on the subject of access to education, we should not be satisfied with the statistical progress that we have seen in secondary education or in higher education in particular. The number of colleges has increased over the last

fifty years from 700 to 10,000 and the number of teachers from 15,000 to 3.2 lakhs today. Actually, we have more college teachers or university teachers today than we had students at the time of Independence. The number of students has gone up from about 7 lakhs to 68 lakhs, but I am not at all happy at the fact that we take refuge under the statistics or behind the statistics and say we have progressed a great deal. If we look into these colleges and universities and see the standard and quality of education that is being provided in these places, we would feel that many of them should have never been established at all. They are in the name of colleges and, sometimes, they are in the name of universities, -- I am speaking even of universities -- but the fact remains that they produce graduates who are unemployed because they are unemployable. They have no strength. They have not derived the strength necessary even to enter the job market, leave alone other tasks that are expected of them. In spite of all the statistics that we boast about, we should remember that even after establishing all these new colleges and universities, only six per cent of the population in the age group of 17-24 has access to higher education today. We compare ourselves very poorly even with other developing countries, much poorer countries, where the average is about 10 per cer.i. In the United States, 50 per cent have access to higher education. If we take Europe as a whole, 20-22 per cent have access to higher education. In our country, even six per cent does not have access to higher education. And those who have access are finding themselves in schools, colleges and universities, which do not deserve the name.

The third point that I would like to mention is that we have failed, in my judgement, to promote the ideals enshrined in the Constitution. The Education Policy statement says that education should further the gcals of socialism, secularism and democracy which means equality and liberty. Let us dc soul-searching and find out whether we have really used education to promote socialism, secular ^m and democracy in our country seriously. I say this with great sadness because by perpetuating the differences and disparities in quality and standards, education is contributing to inequality. When we have schools, when we have educational institutions, when we have colleges and universities -vhich can be categorised as third grade on the one side, and a few islands or pockets of excellence which can be categorised as really excellent on the other side, we really perpetuate inequality in the society. < The son of the butler becomes a butler. The son of a butcher becomes a butcher. The son of a carpenter becomes a carpenter. A peon's son becomes a peon. A doctor's son becomes a

doctor. An engineer's son becomes an engineer. An IAS officer's son becomes an IAS officer. And. you find the disparity being perpetuated and widened. And that is why ' say that far from removing inequality, far frcm achieving the objective enshrined in the Constitution of real democracy, our educational system is contributing to the negation of equality and distortion of democracy. I would, therefore, ask whether the Education Ministry has a real programme which will try to help some of these third grade or fourth grade institutions to improve, at least, to the levels where they can be called colleges or universities.

I want to then ask: - this is my fourth point -- Have we succeeded in another great objective mentioned in the Education Policy statement that education should be "...a culturing process"? The Policy statement says that it should refine sensibilities; it should refine perceptions contributing to national cohesion, scientific temper, and independence of mind. Let us again do soul-searching. Who are the people today, who are spreading communal tension in the country, social tension between castes? Who are the people who are going ^back to obscurantism, superstition, and who behave as if they still live in* the early centuries of our country's history? They are not the uneducated, illiterate people, but most of them are the products of our universities and colleges. If we look today at the objective that we have mentioned in the policy statement of refining sensitivities and perceptions for introducing scientific temper, and are not able to apply that standard to what we see around us, I will blame the education system for that, because in our schools, in our universities, in our colleges we have not been teaching these elementary lessons of democracy. And we have been encouraging these institutions to indulge in various practices by which they distort the value system of our country. We speak of the scientific temper. Where is the scientific temper about which we boasted at one stage of our civilisation? Long, long before other countries could ever boast to be civilised, our great ancestors had applied a scientific temper. They did researches, they mapped the skies of the world, they went into the question: Why is there existence? What is Aatman? What is Parmaatman? What happens to life after death? And they found the answers, and they have been put in the Upanishads and in the Vedas. And. that is why, we claim ourselves to be a great civilisation in the world. We have had scientific temper five thousand years ago. But, todcy, we forget that heritage and we cling on to ritualism, obscurantism, superstition and narrow-mindedness, and say that is civilisation, and that is going back to our ancient glory and ancient richness. A distortion has been made of

what is real Indian heritage. Have we succeeded in using education in the right way? I am afraid, we have not.

Sir, now, I come to a favourite topic, which Dr. Murli Manohar Joshi knows because he has been the recipient of some letters from me. I tned to raise the question of UGC through a proper question in Parliament. My friend, Dr. T. Subbarami Reddy is successful in having his questions always finding place in the list of questions to be answered. Unfortunately, I thought when I put the question, it would somewhere find a place some time and raised this question of the UGC and found, I could not get an opportunity to raise that point in Parliament. I wrote to the hon. Minister and he was kind enough to send me a long reply, which has not satisfied me. I do not want the present UGC Act to continue as it is. I wanted it to be changed. I wanted a new UGC Act to be brought in. I just mentioned to him one case, which worried me. The State Maharashtra from which I was selected to this House, has 17 universities, 1800 colleges and 12 lakh students, the largest enrolment in the whole of India, and its share of UGC, both plan and non-plan in 2001-2002 was Rs.53.98 crores, whereas the 17 Central Universities and their affiliated colleges got Rs.970.63 crores. If we look at the universities in the States and merely say, these are State Universities, the State should fund them, I give a warning to the hon. Minister who is a distinguished educationist himself, we would lose one whole generation without the benefit of real education. We may rectify the mistake later,. he may fund a university much more than what he is able to do today after some years, but we would have missed real, genuine and good education to a whole generation. A building can be built later, but what is lost in education cannot be repaired for that particular person in his life time. That is why, I have been pleading with the Minister that a new Act should come, replacing the existing UGC Act. A mention was made by the previous speaker about this great, influential position in the Government today. I realise it much better than many other people. I am very happy that, at least, at the Central level, we have a Minister who is himself an educationist, and who has an adequate political standing in his own party. If he fails to get that "6 per cent share of the GDP, I do not think his successors are going to succeed in that. You should have the muscle, the strength and the will to fight with the rest of your colleagues in the Cabinet and get your share for education, and then you will not be writing me back that you cannot help because the Central fund should go only to the Central universities. Why should you, Dr. Murli Manohar Joshi, so eminent an educationist, so tall a figure in your own party, not influence your colleagues

and get the legitimate share for education, which is really an effective nation-building tool in your hands, and get, at least, 5 per cent? It is now below 4 per cent. Then, you will be able to give to the UGC the funds that I now have been crying for *(Time-bell}* and then, I will be able to get some share of it for the State universities and colleges which are really now being starved of funds. Therefore, please do not tell me again in your reply that under the present Act this is all you can give. I want you, such an influential leader, to use your influence to change the Act, bring in a new Act, while you are still the Minister, get your share, which is your due and, then, see to it that the UGC functions properly, in fairness to all the institutions of education in the country.

I have one last point. Sir, before you ring the bell for me. The one thing I detest the most is .the bell, which I am not used to. Maybe, that is the reason. But before you do that, I will conclude, with one more point. Mr. Minister, you should use your influence also to ensure that the Ministers at the State level are also influential people, politically tall and educationally advanced. What is happening in many States today is that they split up the Education Ministry and accommodate everybody who has to be accommodated. There is a Minister for Primary Education, a separate one for Secondary Education, a third-one for Higher Education, a fourth one for Technical Education, and I am not exaggerating...

ONE HON. MEMBER: A 5^{h} one for Medical Education.

DR. P. C. ALEXANDER: Yes, for Medical Education. In many States, there will be four or five Ministers of Education. Education Ministry is an integrated one. I am glad, in the Central Government, at least, there is only one Minister for Education. It is an integrated one.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: But Medical Education and Agricultural Education are still out of it.

DR. P. C. ALEXANDER: But you should be able to get them back, if you have the strength. What T say, Sir, .is this. If we do not have good primary schools, we cannot have good secondary schools. If we do not have good secondary schools, we cannot have good colleges. If we do not have "good colleges, we cannot have good universities. Therefore, you have to treat education as one, and ensure that this cutting and chopping of Education Departments, Ministries, or, the subject, is not allowed at the State level, in order to merely accommodate the aspirants of chairs in the ministerial tow.

I am concluding with an earnest plea; we will have a revolutionary approach for education in our country under the leadership of a great educationist. Sometimes, I feel great sadness to think what is happening to that great University of .Allahabad, which in my student days used to be looked upon as the number one or the number two university -- I used to have the pleasure of inviting Amar Nath Jha to inaugurate the University 4rlnion of the Travancore University, of which I was then the elected President, and it was a great dream for us to see, in person, Amar Nath Jha; we had heard so much about his contribution. Do you know what is happening to your old university today? Nobody speaks of Allahabad as the centre of excellence today. Lack of funds is the reason, not lack of brains. Of course, when there is a lack of funds, education gets watered down and then brains come down. Why should you not take example from your own university and see to it that the message of education is properly spread through proper muscles and strength of arms? With this great appeal, earnest appeal, as one who had been the Chancellor of 17-18 universities in Maharashtra, the Chancellor of 14 universities in Tamil Nadu -- and not a sleeping Chancellor, I would like to assure you; a very active, and proactive Chancellor - I would say that great things are expected of you. If you fail, *I* wonder whether education will ever be saved. Thank you.

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I was in a great impatient mood and I was not able to alert myself to your call. Excuse me. Even then I would like to confine myself only to the primary education aspect, in view of the limited time you have allotted to me. Even after 52 years of our planned development, the goal of "Primary Education for AH" continues to be a matter of serious concern in our country. Out of the estimated population of 193 million, in the age group of 6-14 years, in 2000-01, nearly 81 per cent attended the school. The student retention rate at the primary school stage.was about 58 per cent. There has not been any decrease in the drop-out rate over the years. In fact, the drop-out rate at the primary level has increased from 40.3 per cent in 1999-2000 to 40.7 per cent in 2000-01. Even now, we do not have sufficient number of schools, especially in rural areas. The facilities in the existing schools are very poor. As per the Sixth All India Educational Survey, conducted by the NCERT in 1993, about 10.5 per cent primary schools in the country were without any class room and another 24.5 per cent schools were having only one room for instructional purposes. Only 44 per cent of schools had drinking water facilities, 18.9 per cent schools had common toilet and only 8.7 per cent primary schools had separate toilet for girls. The

Operation Black Board Scheme was launched after the adoption of National Education Policy in 1986, aiming at improving the infrastructure facilities in the primary schools. It is a fact that some improvements have been made between 1987-88 and 2001-02. But this "Scheme has been abandoned since 2002-03, the first year of the Tenth Plan.

We often harp on the key role of education in the development of the country, but fail to provide adequate funds to the sector. The goal of providing, at least, 6 per cent of GDP to the education sector in the Budget has never been fulfilled. On an average, the tc'al expenditure on education has been below four per cent of GDP all these years.

The Government has enacted the 93rd Constitution Amendment Act with great fanfare making free and compulsory primary education to all children between the age-group of 6 and 14 years as a Fundamental Right. But it has not yet been implemented. The *Sarva Shiksha Abhiyan* Scheme (SSA) was launched with a view to meet the constitutional obligation of universal elementary education. The estimated financial requirement for the SSA in the first 10 years is Rs.98,000 crore, i.e., Rs. 9800 crore per year. The Centre and State Governments are to share this amount in the ratio 75:25 Accordingly, the Centre has to provide Rs. 7,350 crore per year for the implementation of the Scheme. But the Budget allocation for SSA during the year 2003-04 is only Rs. 1951 crore. From where is the rest of the required amount expected to come? The total budgetary allocation this year for the Department- of Elementary Education and Literacy is only Rs. 4900 crore, the same amount was allocated in 2002-03.

Poverty being a major factor for the increase in the rate of dropouts in primary classes, providing mid-day meals under the Nutritional Support to Primary Education Programme has helped to a great extent in attracting more children to schools and maintaining the student retention rate. This programme has to be strengthened and extended to more schools. But there has been only a marginal increase in the allocation for the Scheme during the current year - Rs.1175 crore, compared to Rs.1057 crore in 2002-03. Moreover, the implementation of the Scheme has not been satisfactory in many States.

Sir. it is clear from these facts that the primary education system has been grossly neglected in the Budget. Lakhs of poor children in the country cannot hope to get quality and standard education in the- near future with such a meagre public investment in the elementary education sector. At the same time, the Government is encouraging more and more

unaided public schools and colleges, thereby commercialising the education sector. Even the Government universities and colleges are. planning to increase the fees steeply in conformity with the recommendation of the Expenditure Development Committee of the Finance Ministry, making the higher education inaccessible to otherwise eligible students coming from poor families in the country.

So, it is high time that our National Education Policy was recast to ensure reasonably good elementary education to all and standard higher education at affordable cost to the eligible students from poorer sections. To fulfil this objective, the Plan allocation to education sector should be raised to a minimum level of 6 per cent of GDP and commercialisation of education sector should be slopped.

Sir, I would like to conclude by reminding the Government and the hon. Minister of Education of what Prof. Amartya Sen, the Nobel Pn'ze winner said, "Primary'Education Sector is neglected in India. More attention to primary education is a must, if our country has to advance."-Thank you, Sir.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, I do not think there is very much more to be said on the educational system in the country. All speakers have drawn attention to the various shortcomings that afflict our educational system.. In all fairness to the Government, I must say that educational system in our country is under intolerable strain, (not because of lack of efforts, --people are doing their best,-- but becausfe of the tremendous increase in population which is something the educational system can do really nothing about. But notwithstanding like our economic policy, our education policy is also more and more relying on private individuals, private resources, private funding and private organisations. But, unfortunately, these sources of funding do not reach out to those areas where the bulk of our student population, potential student population is, that is, rural areas. You will find very high quality schools, very high quality colleges and even some good universities, very selective, but very good; they are all in urban centres. So, unless the Government steps in a big way, continues its efforts to assess the establishment of primary, secondary as well as higher education, a country as populous, as under-developed and as complex as India, the education policy will make no headway. We keep talking about the USA. The schooling system of the USA is based upon funding by the local municipalities from taxes paid by the residents of a particular-area for establishing schools in their districts. They are called

school districts. The quality of education in the 'affluent school districts' of the USA, where affluent parents stay, is extremely high. No doubt about it. But, similarly, when you go tc the rural USA where the 'other sections of the society', particularly, the African-American population live -- or, what we call in India as 'economically backward sections' -- there, their schools are as bad as any worst school in our country. So, I am afraid, the Government must take a major share in spreading education in our country. Resources are scarce. But, notwithstanding that, I would support all my colleagues, who have spoken before me, that the minimum the Government must spend on education -- primary, secondary as well as higher - should not be less than 6 per cent of the GDP. One of the problems, r think, of our education is, it is in the Concurrent List. I do agree that the States must have a larger say in what is being taught. But, I think, we have taken it to another extent. We always compliment the genius of our founding-fathers in having given us the Gonstituticn that we have. But, I do think that with a country as complex, as complicated and as multi-cultured as India, we cannot live with education to vary from State to State. What I am saying is: India needs a system of education which caters for one, or, at the most, two school boards. We, now, find that there is a Central Board, ICSC and each State has its own Boards. Eminent educationists say that allowance must be made for local variations in the various systems of education. ! think, now, this is a fallacy. In an over-populated and in a complex country like ours, we need, at least, at school level, a standardised system of education. The only variation that can be done, at the local level, is in the teaching of languages. Other than that, I think, the system of education we are following is leading to -unnecessary complications and also unnecessary dilution of education throughout the country.

The other issue, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw your attention to, is teaching of English. English is no longer a fore-gn language. It is very much an Indian language. That apart, English is also an international language. And, I am afraid, if we are to maintain the standards of international excellence, if we are to compete with the international community, we have to improve in teaching English. Sir, just yes*erday, the hon. Minister of Communications and Information Technology was saying that in this information age, English is the common language. Whei he was discussing the position of India *vis-a-vis* certain competing countries like China, he mentioned that the advantage that India has got over China in the field of Information Technology is our knowledge on English. And he also

mentioned that China has imported 20,000 teachers just to teach English in their country. So, I think, while the language controversy will go on in this country because of the historical background that associates with English, we should pay much more attention in India to the teaching of English.

Sir, at the end, I would like to speak on a sensitive subject which, I think, is causing an already complicated education system even more complex and sensitive and that is the new terms which have come up. The first one is 'saffronisation' of education -- Bhaghavakaran - and the other one is 'Madrasas' system. Off and on, not only in the field of education but also in maYiy other contexts, these terms have come up. Firstly, I must express my disapproval of the term 'saffronisation.' Saffron is a colour of our National Flag. Saffron is a coloui with which a large section of Indian I society associates itself with certain spiritual value. उसको इस तरीके से उछालना, मेरे ख्याल से यह गलत है। Yes, that notwithstanding, that does not hide the fact that there are attempts, as Dr. Alexander has mentioned just now, to associate certain ritualistic aspects of our culture, with what our actual traditional culture is. I think, this is where, without using the word 'saffronisation', we have to come to some understanding. s»rft ^t <pr Ft*r 3rprr grfexj- % Indian cultuttre, Indian history must not be attempted to be cast in a particular mould, which the multifarious, complex, society of ours has to accept in its full whole. And, that is a mistake being committed by our political parties. I do hope there is some kind of awakening in our system. And, that this -- what we call saffronisation, but I do not approve that term - must stop.

Let me come to the other aspect, that is, the *madarsa* education. The *madarsa* education has beer, commented upon adversely in many contexts, under many different connotations. In the context of *Madarsa* education -- and, I am very happy.that Dr. Kidwai is here -- particularly, when we are discussing other issues regarding the country, it is said that *madarsa* education poses a threat to the security of the country, in the aspect that some kind of anti-national training, some kind of anti-national feelings are being developed and taught there. I think, in this particular context, we must be very clear that with, perhaps, the very, very odd exception, generally, *madarsas* are not indulging in these things. But, at the same time, a question aiso arises: Are *madarsas* a part of the educational mainstream of the country? There also the answer is 'No'. It is 'No' because of one main reason that this system of education comprises almost exclusively, almost exclusively *of...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**): कृपया समाप्त करें।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: This system of education comprises almost exclusively of religion-based education. And, no system of education which is totally based on religious education can ever be a part of the national mainstream of a complex society. So, how do we improve this? And, I think, the author of such a scheme is sitting right here -- Dr. Kidwai. This is an experiment which is being undertaken in the Government of West Bengal. The ultimate product of St. Xavier's school, a Christian missionary institution where I studied, or, Ramakrishna Mission Schools, is a higher secondary student, who has possibly passed his C.B.S.E. I think, the only, way to" reform and bring this *madarsa* system, the maligned *madarsa* system into the national mainstream is to retain the title of a *madarsa,* for example, Calcutta *madarsa* was founded in 1837, which, I think, is the oldest one in the country. Why the *madarsas* cannot award, at the end of their educational training, a normal higher secondary or C.B.S.E. degree like all the other schools? This experiment is being tried in West [1] Bengal. It had been' recommended by Dr. Kidwai. But, the ultimate solution to this particular problem does not lie with the people like us, does not lie with the Government also; it must come from within the community. I was informed - when I discussed about West Bengal with Dr. Kidwai, who had made this recommendation - even in West Bengal, while this thing is progressing, they have not been able to go to the full distance to say, "All right, *madarsa* is just any other school like St. Xavier's or Ramakrishna Mission School; it gives a higher secondary degree, with certain additions to its syllabus" In this case, certain additions could be Arabic history, Islamic history. But the end-result must be a standard educational degree. With that, Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अभी यहां पार्लियामेंट के परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और महा-महिम राष्ट्रपति जी उस में भाग लेने वाले हैं। अतः अब हम लोग उठेंग़े, लेकिन उस से पहले मैं यह सूचित कर दूँ कि यह चर्चा अभी अधूरी रही है। यह कल जारी रहेगी और माननीय मंत्री जी कल ही कल ही उत्तर देंगे, लेकिन अब चर्चा में केवल वही माननीय सदस्य भाग ले पाएंगे जिन के नाम आज की लिस्ट में हैं और वे बोल नहीं पाए हैं। उन मे हैं-श्री अवनि राय, श्री दत्ता मेघे और श्रीमती प्रेमा करियप्पा।

अब हम कल मंगलवार दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न तक के लिए उठते हैं।

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, trie 29th April, 2003.